R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 17
01 से 15 जून 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

विधानसभा चुनाव 2023

मप्र में हाईवोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू

तेरा काम... मेरा काम...

जनता किसको देगी ईनाम?

कुलीनों के कुनबे में दिग्गज नेताओं में छिड़ी वर्चस्व की जंग

कांग्रेस के कुनबे में भी भावी मुख्यमंत्री को लेकर बढ़ी रार

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

अपरा

9 | इंदौर बना 'ड्रग्स का अड्डा'

मिनी मुंबई के नाम से पहचान बनाने वाले इंदौर शहर में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है। इसका प्रमाण है ऐसा कोई थाना नहीं है, जहां साल में 50 से अधिक ड्रग्स के केस दर्ज न हुए हों। पिछले साल शहर में नशा...

राजपथ

10-11 | मप्र में चुनावी 'घोषणाकाल'

मप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में उतर चुके हैं, जहां भाजपा अपनी विभिन्न योजनाओं से जनता को रूबरू कराकर फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस...

लालफीताशाही

15 | कई नौकरशाह खा रहे जेल की हवा

देश में प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई, तो कोई अन्य की जांच में दोषी पाया गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार...

भर्राशाही

18 | अनाथों को नहीं मिला 'वात्सल्य'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी, लेकिन मप्र में अफसरों की भर्राशाही और लापरवाही के कारण अनाथ बच्चों को वात्सलय नहीं मिल पाया। यानी प्रदेश में यह योजना एक साल बाद भी लागू नहीं हो पाई है। इस योजना...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

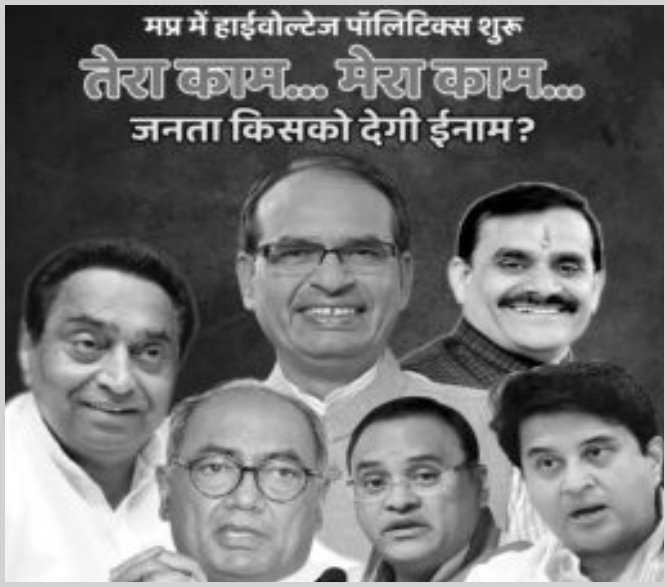

चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस में बगावत, भितरघात, वर्चस्व की जंग, क्षेत्रवाद और जातिवाद के कारण मप्र में हाईवोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रदेश में 200 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही भाजपा कई गुटों में बंट गई है। कांग्रेस के दावे के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा में बंट गई है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों में वर्चस्व की जंग इस कदर छिड़ गई है कि मंत्री एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं।

16-17

34

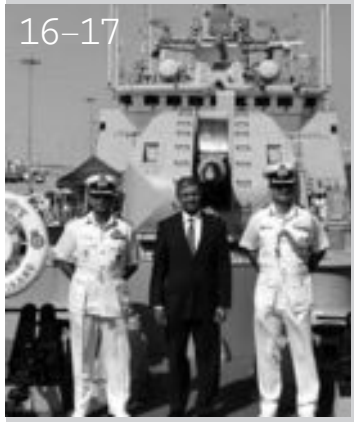

44

45

राजनीति

30-31 | कम हो रहा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव?

कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद से क्षेत्रीय दलों के सुर बदल गए हैं। बात-बात में कांग्रेस को कोसने और राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता न मानने की बात करने वाले अब चुप हैं। राहुल गांधी का मुखर विरोध करने वाले विपक्षी दल अब राहुल गांधी में नेतृत्व देख रहे हैं।

महाराष्ट्र

35 | तलवार की धार पर अजीत पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के इस्तीफे से उठा बवंडर अब लगभग शांत हो गया है। पवार के इस्तीफे से पार्टी में अनिश्चितता का जो माहौल बना था वो लगभग थम गया है। लेकिन यह तूफान आने के पहले वाली शांति है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं...

बिहार

38 | बिहार में हिंदुत्व की हुंकार?

बागेश्वरधाम वाले धीरेंद्र शास्त्री और विवाद एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन, बयान, टिप्पणी और चमत्कार को लेकर मुख्य धारा के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान न मचे।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

सोशल मीडिया और यूट्यूब पर चलेगी राजनीतिक चाल

झूठ के पांव नहीं होते, ये पुराना मुहावरा है... लेकिन अब सोशल मीडिया ने इस मुहावरे को गलत साबित कर दिया है। सोशल मीडिया ने यह बता दिया है कि झूठ के पांव भले ही नहीं होते, लेकिन उसके पंख जरूर होते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने भी पंपलेट, वाहनों से प्रचार, जनसंपर्क, डोर-टू-डोर कैंपेन के बजाय चुनाव में सोशल मीडिया और यूट्यूब से प्रचार करने की तैयारी पूरी कर ली है। यानी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर राजनीति की साम, दाम, दंड, भेद वाली चाल चली जाएगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया झूठ परोसने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन गया है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ ही यूट्यूब पर प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाई है। पार्टियों और नेताओं के सोशल मीडिया प्रेम पर मोहम्मद अली साहिल का यह शेर सटीक बैठता है...

ये उसका काम है फिरका-परस्ती छोड़ दे कैसे
सियासत कुछ भी कर ले उसकी मक्कारी नहीं जाती

यानी आगामी चुनाव में सियासतदान सोशल मीडिया पर वह सबकुछ परोसेंगे जो वे पंपलेट, वाहनों से प्रचार, जनसंपर्क, डोर-टू-डोर कैंपेन में नहीं कह सकते। शायद यही वजह है कि पार्टियों की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्याशी और नेता भी सोशल मीडिया का ज्यादा सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया की इस दुनिया में सबसे ज्यादा मारामारी फॉलोवर्स बढ़ाने की ही है। वर्चुअल वर्ल्ड में फॉलोवर्स की संख्या से ही अब लोकप्रियता तय होती है। हमारे नेता भी इस ट्रेंड से अछूते नहीं है। उन्हें भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स का मतलब क्या है। यही वजह है कि उनमें भी फेसबुक से लेकर ट्विटर तक अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ है। ताकि डिजिटल दुनिया के इस दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो अपने रुख, राय और बातों को पहुंचा सकें। यानी चुनावी राजनीति में भी सोशल मीडिया की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। मतदाताओं को लामबंद करने के लिए सोशल मीडिया अचूक राजनीतिक हथियार साबित हो रहा है। जो राजनीतिक ध्रुवीकरण और सियासी एजेंडा सेट करने में बड़ी भूमिका भी निभाने लगा है। मप्र चुनाव में भी सोशल मीडिया के दखल से इनकार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर राज्य के हर बड़े राजनीतिक चेहरे के फॉलोवर्स लाखों की संख्या में हैं। ऐसा लग रहा है मानो 2023 विधानसभा चुनाव सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाएगा। दरअसल, आज सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां भी अब सोशल मीडिया की ताकत को पहचान गई हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमकर अपना प्रचार कर रही है। 2023 चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर घेरने की रणनीति बना रही है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने नेताओं को बकायदा ट्रेनिंग देकर सोशल मीडिया पर सक्रिय होने का निर्देश दिया है। वहीं दोनों पार्टियां के आईटी सेल भी सक्रिय हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से नेताओं के अधिकतर बयान और जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से ही सामने आ रहे हैं। चुनावी साल में इनकी बाढ़ आ गई है। वहीं जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, पार्टियां सोशल मीडिया और यूट्यूब पर प्रचार-प्रसार करने के लिए कंपनियों को हायर कर रही हैं। यह सब देखकर साफ लगता है कि अगला चुनाव पूरी तरह सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लड़ा जाएगा और पार्टियां आसानी से अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने में सफल होगी।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 17, पृष्ठ-48, 1 से 15 जून, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

चुनावी तैयारी

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। चुनाव से पहले भाजपा जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। उधर, कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तरह-तरह के आयोजन कर रही है।

● **सीमा सेन, भोपाल** (म.प्र.)

मेट्रो का इंतजार

स्वच्छता में कई सालों से नंबर वन आने वाला हमारा शहर इंदौर नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। इंदौर मेट्रो का कार्य तेज गति से हो रहा है, इंदौर मेट्रो का कार्य पूरा होने के बाद मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। शहर के रहवासी मेट्रो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

● **शफीक कुरैशी,** इंदौर (म.प्र.)

मप्र में प्राकृतिक खेती

जैविक खेती में अव्वल होने के साथ अब प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना है। मप्र फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। सरकार भी इस ओर अधिक ध्यान दे रही है।

● **याचिका नागर,** राजगढ़ (म.प्र.)

धर्म की आड़ में राजनीति न हो

भारतीय राजनीति के निर्धारण में धर्म ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रयोग विभिन्न जातियों में कटुता की भावना पैदा करने के लिए भी किया गया है। दूसरी ओर धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी किया गया है। आम लोगों के सामने जहां पहले से ही रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई ने समस्याएं खड़ी कर रखी थीं वहीं कोरोना महामारी ने तो आम लोगों को बे मौत मार दिया है। लोग दो वक्त की रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस बीच समाज में कुछ कट्टरपंथियों द्वारा घोले जा रहे जहर ने पहले से ही मौत के मुंहाने पर पहुंच चुके लोगों के लिए एक और मौत का कुंआ खोद दिया है।

● **अविनाश गुप्ता,** रीवा (म.प्र.)

कड़ी कार्यवाही हो

एमपी बोर्ड के पेपर आउट करने वालों पर अब सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में चला गया है। विद्यार्थियों ने दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की थी और पेपर आउट करने वालों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार को इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सजा के डर से भी लीक करने के पहले कई बार सोचना पड़ेगा, उनमें खौफ पैदा होगा।

● **महेंद्र सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

सड़क हादसों पर लगाम कब

प्रदेश में बस हादसे आम होते जा रहे हैं। हर सड़क हादसे के बाद व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और जैसे-जैसे घटना पुरानी होती जाती है, सवाल भी कमजोर पड़ते जाते हैं। नतीजा, हर कुछ दिनों में एक्सीडेंट की खबर आती रहती है। सरकार को सड़क हादसों को लेकर कड़े नियम बनाने चाहिए, जिससे लोगों की जान को खतरा न हो। खासकर बस के ड्राइवरों और बस मालिकों के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे आने वाले समय में हादसों पर लगाम लगाई जा सके।

● **प्रवेश कुशवाहा,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

त्रिपुरा में साहा और बिप्लब में कुर्सी को लेकर 'अपच'

त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटें जीतकर इस साल मार्च में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। लेकिन, बिप्लब कुमार देव माणिक साहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पचा नहीं पा रहे हैं। 2018 में जब भाजपा ने इस सूबे में पहली बार सरकार बनाई थी तो सफलता का सेहरा बिप्लब कुमार देव के सिर बंधा था। चुनाव के वक्त वे भाजपा के सूबेदार भी थे। लेकिन, 2018 में आलाकमान ने उन्हें हटाकर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया। साहा मूल भाजपाई नहीं हैं। कांग्रेस छोड़कर वे 2016 में भाजपा में आए थे। भाजपा ने 2022 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। फिर 2018 में मुख्यमंत्री बनाया तो उनकी राज्यसभा सीट बिप्लब कुमार देव को दे दी। देव साहा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभी तक भी पचा नहीं पाए। त्रिपुरा में भाजपा दो खेमों में बंटी है। एक खेमा संघी पृष्ठभूमि वाले और मूल भाजपाइयों का है तो दूसरा साहा की तरह माकपा और कांग्रेस से आए नेताओं का। मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी के कई नेता बगावत पर उतारू हैं। तभी तो बिप्लब कुमार देव पिछले हफ्ते अचानक दिल्ली आकर आलाकमान से मिले। मिलकर शिकायत की कि साहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर पूर्व के प्रभारी संबित पात्रा को यह झगड़ा निपटाने का जिम्मा दिया गया है।

क्या होगी कांग्रेस की कहानी ?

अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने की नीतीश कुमार की रणनीति अभी परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के मुद्दे पर गैर भाजपा विपक्ष फिर विखंडित नजर आया। भाजपा का विरोध करने वाले अकाली दल, तेलगुदेशम, जनता दल (सेकु) और बसपा जैसे दल विपक्ष का साथ छोड़ गए। वाइएसआर कांग्रेस और बीजू (जद) तो खैर भाजपा विरोधी किसी भी मोर्चे में शामिल न होने की बात खुलेआम कर ही रहे थे। सबसे बड़ी अड़चन क्षेत्रीय दलों का अपने राज्यों में कांग्रेस को भाव नहीं देने का रवैया है। कांग्रेस में भी कुछ अंतरविरोध है ही कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर जैसे नेताओं से हाथ मिलाना विधानसभा चुनाव में नुकसान करेगा या नहीं। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस भी अब एकता के लिए ज्यादा उतावली नहीं लगती। देश की सियासी तस्वीर इस साल होने वाले मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगी। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो फिर क्षेत्रीय दलों को उसकी छतरी के नीचे आना पड़ेगा। उल्टा हुआ तो हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हल्ला बोल करेगा।

सुख में सुक्खू

विपक्षी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने छह महीने हो गए पर मंत्रिमंडल का विस्तार लटका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा पांच और मंत्री हैं सरकार में। सुक्खू ने छह विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव भी बनाया था। पर, एक एनजीओ ने इस मुद्दे पर हिमाचल हाईकोर्ट में दस्तक दे दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि संविधान में मुख्य संसदीय सचिव का कोई पद है ही नहीं। अलबत्ता विधायकों की कुल संख्या के अधिकतम 15 फीसदी मंत्री पदों की वैधानिक सीमा जरूर है। मुख्यमंत्री ने इसी सीमा की अनदेखी करने के लिए बना दिए मुख्य संसदीय सचिव। जिन पर हर साल सरकारी खजाने का 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। सूबे की 68 सदस्यीय विधानसभा को देखते हुए मंत्रिपरिषद अधिकतम 10 की हो सकती है। इस नाते सुक्खू अभी तीन मंत्री और बना सकते हैं। पर, मुख्य संसदीय सचिवों का भाग्य ही अधर में लटकने से न तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा है और न ही दूसरे मलाईदार पदों पर चहेतों की नियुक्तियां। इसके पीछे एक वजह पार्टी की गुटबाजी भी है।

तकरार के बाद सुधार की दरकार

लगता है कि केंद्र की राजग सरकार ने न्यायपालिका के साथ टकराव की अपनी नीति में बदलाव किया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाने से इस बदलाव का पहला संकेत मिला था। दूसरा संकेत, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खाली हुए दो जजों के पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने कुछ दिन पहले ही इन नामों की केंद्र से सिफारिश की थी। अतीत में इतनी तेजी से केंद्र सरकार ने कालेजियम की किसी भी सिफारिश को कभी मंजूरी नहीं दी। रिजिजू के कानून मंत्री रहते न्यायपालिका और कार्यपालिका के रिश्तों में तल्खी तो बढ़ी ही, सुप्रीम कोर्ट को कई बार मर्यादित शब्दों में फटकार भी लगानी पड़ी। रिजिजू जो भी बयानबाजी कर रहे थे, उसके पीछे उनके नेतृत्व का समर्थन न रहा हो, आसानी से यह बात गले नहीं उतरती। पर, हिमाचल के बाद कर्नाटक भी भाजपा के हाथ से निकलने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के प्रबंधकों को रिजिजू का विभाग बदलकर रिश्तों की तल्खी में कमी लाना जरूरी लगा होगा।

झटके जरा हटके

विपक्षी एकता के लिए जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हफ्ते दो झटके लगे। पहला ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया। दूसरा दो दशक तक उनके खास रहे आरसीपी सिंह ने भाजपा में विधिवत शामिल होकर दिया। आरसीपी सिंह ने जनता दल (एकी) से इस्तीफा तो पहले ही दे दिया था और बाहर रहकर भी अनौपचारिक रूप से भाजपा के ही प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे थे। तभी नीतीश इस पर हैरान नहीं हुए। उलटे वे तो यही उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा आरसीपी सिंह को राज्यसभा में अवसर देकर केंद्र में मंत्री बनाए रखेगी। आरसीपी सिंह नीतीश के नालंदा जिले के तो हैं ही, उन्हीं की तरह कुर्मी बिरादरी के भी हैं। वे उप्र काडर के आईएएस थे और नीतीश के संपर्क में उनके रेल मंत्री रहने के दौरान आए थे। एक दशक तक तो नीतीश के नाक-कान सब कुछ वही थे। तभी तो पार्टी के अध्यक्ष भी बने और केंद्र में मंत्री भी।

कैरेक्टर तो नहीं, कैडर बदला

प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में इन दिनों एक आईएएस अधिकारी अपनी संभावित तीसरी शादी के लिए चर्चा में हैं। वर्तमान में साहब महाकौशल क्षेत्र के एक जिले के कलेक्टर हैं। साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका कैरेक्टर भले ही नहीं बदला है, लेकिन उन्होंने शादी करके किसी का कैडर जरूर बदलवा दिया है। गौरतलब है कि 2014 बैच के इस आईएएस अधिकारी ने अपनी ही बैच की एक महिला आईएएस अधिकारी से शादी की थी। जिस महिला अधिकारी से साहब ने शादी की थी, उन्हें पहले छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ था। साहब से शादी के बाद नियमानुसार मैडम को भी मप्र कैडर मिल गया। लेकिन दोनों की शादी अधिक दिन तक नहीं चल सकी और इनका तलाक हो गया। उसके बाद साहब ने आंध्र प्रदेश कैडर की एक महिला अधिकारी से दूसरी शादी की। उक्त महिला आईएएस को भी साहब से शादी होने के बाद मप्र कैडर मिल गया। सूत्रों का कहना है कि साहब का इनसे भी मामला जम नहीं पा रहा है। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच साहब का दिल एक अन्य महिला अधिकारी के साथ लग गया है। बताया जाता है कि एक बड़े राजनेता के बेटे के साथ मैडम की शादी होने वाली थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में अब साहब अपने कैडर की महिला अधिकारी के साथ तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं।

कैमरे भी निकाल ले गए साहब

देश में ब्यूरोक्रेट्स को सबसे सुशिक्षित, सभ्य और संवेदनशील माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ अफसर ऐसा कर जाते हैं, जिससे लोग इन्हें हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे अफसरों की संख्या भले ही कम है, लेकिन इनकी करतूतें कई बार हदें पार कर जाती हैं। ऐसे ही एक साहब जो आईपीएस हैं, इन दिनों प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। साहब भले ही मप्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन प्रशासनिक वीथिका में इन्हें मालवा सर्विसेस का अधिकारी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि साहब ने अपनी सेवा का अधिकांश समय इसी क्षेत्र में गुजारा है। वर्तमान में साहब इसलिए चर्चा में हैं कि जब वे मालवा क्षेत्र के एक बड़े जिले में बड़े पद पर पदस्थ थे तो उन्हें बड़ा सा सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। सुरक्षा को देखते हुए साहब ने अपने बंगले पर सरकारी वेंडर से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे। लेकिन जब साहब का वहां से तबादला हुआ तो वे बंगले में से अपना साजो सामान तो ले गए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी निकाल ले गए। सूत्रों का कहना है कि अब ये कैमरे साहब के फ्लैट में निगरानी कर रहे हैं। साहब के करीबी उनकी इस हरकत के लिए तरह-तरह के आक्षेप लगा रहे हैं।

एक के साथ एक फ्री

शीर्षक पढ़कर आपको लग रहा होगा कि कहीं कोई सेल लगाई गई है। लेकिन यह सेल का नहीं बल्कि अफसरों की पदस्थापना का मामला है। यह मामला प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए गठित विभाग का है। बताया जाता है कि इस विभाग में पहले से ही एक ईडी पदस्थ थे, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर एक और ईडी की पदस्थापना कर दी गई है। बताया जाता है कि ये दोनों ईडी मालवा के सबसे बड़े जिले में पदस्थ रहे एक कलेक्टर के खास हैं। कलेक्टर साहब की वहां से रवानगी हो गई है, लेकिन उनके खास ये दोनों अधिकारी अभी भी विभाग में पदस्थ हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक ही विभाग में एक ही काम के लिए दो ईडी पदस्थ करने पड़े हैं। गौरतलब है कि यह विभाग लक्ष्मी कमाने वालों पर खूब कृपा बरसाता है। इसलिए प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा भी जोरों पर है कि ये दोनों अधिकारी किसी टारगेट के तहत पदस्थ किए गए हैं। यहां बता दें कि इन दोनों अफसरों में से एक साहब महिला कांड में फंस चुके हैं। 2007 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी पर वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा इस कदर बरस रही है कि उनके विभाग की एक महिला के आत्महत्या मामले में इनका नाम आने के बाद उस मामले को इस कदर दबा दिया गया कि अब कोई उसका नाम भी नहीं ले रहा है। फिर भी साहब के साथ एक और अफसर की पदस्थापना चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

बड़ी मैडम की सिफारिश

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी की सिफारिश चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, मैडम ने यह सिफारिश दो विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे 2010 बैच के एक आईएएस अधिकारी के लिए की थी। जानकारी के अनुसार साहब वर्तमान में दो विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों विभागों के प्रमुख सचिव अलग-अलग हैं। इस दौरान जब साहब की सीआर लिखी जा रही थी तो उनके एक विभाग की प्रमुख सचिव महिला आईएएस अधिकारी ने तो उसे बेहतर तरीके से लिख दिया। साथ ही उन्होंने साहब के दूसरे विभाग के प्रमुख सचिव से सिफारिश की कि वे भी उनकी सीआर को अच्छे से लिख दें। अब प्रशासनिक महकमे में यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि मैडम को दूसरे विभाग के प्रमुख सचिव से जूनियर अफसर की सीआर लिखने की सिफारिश करनी पड़ी। यहां बता दें कि साहब पर पूर्व में हुए एक बड़े घोटाले के छींटे पड़ चुके हैं। शायद यही वजह है कि मैडम को सिफारिश करनी पड़ी।

एक नहीं चार जगह लगाएंगे

चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह-तरह के जतन कर रही है। कोई जाति, तो कोई धर्म के नाम पर मतदाताओं को खुश करने में लगा है। इसी कड़ी में गत दिनों महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसा ही एक आयोजन ग्वालियर-चंबल अंचल के एक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह विधानसभा क्षेत्र प्रदेश सरकार के एक राज्यमंत्री का है। मंत्रीजी मंच से महाराणा प्रताप की वीरता को लेकर कसीदे गढ़ रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में यहां महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी दौरान मंच के नीचे से एक व्यक्ति ने मंत्री से पूछ डाला कि क्या बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा भी यहीं लगवाएंगे, तो मंत्रीजी ने आव देखा न ताव और तपाक से जवाब दे डाला कि एक नहीं चार जगह लगाएंगे। मंत्रीजी की यह बात सुनकर लोग आवाक रह गए। क्योंकि क्षेत्र में ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। अब पार्टी के लोग इस गणना में लग गए हैं कि मंत्रीजी के इस बोल का क्या असर पड़ेगा।

फूड के लाइसेंस पर परोसी जा रही शराब

धुंधले नियमों की आड़ में जमकर उड़ रहा धुंआ

अस्पष्ट नियमों की आड़ में शहर में खुलेआम हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग का कहना है कि हमारी ओर से हुक्का बार के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट होने पर इनके विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा। जिम्मेदारों की टालमटोली के बीच युवाओं में हुक्का पाइप से धुआं उड़ाने का चलन धीरे-धीरे आम होता जा रहा है। बता दें कि गांधी जयंती पर नशामुक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश की धरती पर हुक्का लाउंज जैसी गतिविधियां नहीं चलेंगी। ऐसे लाउंज पर बुलडोजर चलाने जैसी सख्त कार्यवाही की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार आदेश की समीक्षा करने जैसे बहाने बनाने में लगे हैं। शहर में लगभग 150 हुक्का लाउंज संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से लगभग 40 प्रतिशत लाउंज संचालकों ने जिला प्रशासन के खाद्य विभाग से रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति ले रखी है। वहीं अन्य 60 प्रतिशत लाउंज तो ऐसे हैं जिनके पास रेस्टारेंट तक की अनुमति नहीं है और यह ऐसे ही चल रहे हैं। पड़ताल करने पर पता चला कि हुक्का लाउंज के नाम पर जिला प्रशासन के किसी भी विभाग द्वारा कोई अनुमति देने का कोई प्रविधान ही नहीं है। हुक्का लाउंज संचालक रेस्टोरेंट के नाम पर अनुमति लेते हैं और प्रशासन द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 200 × (सीओटीपीए या कोटपा एक्ट) के तहत कार्यवाही नहीं होने की वजह से पूरे रेस्टोरेंट में धुआं उड़ाने की छूट देते हैं।

मप्र में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया, जिसके बाद सरकार ने शराबबंदी के नाम पर अहातों को तो बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अवैध रूप से शराब परोसने का काम रुका नहीं है। इसका खुलासा गत दिनों राजधानी में आबकारी विभाग और पुलिस की छापामार कार्यवाही में हुआ है। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि कम समय के लिए लाइसेंस लेकर रात-रातभर शराब परोसी जा रही है।

अवैध शराब को लेकर शहर में गत दिनों पूर्व रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करोंद से लेकर बैरसिया, अयोध्या नगर, 11 मील और कोलार इलाके में दी गई दबिश में सामने आया कि ढाबों और होटलों के पास फूड लाइसेंस था, लेकिन वहां शराब के जाम छलक रहे थे। करीब 7 घंटे चली कार्यवाही में ही शराब की अवैध गट्टियों से लेकर, शराब तस्करी, ढाबों में अवैध रूप से शराब पिलाने और खरीदने तक के 71 मामले दर्ज किए। इतना ही नहीं अब आबकारी विभाग इनका फूड लाइसेंस रद्द किए जाने के लिए खाद्य विभाग को पत्र लिखेगा। भोपाल में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

40 कर्मचारियों को 7 टीमों में बांटा गया था। रात 11 बजे से फील्डिंग शुरू की गई। पूरी टीम ही सिविल में थी। ढाबों में अधिकारी ग्राहक की तरह शराब खरीदकर अंदर गए फिर साथियों को इसकी सूचना दे दी। कंट्रोल सजेंद्र मोरी ने बताया कि बनारसी ढाबा, देशी ढाबा, दांगी ढाबा, देशी डेरा, बंगरसिया, ग्रेवाल ढाबा, राधे-राधे ढाबा, देसी बिरयानी और रौनक ढाबा में बिना अनुमति के लोग शराब पीते मिले। विभाग की 5 टीमों को शराब दुकानों की निगरानी के लिए लगाया था। दरअसल, कई दिनों से कुछ इलाकों में शराब दुकानों के तय समय से अधिक समय तक खुले होने की शिकायतें मिल रहीं थीं। ऐसे में तय समय के बाद भी शराब बेचे जाने पर डीआईजी बंगला, सीहोर नाका, पुल बोगदा, हमीदिया रोड और डिपो चौराहा शराब दुकानों के खिलाफ मामले बनाए गए। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा का कहना है कि रात की कार्यवाही के बाद टीम ने सुबह अवैध शराब की भट्टियों पर कार्रवाई की। इस दौरान कजलीखेड़ा, कालापानी कोलार क्षेत्र में दबिश दी। यहां नालों के किनारे, जमीन में गड़े कुप्पों से हाथभट्टी शराब लाहन बरामद की। टीम ने गीताबाई समेत 5 पर प्रकरण बनाए। अब सिर्फ आकस्मिक लाइसेंस ही दिए जाएंगे।

उधर, ग्वालियर शहर में आहते बंद होने के बाद हाईवे पर स्थित ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ गत दिनों आबकारी विभाग टीम ने कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग को एक दर्जन से अधिक ढाबों पर कई लोग अवैध रूप से शराब पीते और पिलाते मिले जिस पर आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए शराब बरामद कर 15 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए। साथ ही ढाबा संचालकों को वार्निंग दी गई है कि अगर वह अपने ढाबों पर फिर से शराब पीते या पिलाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी मनीष द्विवेदी के अनुसार, अहाते बंद होने के बाद लगातार सूचना मिल रही थी कि हाईवे स्थित ढाबों पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर आबकारी टीम ने दबिश दी। टीम ने होटल पंडित, एन-11 रिसोर्ट, नीलकंठ, हवेली, नाका चंद्रवदनी सहित अन्य ढाबों पर निरीक्षण किया। यहां लोग अवैध रूप से शराब पीते हुए मिले। आबकारी टीम ने आठ ढाबा संचालक और करीब सात शराब पीने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। आबकारी टीम को इन ढाबों से बीयर और देशी शराब के क्वार्टर मिले। द्विवेदी ने बताया, आबकारी टीम अब लगातार ऐसे ढाबों और होटलों पर निगरानी रखेगी और कार्यवाही करेगी। कार्यवाही करने वाली टीम में आबकारी उपनिरीक्षक मोनिका पाठक, विवेक प्रकाश पटसारिया, संजय भदौरिया, पंकज शर्मा आदि शामिल थे।

वहीं आबकारी विभाग का अमला जैसे ही हाईवे किनारे ढाबों पर कार्यवाही करने पहुंचा तो शराब पिलाने वाले ढाबा संचालकों और पीने वाले ग्राहकों में भगदड़ मच गई। ढाबों पर शराब के जाम आपस में टकरा रहे लोग अपनी-अपनी टेबल छोड़कर खड़े हो गए इनमें से कुछ लोग अपनी शराब की बोतल और जाम से भरे ग्लास टेबल पर ही छोड़कर वहां से खिसक गए। जिनके खिलाफ आबकारी विभाग ने मौके पर ही आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किए। साथ ही ढाबों से भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें कि मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद सभी जिलों में चल रहे अहाते (खुले बार) 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए थे।

● **कुमार विनोद**

इंदौर बना 'ड्रग्स का अड्डा'

पब और पार्टियों में जमकर खपाए जा रहे ड्रग्स

शहर में ड्रग्स की सप्लाई लगातार बढ़ गई है। शहर में बड़ी संख्या में नाइट रेस्टोरेंट और पब हैं जहां पर बड़ी मात्रा में युवाओं में ड्रग्स खपाने के लिए मुंबई से मिनी मुंबई इंदौर का सफर तय कर ड्रग पैडलर इंदौर आ रहे हैं। यह इंदौर पुलिस के ड्रग्स के खिलाफ की जा रही मुहिम ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्यवाही है, जो बता रही है इंदौर शहर में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैल रहा है। हाल ही में पूर्व एयर होस्टेज रही महिला को पुलिस ने पकड़ा है जो कि बच्चों के डाइपर में एंटी ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करती थी। इसकी पहुंच सीधे शहर के बड़े पबों में थी जो पिछले कई सालों से ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। तेजी से विकास की दिशा में स्मार्ट होता इंदौर शहर नशे की आगोश में भी उतनी ही तेजी से स्मार्ट होता जा रहा है, शहर में ड्रग्स कारोबार तेजी बढ़ता जा रहा है। युवाओं को नशे की लत में धकेलने के लिए ड्रग्स पैडलर तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। पिछले 2 साल में ड्रग्स के मामलों में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा की अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ड्रग्स पकड़ी है। ड्रग्स मामले में पुलिस 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इन सभी का सीधा कनेक्शन मायानगरी मुंबई से है। पैडलर ड्रग्स लेकर इंदौर आते हैं और यहां पर शहर के अलग-अलग पबों में खपाते हैं।

मिनी मुंबई के नाम से पहचान बनाने वाले इंदौर शहर में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है। इसका प्रमाण है ऐसा कोई थाना नहीं है, जहां साल में 50 से अधिक ड्रग्स के केस दर्ज न हुए हों। पिछले साल शहर में नशा करने और बेचने वाले 2000 से अधिक लोग पकड़े गए थे। शांति समिति की बैठक में भी शहर में ड्रग्स का मामला उठ चुका है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने माना कि शहर में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है और उन्होंने इसकी सप्लाई चेन तोड़ने की बात कही है। शहर में सबसे अधिक गांजा धार-मनावर के अलावा देवास और खरगोन से शहर में पहुंच रहा है। वहीं काला गांजा आंध्रप्रदेश से पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर प्रदेश की बॉर्डर से लगे राजस्थान के प्रतापगढ़ से उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंच रही है। क्राइम ब्रांच ने इस साल ब्राउन शुगर के 43 केस बनाए हैं, जिनमें 73 आरोपियों से डेढ़ करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जबकि 50 लाख की एमडी। वहीं धार-मनावर से गांजा लेकर आने वाले दो दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच लगातार इन पर नजर रखे हुए है, ताकि सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके।

आला अफसरों ने ये भी स्वीकारा कि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कोई न कोई परिजन अपने बच्चों की इस ड्रग्स की नशाखोरी से दुखी होकर हम तक नहीं आता। शहर भी इस चिंता में शामिल हुआ। अफसरों ने भरोसा दिलाया कि चिंता न करें। सब पर नजर है। हर हाल में ड्रग्स की सप्लाई चेन को जल्द ही नेस्तनाबूद कर देंगे। ड्रग्स के खिलाफ चिंता में ये भी निकलकर आया कि शहर के कुछ थाना क्षेत्र इस बुराई के गढ़ बनते जा रहे हैं। इसमें खजराना, आजाद नगर, सदर बाजार, चंदन नगर, बाणगंगा और द्वारकापुरी अहम हैं। इन थाना क्षेत्रों में 100 से ज्यादा एनडीपीएस एक्ट के केस दर्ज हुए हैं। ये भी खुलासा हुआ कि एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर के सबसे ज्यादा केस इंदौर में ही दर्ज हुए हैं।

क्राइम ब्रांच के आंकड़े बताते है कि इंदौर तेजी से ड्रग्स का गढ़ बनता जा रहा है। पूरे प्रदेश में ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स के सबसे ज्यादा केस इंदौर में ही सामने आए। 2022-23 में 43 केस दर्ज हुए हैं। 73 लोगों को आरोपी बनाया गया। 1.56 करोड़ की ब्राउन शुगर भी शहर से पकड़ाई है। एक-एक ग्राम की पुड़िया के रूप में बिकने वाली एमडी ड्रग्स भी 480 ग्राम यानी आधा किलो के करीब पकड़ाई है। इस मामले में 10 केस दर्ज हुए और 73 आरोपियों पर कार्यवाही की गई। बीते साल भी करीब 2 किलो (1.88 किग्रा) ब्राउन शुगर जब्त की गई थी।

शहर में बढ़ती ड्रग्स की लत के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुखर हुए थे। उन्होंने पितृ पर्वत पर हुए आयोजन में दो टूक कहा था कि शहर सफाई में भले ही अव्वल है लेकिन यहां के युवाओं में ड्रग्स के नशे की लत भी तेजी से फैल रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए विजयवर्गीय ने बोला था। युवाओं को नशे से बचाने के लिए हनुमान चालीसा क्लब बनाने की बात भी कही थी। इसके बाद से हिंदू संगठनों ने भी नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को नशे में धकेलने वाले पैडलर भी नए तरीकों से ड्रग्स खापने में लगे रहते हैं। इंदौर पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले 2 महीने में 5 से ज्यादा बड़ी कार्यवाही कर चुकी है, जिनमें पुलिस ने मुंबई से इंदौर आकर ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपियों को पकड़ा है। हाल के दिनों में ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पूर्व एयर होस्टेज है जो कि बच्चों के डाइपर में ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करती थी। पुलिस पूछताछ में महिला से जुड़े हुए दो और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की सतर्कता से पकड़े जा रहे ड्रग पैडलर इस बात का सबूत हैं कि इंदौर शहर में युवा तेजी से नशे की आगोश में धकेले जा रहे हैं। शहर में बड़ी संख्या में पब और रेस्टोरेंट हैं जहां पर यह पैडलर्स अपने नशे का कारोबार चला रहे हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में ड्रग्स पैडलर्स का सीधा कनेक्शन मुंबई से है। पुलिस ने अब तक जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें अधिकतर मुंबई से ड्रग्स लाकर शहर में सप्लाई करते रहे हैं।

● **सुनील सिंह**

मप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में उतर चुके हैं, जहां भाजपा अपनी विभिन्न योजनाओं से जनता को रुबरु कराकर फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए 5 बड़े वादे किए हैं, जिसकी घोषणा बार-बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह 2018 में किसान कर्ज माफी की घोषणा ने उन्हें सत्ता दिलाई थी, ठीक उसी तरह कमलनाथ का 'पंच' इस बार जीत दिलाएगा।

मप्र में चुनावी 'घोषणाकाल'

घोषणाओं का वोटर्स पर असर

चुनावी साल में सियासी दलों की ओर से की जा रही घोषणाओं का वोटर्स पर भी असर देखा जा रहा है। लाड़ली बहना और नारी सम्मान योजना को लेकर महिला वोटर्स में खासी उत्सुकता है। लाड़ली बहना योजना के आवेदन भरने के दौरान जहां वार्ड कार्यालय में भारी भीड़ देखी गई है तो अब कांग्रेस नारी सम्मान योजना के तहत घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रही है। वहीं किसान कर्ज माफी भी ग्रामीण इलाकों में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। भाजपा जहां कांग्रेस पर किसानों को कर्जमाफी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगा रही है और डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफी का ऐलान कर रही है। वहीं कांग्रेस फिर दावा कर रही है कि सत्ता में आने पर एक बार फिर किसान कर्जमाफी की जाएगी।

मप्र में विधानसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए इस वक्त घोषणाओं का दौर चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस में घोषणा करने की एक होड़ सी लगी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग हर दिन कुछ-न-कुछ घोषणा कर रहे हैं तो विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भाजपा की काट के लिए उससे बढ़कर घोषणाएं की जा रही है। दरअसल, कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए घोषणाओं के भरोसे है। चुनाव में महिला वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का ऐलान कर महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने उससे बढ़कर नारी सम्मान योजना के तहत डेढ़ हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ विधानसभा चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस सत्ता में आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है। इसके साथ मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसान वोटबैंक को साधने के लिए सत्ता में आने पर कर्जमाफी का वादा कर रही है। वहीं सरकार आने पर कांग्रेस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रही है। वहीं चुनाव में युवा वोटरों को साधने के लिए रोजगार देने का वादा करने के साथ सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने जा रही है। पार्टी अपने वचन पत्र में सत्ता आने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ दो से ढाई हजार तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने की तैयारी में है।

मप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने एक और बड़ा वादा प्रदेश की जनता से कर दिया है। धार के बदनावर में पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाएगा। दरअसल मुफ्त बिजली देने का वादा कांग्रेस का सफल चुनावी फॉर्मूला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का कार्ड खेला था। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और चुनावी परिणाम बताते हैं कि जनता ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया। कमलनाथ का कहना है कि हम झूठी घोषणाएं नहीं करते, हम तो वचन देते हैं और उसे पूरा करते हैं। हमने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वचन दिया था, जिसे पूरा किया था। कमलनाथ का कहना है कि हमारे दिल-दिमाग में समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की सोच है। यदि उसे 100 यूनिट बिजली बिल से राहत मिलेगी तो हमारा गरीब, आदिवासी, किसान सशक्त बनेगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और गांव की किराने की दुकान भी चलेगी।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार जनता को 5 वादों से रूबरू करा रहे हैं। कभी सभाओं में तो कभी ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री 5 बड़े वादे कर रहे हैं वे हैं-गैस सिलेंडर 500 रुपए में, हर महिला को 1,500 रुपए प्रति महीना, बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, किसानों का कर्ज माफ और पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। उनका कहना है कि जिस प्रकार कर्नाटक में हमने वादा निभाया है, उसी प्रकार मप्र में भी वादा निभाएंगे। कमलनाथ द्वारा गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में देने की घोषणा की गई है, वर्तमान में गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपए में आ रहा है, पहले इस पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन वह भी

लगभग बंद के समान हो गई है। जब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की शुरुआत की गई थी, तब गैस सिलेंडर रिफिलिंग 850 रुपए के करीब होती थी और करीब 250 से 300 रुपए सब्सिडी में आ जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे सब्सिडी कम करते-करते अब लगभग बंद सी कर दी है। प्रदेश में भाजपा सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। इस पर कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया है, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। भाजपा सरकार ने डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है, लेकिन वह भी तब जब उनकी सरकार बनेगी।

वहीं कमलनाथ का एक अहम वादा है पुरानी पेंशन योजना लागू करना। ये मुद्दा लगभग सभी प्रदेशों में छाया हुआ है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू कर देगी, लेकिन नहीं की। दोनों प्रदेशों में अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन दे रही है, अब मप्र में भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 यूनिट पर हाफ का वादा भी लोगों को लुभा रहा है। बिजली बिल ऐसी चीज है, जिसका असर आम और खास सभी पर पड़ता है, वर्तमान में 100 यूनिट से कम बिजली की खपत होने पर महज 100 रुपए के अंदर ही बिल आता है, लेकिन 100 यूनिट से ऊपर हो जाने पर फिर बिल साधारण बिल की तरह आता है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोगों को अधिक बिल चुकाना पड़ता है। कमलनाथ का वादा है कि हमारी सरकार बनी तो हम 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर देंगे, इसके ऊपर आने पर उसे आधा कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के इस

ऐलान के बाद अब पार्टी अपने घोषणा पत्र में (वचन पत्र) में किसानों के बिजली बिल की माफी को शामिल कर सकती है। दरअसल मप्र में ग्रामीण इलाकों में किसानों के बिजली बिल का मुद्दा इस वक्त प्रदेश की राजनीति में गर्माया हुआ है और कांग्रेस इसका चुनावी लाभ लेने की तैयारी में है।

चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस में घोषणाओं की एक दौड़ सी लगी है और चुनाव से पहले का समय घोषणाकाल जैसा नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए सत्ता में काबिज भाजपा सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। चुनाव से ठीक पहले महिला वोटर्स के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान ने लाड़ली बहना योजना का ऐलान किया। योजना के तहत महिलाओं को जून महीने से 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं चुनाव में युवा वोटरों को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लाई है। सीखो और कमाओ योजना के तहत युवाओं को हर महीने 8 हजार से 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। जून से शुरू होने वाली योजना में अगस्त से रोजगार दिया जाएगा और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले सितंबर में पैसा दिया जाएगा। वहीं चुनावी साल में शिवराज सरकार ने 12वीं कक्षा की टॉपर बालक और बालिकाओं को ई-स्कूटी देने जा रही है। पहले सरकार केवल लड़कियों को ई-स्कूटी देने का ऐलान किया था वहीं पिछले दिनों भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने लड़कियों के साथ लड़कों को भी ई-स्कूटी देने की भी घोषणा कर दी।

चुनाव में वोटरों को साधने के लिए चुनावी साल में ही शिवराज सरकार गरीबों को मुफ्त प्लॉट दे रही है। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के तहत गराबों को मुफ्त भूखंडों का वितरण जोर-शोर से किया जा रहा है। वहीं चुनाव से ठीक पहले सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवा रही है।

भाजपा जहां सत्ता बचाने के लिए घोषणाओं का सहारा ले रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए घोषणाओं के भरोसे है। सरकार आने पर कांग्रेस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रही है। वहीं चुनाव में युवा वोटरों को साधने के लिए रोजगार देने का वादा करने के साथ सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने जा रही है। पार्टी अपने वचन पत्र में सत्ता आने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ दो से ढाई हजार तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने की तैयारी में है।

● **जितेंद्र तिवारी**

कमलनाथ के 5 वादे बदलेंगे माहौल

मप्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में उतर चुके हैं, जहां भाजपा अपनी विभिन्न योजनाओं से जनता को रूबरू कराकर फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए 5 बड़े वादे किए हैं, जिसकी घोषणा बार-बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर जनता को 5 वादों से रूबरू कराया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार कर्नाटक में हमने वादा निभाया है, उसी प्रकार मप्र में भी वादा निभाएंगे। उन्होंने इस बार वादों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं रखते हुए सिर्फ 5 वादे किए हैं। कमलनाथ के 5 बड़े वादों में गैस सिलेंडर-500 रुपए, हर महिला को 1,500 रुपए प्रति महीना, बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू करना आदि शामिल हैं।

परिवहन की व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त

मप्र में परिवहन विभाग अपनी सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर उन्हें दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इस संदर्भ में गत दिनों विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 जून तक ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस में पता बदलवाने की व्यवस्था आदि ऑनलाइन शुरू कर दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन व जिला परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, पता, नाम बदलवाने जैसी 5 सुविधाएं ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन एनआईसी के पोर्टल पर बढ़ रहे दबाव के कारण व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। कभी पोर्टल की रफ्तार कम होने तो कभी कार्ड की कमी के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने में परेशानी आ रही है। इसलिए बैठक में निर्णय लिया गया है कि इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।

गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने बीते साल नवंबर माह में पहले घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा शुरू की थी। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट पर खुद ही लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं। वहीं कियोस्क पहुंचकर भी लाइसेंस बनवा रहे हैं। अब खुद लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद छह महीने की समयावधि में एक माह बीतने पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर तय समय में आरटीओ पहुंचकर परमानेंट लाइसेंस बनवा रहे हैं। जिनके लिए ही लोग आरटीओ फोटो खिंचवाने, फिंगर प्रिंट व हस्ताक्षर की प्रक्रिया करने सहित टेस्ट देने जाते हैं।

परिवहन विभाग की सभी सेवाएं राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) वाहन-4 व सारथी-4 पोर्टल के माध्यम से मिल रही हैं, लेकिन इस पोर्टल पर हर दिन नई समस्या सामने आ रही है। परमिट की समस्याएं दूर नहीं हुईं, जिससे ऑपरेटर परमिट के लिए परेशान हैं। लोग अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम भी बन गया है, लेकिन उससे ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। ट्रक व बस के नेशनल परमिट जारी करने में नई दिक्कत सामने आई है। पुरानी गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन उसका परमिट पहले मालिक के नाम ही प्रदर्शित हो रहा है। इस कारण परमिट का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार नहीं हो पा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में चलने वाले वाहन जो दो राज्यों में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें एक जगह ट्रांसफर किया जाए। जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में करीब 500 वाहन ऐसे हैं, जिनका डाटा एनआईसी के पोर्टल पर ट्रांसफर नहीं हो पाया है। बैठक में 15 जून तक इनका निराकरण करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस का जो डाटा पोर्ट हुआ है, वह अधूरा है। किसी का सरनेम नहीं, तो किसी के नाम में गलती है। डेटा मिसमैच होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होता है। इसमें सुधार के लिए आरटीओ के पास जाना पड़ता है। यहां से भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा है। लोग अपने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भटक रहे हैं। दरअसल, पोर्टल की धीमी गति के कारण आरटीओ संबंधी कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। एनआईसी के दोनों पोर्टल का आए दिन सर्वर धीमा चलता है। कई बार सर्वर बंद हो जाता है। इससे आरटीओ संबंधी कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाते हैं। आरटीओ में एनआईसी की तरफ से कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं है, जो बता सके कि बार-बार दोनों पोर्टल का सर्वर क्यों धीमा चलता है, या फिर क्यों बंद हो जाता है।

वहीं प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन के लिए नई नीति बनाई जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 में संशोधन कर इसे पुन: लागू किया जाएगा। वर्तमान समय में ई-वाहनों को लेकर काफी कुछ बदलाव हुए हैं। नई आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व की नीति में भी बदलाव की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने नीति को नए स्वरूप में बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जून में विशेषज्ञों के साथ एक बैठक भी आयोजित की जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के वाहन निर्माता, वाहन डीलर, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बुलाया जा रहा है। इनके साथ बैठक कर नई नीति के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर नीति का प्रारूप तय किया जाएगा।

● **प्रवीण सक्सेना**

वाहनों पर टैक्स भार घटाया

मप्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जनता के हित में नित नए निर्णय ले रही है। इसी क्रम में अब मप्र सरकार ने यात्री बसों का टैक्स भार घटाया है। परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव नए टैक्स निर्धारित किए हैं। संशोधित शुल्क आगामी 19 जून के बाद पूरे राज्य में प्रभावशील होंगे। वाहन बेचने वाले डीलरों को भी व्यापार प्रमाण-पत्र लेने पर अब स्लैब के अनुसार शुल्क देना होगा। इसके अलावा सरकारी वाहन पर उसकी आयु के हिसाब से लाइफ टाइम टैक्स लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहनों के मानक मूल्य भी तय कर दिए हैं। भारत में निर्मित वाहन के मानक मूल्य में एक्स शोरूम मूल्य, जीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल रहेगा या डीलर द्वारा जारी वाहन के मूल्य का बीजक, इनमें से जो भी ज्यादा हो, मानक मूल्य रहेगा। विदेश से आयात कर भारत लाए वाहन के मानक मूल्य में सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी लैंड वेल्यू जिसमें सभी कर शामिल हैं, सम्मिलित रहेगा। ऑल इंडिया परमिट वाली बसों जिनमें बैठक क्षमता 13 प्लस एक या अधिक है और निजी सेवा वाहन के रूप में अन्य राज्य से जारी अनुज्ञा पत्र पर मप्र में संचालित हो रही है, उन्हें 200 रुपए प्रति सीट टैक्स देना होगा। पहले यह टैक्स 700 रुपए प्रति सीट था।

मोर्चा संभालेंगी प्रियंका गांधी

हिमाचल और कर्नाटक में लगातार सक्रिय रहकर कांग्रेस को सत्ता में लाने वाली प्रियंका गांधी अब मप्र में चुनावी मोर्चा संभालेंगी। प्रियंका गांधी जबलपुर जिले में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका 12 जून को जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद जबलपुर में रोड शो और रैली के साथ विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी।

महाकौशल इलाके का जबलपुर सबसे बड़ा शहर है। इस इलाके में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी तथा भाजपा को सिर्फ दो सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के विधायक और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बताया कि प्रियंका गांधी सबसे पहले यहां पवित्र नदी के ग्वारीघाट तट पर नर्मदा पूजा करेंगी। इसके बाद वह रोड शो करेंगी और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वह 12 जून को नर्मदा नदी का आशीर्वाद लेने के बाद पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान संकल्प 2023 की शुरुआत करेंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के प्रचार ने हिमाचल और कर्नाटक में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। जबलपुर के महापौर और कांग्रेस के नगर प्रमुख जगत बहादुर सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी यहां दो किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी और बाद में उनकी रैली में डेढ़-दो लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि जबलपुर संभाग के लोग भाजपा शासन से तंग आ चुके हैं। जिसके कारण 2023 के चुनावों में कांग्रेस महाकौशल क्षेत्र में जीत हासिल करेगी।

कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस क्षेत्र से नहीं गुजरी थी और यात्रा ने मालवा और मध्य भारत को कवर किया था तथा वहां जनता से यात्रा को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि महाकौशल क्षेत्र में प्रियंका की रैली से पड़ोसी विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में भी कांग्रेस को मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में एक मजबूत सत्ता विरोधी भावना है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी, पारंपरिक कांग्रेस मतदाता रहते हैं। मप्र में मुख्य तौर पर छह क्षेत्र- महाकौशल, ग्वालियर-चंबल, मध्य भारत, निमाड़-मालवा, विंध्य और बुंदेलखंड हैं। महाकौशल या जबलपुर संभाग में-जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और छिंदवाड़ा सहित आठ जिले आते हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने क्षेत्र के 38 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 पर जीत हासिल की थी। वहीं, एक सीट पर कांग्रेस के करीबी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। छिंदवाड़ा प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ का गृह क्षेत्र है। वे कई बार क्षेत्र से लोकसभा सांसद रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं। वर्ष 2013 में, कांग्रेस ने इस क्षेत्र में खराब प्रदर्शन किया तथा उसने 13 सीटें हासिल की जबकि भाजपा ने 24 सीटों पर विजय दर्ज की थी और तब भगवा पार्टी राज्य में सत्ता में आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में मप्र के 230 सदस्यीय सदन में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, जबकि भाजपा ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी।

मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर चुनाव लड़कर सत्ता की वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। कर्नाटक में जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी ने कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाई, ठीक उसी तर्ज पर मप्र में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी चुनावी मैदान में आ डटी है। चुनाव से पहले दिग्विजय-कमलनाथ की जोड़ी एक सुर में भाजपा पर आक्रामक नजर आ रही है। चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे कमलनाथ ने पार्टी के चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। कमलनाथ लगातार जिलों का दौरा कर पार्टी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कमलनाथ चुनावी मंचों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दों का ऐलान कर जनता को सीधे पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। बात चाहे नारी सम्मान योजना की हो या सत्ता में आने की मुफ्त बिजली देने के ऐलान की, कमलनाथ चुनावी मंच से लोगों के बीच कांग्रेस के नारे को पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के चुनावी कैंपेन में कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह खुलकर हर मंच से कह रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। दिग्विजय सिंह साफ कह रहे है कि वह मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने की बात उस समय कही जब कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने पर ऐतराज जता चुके थे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर मीडिया के सवालों पर दिग्विजय सिंह बेबाकी से कहते है कि हमारा एक ही चेहरा हैं वो हैं कमलनाथ। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने के साथ पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने के साथ कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह लगातार जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं को समझाइश देने के साथ एकजुटता का संकल्प दिला रहे हैं। पिछले दिनों सिंगरौली पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। प्रदेश में पार्टी की लगातार हार पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है और चुनाव में कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है।

● **अरविंद नारद**

कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद

2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, दिग्विजय सिंह उन सीटों पर पहुंचकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे है। दिग्विजय सिंह मंडलम सेक्टर की बैठक में शामिल होकर ब्लॉक, उप ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बीएलए स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे है। दिग्विजय सिंह बूथ पर कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कह रहे है कि अगर कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करके उनसे चुनाव की तैयारियों को लेकर सुझाव भी मांग रहे है। बैठक के अंत में दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी उम्मीदवार को जिताने का संकल्प भी दिला रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में भाजपा पर लगातार हमलावर है।

93 प्रतिशत हेल्थ वर्कर डिप्रेशन में

कोरोना की पहली-दूसरी लहर का नाम आते ही आंखों के सामने लॉकडाउन, अस्पतालों में आईसीयू और ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद के साथ एक के बाद एक हो रही मौत का दृश्य नजर आने लगता है। कोरोना का शारीरिक के साथ मानसिक स्तर पर भी बुरा असर पड़ा है। इसका डर और तनाव सिर्फ कोविड मरीजों ने नहीं, बल्कि उनका इलाज कर रहे हेल्थ वर्कर्स ने भी सहा है जिससे उनका स्ट्रेस बढ़ गया था। यह खुलासा भोपाल एम्स और इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज बीकानेर की एक स्टडी में सामने आया है। लंदन की जर्नल ऑफ एक्यूट डिजीज में यह स्टडी प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि कोरोना की लहर के दौरान कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ में तनाव का स्तर काफी बढ़ गया था। स्टडी में शामिल कुल हेल्थ वर्कर्स में से 93 फीसदी (93.37 प्रतिशत) ने यह स्ट्रेस उस दौरान महसूस किया। इनमें से करीबन 20 फीसदी (19.88 प्रतिशत) को तो हाई स्ट्रेस रहा। शादीशुदा हेल्थकर्मियों में से 95 फीसदी स्ट्रेस में थे। हेल्थकर्मियों ने कैसे उस दौरान अपना स्ट्रेस कम किया और मरीजों का इलाज करने में लगे रहे, यह भी इस स्टडी का हिस्सा है।

भोपाल एम्स के नर्सिंग ऑफिसर-सुपरिटेंडेंट की टीम ने इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज बीकानेर के साथ मिलकर कोविड के पहले और दूसरे फेस के दौरान कोविड मरीजों के इलाज में लगे मेडिकल स्टॉफ में तनाव की स्टडी की। स्टडी में शामिल भोपाल एम्स के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट (साइकेट्रिक नर्सिंग एक्सपर्ट) दिगपाल सिंह चुंडावत और भोपाल एम्स की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट (साइकेट्रिक नर्सिंग एक्सपर्ट) मुदिता शर्मा ने बताया कि महामारी के पहले फेस के दौरान हर आदमी डरा हुआ था। मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और वे अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। वह समय हेल्थकर्मियों के लिए बहुत ही तनाव भरा था। कई रिसर्च में सामने आया है कि ठीक होने के बाद भी कई कोविड मरीज मानसिक बीमारियों का शिकार हुए। इसका असर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों सब पर पड़ा। एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया था।

पहले फेस के दौरान कोविड वैक्सीन और इलाज के लिए कोई तय दवाई भी नहीं थी। उन हालात में हेल्थकर्मियों को 10-12 घंटे पीपीई किट पहनकर लगातार काम करना पड़ रहा था। दिगपाल के अनुसार, हमने भोपाल एम्स में उस दौरान कोविड की ड्यूटी में लगे 694 मेडिकल स्टॉफ का आंकलन किया। इसमें 64 फिजिशियन, 606 नर्स और 24 अन्य हेल्थकर्मी शामिल थे। इन सभी की आयु 20 से 52 वर्ष थी। इस स्टडी के डेटा कलेक्शन और उसके विश्लेषण में इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस, बीकानेर के सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शत्रुघन पारिक, भोपाल एम्स के नर्सिंग ऑफिसर सुनील कुमार टेलर और रोहित रिछारिया शामिल थे। यह स्टडी मई से जुलाई 2021 के दौरान की गई थी। लंदन की जर्नल ऑफ एक्यूट डिजीज ने फरवरी 2023 में स्टडी को स्वीकृत मिली और 26 अप्रैल 2023 में इसे पब्लिश किया।

डेटा विश्लेषक शत्रुघन और सुनील ने बताया कि स्टडी में शामिल सभी 694 मेडिकल स्टॉफ को उम्र, एजुकेशन, लिंग, प्रोफेशन, हेल्थ सेक्टर में काम के अनुभव, काम के क्षेत्र के अनुसार बांटा गया। इसमें शामिल सभी के स्ट्रेस का आंकलन 32 सवालों के आधार पर किया गया। पहले उनसे स्ट्रेस लेवल से जुड़े सवाल पर जवाब मांगे गए। उसके बाद मिले जवाब से तय फॉर्मूले के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। स्टडी में आयु वर्ग के हिसाब से 694 में सबसे ज्यादा 20-30 साल के 522 युवा थे। 31-40 आयु वर्ग के 158 और 41-50 आयु वर्ग के 12 और 51 से ज्यादा उम्र के 2 हेल्थकर्मी शामिल थे। स्टडी में पाया गया कि 93 फीसदी युवा हेल्थकर्मी, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी, उनका भी स्ट्रेस का लेवल अन्य बड़ी आयु वालों की तरह ही ज्यादा था। इस युवा वर्ग में शामिल कुल 522 में 386 हेल्थकर्मियों को मध्यम स्ट्रेस और 102 को हाई स्ट्रेस था। सिर्फ 34 लोगों में स्ट्रेस का स्तर कम मिला, जबकि 31-40 आयु वर्ग वाले 158 लोगों में से 148 स्ट्रेस में थे।

भोपाल एम्स के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिगपाल ने बताया कि स्टडी में शामिल कुल स्वास्थ्यकर्मियों में से शादीशुदा कर्मचारियों में स्ट्रेस कुछ ज्यादा था। शादीशुदा 418 मेडिकल स्टॉफ में से 398 (95.21 प्रतिशत) में स्ट्रेस मिला। इनमें से 308 को मध्यम और 90 को हाई स्ट्रेस था। अविवाहित 266 हेल्थकर्मियों में से 242 (90.97 प्रतिशत) में स्ट्रेस का लेवल अधिक था। स्टडी में शामिल फिजिशियन, नर्स व अन्य मेडिकल स्टॉफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस नर्सों में देखा गया। कोरोना के दौरान उनकी ड्यूटी आईसीयू व वार्ड में लगती थी और दोनों जगहों पर उन्हें मरीजों के संपर्क में रहना पड़ता था। 606 नर्स में से 574 (94.71 प्रतिशत) में स्ट्रेस देखा गया। इनमें से 454 में मध्यम और 120 में हाई स्ट्रेस रहा। वहीं कुल 64 फिजिशियन में से 50 में स्ट्रेस मिला। इनमें 38 को मध्यम और 12 को हाई लेवल का तनाव रहा।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

महिलाओं से अधिक पुरुष कर्मियों में बढ़ा लेवल

डेटा विश्लेषक रोहित रिछारिया के अनुसार पुरुष हेल्थकर्मियों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा स्ट्रेस था। कुल 476 पुरुष स्वास्थ्यकर्मियों में से 456 (95.79 प्रतिशत) और कुल 218 महिलाकर्मियों में से 192 (88.07 प्रतिशत) का स्ट्रेस बढ़ा था। नए हेल्थकर्मियों से ज्यादा स्ट्रेस व डर 3-6 साल से काम कर रहे वर्कर में मिला। 3-6 साल का काम अनुभव रखने वाले 97.3 फीसदी कर्मियों ने अपना स्ट्रेस बढ़ा हुआ महसूस किया। कुल 432 कर्मी ऐसे थे, जिन्हें एक से तीन साल के बीच का अनुभव था, उनमें से 402 लोगों (93.05 प्रतिशत) में स्ट्रेस का स्तर बढ़ा था। इनमें मध्यम स्ट्रेस वाले 322 और हाई स्ट्रेस वाले 80 लोग थे। सिर्फ 30 लोगों में स्ट्रेस लेवल कम था। वहीं स्टडी में यह भी सामने आया कि कोविड आईसीयू में काम करने वाले हेल्थकर्मियों से ज्यादा वार्ड में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में ज्यादा स्ट्रेस था। वार्ड में ड्यूटी कर रहे 93 फीसदी कर्मियों को तनाव था।

कई नौकरशाह खा रहे जेल की हवा

देश में प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई, तो कोई अन्य की जांच में दोषी पाया गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के इस कदम को जहां एक ओर सराहा जा रहा है, वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि देश में ब्यूरोक्रेट्स की कमी के बावजूद इन अफसरों को जेल में डालने से व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा।

गौरतलब है कि अभी तक देश के विभिन्न राज्यों के जिन नौकरशाहों को खासकर आईएएस अफसरों को जेल में डाला गया है, वे अपने राज्य में महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे थे। अगर देखा जाए तो इन अफसरों के नेतृत्व में उक्त विभाग कामकाज की दृष्टि में अन्य विभागों से काफी आगे रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन अफसरों को जेल की हवा खानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार देशभर में सबसे अधिक आईएएस अधिकारी झारखंड के हैं, जो जेल की हवा खा रहे हैं। इनमें छवि रंजन, सैय्यद रियाज अहमद, अनिल कुमार और पूजा सिंघल का नाम शामिल है। अभी हाल ही में रांची के पूर्व डीसी रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। लंबे समय से चल रही जांच, कई सवाल-जवाब के बाद छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया।

झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 11 महीने में कई आईएएस अधिकारियों को अपनी रडार में ले रखा है। इन अधिकारियों पर कई मामलों में जांच चल रही है। 5 बड़े मामलों में 4 आईएएस अधिकारी जांच के घेरे में हैं। ईडी इनसे जुड़ी करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। ताजा मामला आईएएस छवि रंजन का है जिन पर सख्त कार्रवाई हुई है। आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त कुछ महीने पहले तक जेल में छापेमारी करने जाते थे। अब भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार होने के बाद उसी जेल में कैदी की तरह रहने पहुंचे हैं।

वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। फरवरी में पूजा सिंघल को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। बेटी के इलाज के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी। इसके पहले भी उन्हें कंडीशनल अंतरिम राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 12 अप्रैल को ईडी की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूजा सिंघल पर पीएमएलए कोर्ट में बीते दिनों आरोप तय कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईडी की ओर से पूजा सिंघल समेत अन्य के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू में डीसी रहते हुए उनके खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक आए थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई।

इधर 2019 के आईएएस अधिकारी खूंटी के एसडीएम रियाज अहमद आईआईटी की एक छात्रा के यौन शोषण के आरोपों में फंसे हैं। उन पर निलंबन की तलवार लटक रही है। चाईबासा में तैनात भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी भी यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं। राज्य के नौकरशाहों के विभिन्न मामलों में फंसने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी के बारे में गलत छवि बन रही है। हालिया घटनाओं से कुछ अधिकारी परेशान हैं और वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की घटनाएं मनोवैज्ञानिक असर डालती है। लोगों में इससे गलत छवि बन रही है। ज्यादातर अधिकारी अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं, लेकिन वे भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। कुख्यात चारा घोटाले में राज्य के कई आईएएस अधिकारी फंसे। पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, फूलचंद सिंह, बेक जूलियस आरोपों में सजायाफ्ता हुए। दवा घोटाले में आईएएस अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार फंसे। वैसे देश के विभिन्न राज्यों में ब्यूरोक्रेट्स लगातार किसी न किसी मामले में फंसते रहते हैं और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। अब तक कई अफसरों को भ्रष्टाचार के कारण अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

विश्नोई के साथ सौम्या चौरसिया भी जेल में

छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया इस समय जेल में हैं। राज्य सरकार ने आईएएस समीर विश्नोई को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि विश्नोई के घर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने छापा मारा था, जिसमें 47 लाख नगद के साथ ज्वैलरी जब्त की गई थी। ईडी ने दो बार में 14 दिन की रिमांड लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 27 अक्टूबर को रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया था। इसी दिन सरकार ने विश्नोई को सस्पेंड कर दिया था। वहीं 2 दिसंबर 2022 को अफसर सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 12 दिनों तक सौम्या चौरसिया ईडी की कस्टडी में रही हैं। उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। वहीं आय से अधिक संपत्ति कर मामले में जेल में बंद उत्तराखंड के पूर्व आईएएस रामविलास यादव को अब ईडी ने भी गिरफ्तार किया है। पीएमएलए एक्ट के तहत सुद्धोवाला जेल में यादव की औपचारिक गिरफ्तारी की गई। इसके बाद से उसे फिर सुद्धोवाला जेल में ही दाखिल कर दिया गया। बता दें कि आईएएस रहते ही रामविलास यादव को पिछले साल विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। यादव पर आरोप है कि उसने उत्तराखंड में तैनात रहते आए से अधिक संपत्ति अर्जित की है। विजिलेंस ने जांच में पाया था कि उसने ज्ञात सोर्स से करीब 78 लाख रुपए की कमाई की। जबकि, उनके पास 21 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई है।

30 अगस्त 2022 की बात है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हें अलग-अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। 30 मई 2023 यानी 9 महीने बाद भी भारत सरकार इन्हें छुड़ा नहीं पाई है। अब भारत के पूर्व नौसेना अफसरों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे और उन्हें कतर की अदालतों में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इससे भारत लौटने की उनकी उम्मीदें फीकी पड़ती जा रही हैं।

साजिश या कुछ और?

कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी में काम कर रहे 8 पूर्व नौसेना अफसरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम हैं- कैप्टेन नवतेज सिंह गिल, कैप्टेन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टेन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते थे। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। यह कंपनी कतर की नौसेना यानी क्यूईएनएफ को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस प्रदान करती है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने और उनकी रिपेयरिंग व मेंटेनेंस का एक्सपर्ट बताती है। इस वेबसाइट पर कंपनी के सीनियर अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट अब मौजूद नहीं है।

जेल में बंद कमांडर पूर्णेन्दु को कतर में प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है। दाहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। वह यह पुरस्कार पाने वाले आर्म्ड फोर्सेज के एकमात्र शख्स हैं। उस वक्त दोहा में तब के भारतीय राजदूत पी कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेज इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख ने भी पूर्णेन्दु का स्वागत किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन कल्चरल सेंटर में हुआ था। उस वक्त भारतीय दूतावास में तैनात इंडियन नेवी के कैप्टन कपिल कौशिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

कतर ने आरोप लगाया है कि ये नेवी ऑफिसर्स उसके पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी कर रहे थे और इजरायल को जानकारियां मुहैया करा रहे थे। न तो कतर की तरफ से और न ही भारत सरकार की तरफ से आरोपों को लेकर कोई जानकारी साझा की गई है। दोनों ही सरकारों ने उन आरोपों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है जिसके तहत इन्हें 9 महीने से जेल में रखा गया है। इस पूरे मामले ने कतर और भारत के रिश्तों पर भी खासा असर डाला है।

पनडुब्बी जासूसी कार्यक्रम की जासूसी को लेकर जो भी मीडिया रिपोर्ट्स पिछले दिनों आई हैं, वो पूरी तरह से अपुष्ट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के पनडुब्बी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली कंपनियों में से एक कंपनी इटली की नौसैनिक जहाज निर्माण कंपनी, फिनकैंटिएरी खासतौर पर शामिल है। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कतर की कंपनी दाहरा ग्लोबल बंद होने वाली है। ऐसे में उसने काम करने वाले सभी भारतीयों को छोड़ने के लिए कह दिया है। दूसरी तरफ इटैलियन कंपनी फिनकैंटिएरी ने कतर सरकार के

कतर पर दबाव क्यों नहीं बना रही केंद्र सरकार?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले दिनों कहा था, क्या प्रधानमंत्री इस वजह से कतर पर दबाव बनाने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड अडाणी इलेक्ट्रिसिटी, मुंबई में एक प्रमुख निवेशक है। क्या इसीलिए जेल में बंद पूर्व नौसेना कर्मियों के परिजन जवाब के लिए दर-दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार बताए कि पूर्व नौसेना के कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार 8 कर्मियों को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखा गया है। भारत सरकार को इनके खिलाफ आरोपों की जानकारी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में दोहा, कतर का दौरा किया था। एक संयुक्त वक्तव्य में मोदी ने भारतीय समुदाय की मेजबानी करने और उनके कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कतर के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर संसद में कहते हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के हित हमारे दिमाग में सबसे पहले हैं।

लिए किसी भी प्रोग्राम के तहत पनडुब्बी बनाने की बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फिनकैंटिएरी तस्वीर से बाहर है। ऐसे में संभावना है कि एक कतर की डिफेंस कंपनी, दो और इटैलियन कंपनियों के साथ, इस पूरे बवाल के पीछे शामिल हो सकती है। एक जांच के बाद रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह एक साजिश है जिसमें भारतीय नागरिकों को एकांत कारावास में भेज दिया गया है। जो भी रिटायर्ड अधिकारी जेल में हैं वो दाहरा ग्लोबल के लिए काम कर रहे थे।

यह पूरी कहानी कंपनियों के चक्रव्यूह और क्रॉस होल्डिंग्स से जुड़ी है जिसके तार कतर से लेकर इटली तक फैले हैं। दावा किया जा रहा है कि कतर के प्रभावशाली शासकों के साथ ही उनके करीबी भी इसमें शामिल हैं। साल 2019 में जहाज बनाने वाली इटली की एक कंपनी कैबी कट्टानियो को कतर की नौसेना से खाड़ी देश के लिए दो पनडुब्बियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट 190 मिलियन यूरो की कीमत के साथ था। सूत्रों की मानें तो यह प्रोजेक्ट इटली की एक और कंपनी एम23 की मदद से चलाई जा रही थी। यह कंपनी एक और इटैलियन शिप मेकर कंपनी जीएसई ट्राइस्टे का ही एक हिस्सा है। एम23 की टॉप लीडरशिप में शामिल बाकी लोगों में तौफिक अबी फदेल शामिल हैं, जो कतर के शाही परिवार के करीबी हैं। वह इस समय कतर की सरकारी कंपनी बरजान होल्डिंग्स के लीगल हेड हैं। यह कंपनी, देश के रक्षा मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। इसे मार्च 2018 में कतर की सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से बनाया गया था। बरजान होल्डिंग्स के प्रेसीडेंट खालिद बिन मोहम्मद अल अत्तियाह हैं, जो कतर के रक्षा राज्यमंत्री भी हैं। उनके अनुसार, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य कतर की लंबी रक्षा और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है। दूसरे आसान शब्दों में अगर यह कहें कि बरजान होल्डिंग यह तय करता है कि रक्षा जरूरतों पर कतर के खर्च की हर स्तर पर निगरानी की जाए।

सूत्रों की मानें तो कतर की नौसेना की ओर से इन पनडुब्बियों का अधिग्रहण दोहा स्थित लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अल-शमल-3 के द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रमुख बरजान होल्डिंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिर हसन अल नईमी हैं जिन्होंने एम23 में काफी निवेश किया। उपरोक्त सभी लेन-देन मई 2020 तक पूरे किए गए थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन दो पनडुब्बियों पर आठ भारतीयों सहित दाहरा ग्लोबल के कर्मचारी कैसे और किस क्षमता में काम कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के नम्र समर्पण ने भारत को विश्वगुरु बनाने के उनके लंबे दावों की पोल खोल दी है। भारत और कतर 2023 में राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा भारतीय, कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर में अपने समकक्ष को फीफा विश्वकप की शुभकामनाएं भेजीं, लेकिन हमारे बहादुरों के कीमती जीवन को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में इस मामले को बहुत ही संवेदनशील बताया था। गत वर्ष भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वालों में कतर पहला देश था। कतर ने उस वक्त इस मुद्दे पर भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। भारतीय राजदूत को समन किया था।

भारत ने गत वर्षों में कतर के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी कुछ किया है। कतर में लगभग 7 लाख प्रवासी भारतीय हैं। उनमें कई बड़े कारोबारी भी हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काफी इन्वेस्ट किया है। उन्होंने तीन वर्षों में कतर की चार यात्राएं की हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार **अजीत डोभाल** भी कतर जा चुके हैं। गत नवंबर में फीफा विश्वकप के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच 15 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार बताया गया है। इसके अलावा भारत और कतर, दोनों मुल्कों की नौसेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास करती हैं। यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2008 में कतर की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2016 में दोहा गए थे। इस बीच 2015 में कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत आए थे। साल 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कतर का दौरा किया था। पिछले साल पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कतर की यात्रा की थी।

● **कुमार राजेंद्र**

9 महीने बाद भी आरोपों के बारे भी नहीं बताया

कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। हालांकि इसमें भी कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है। यह पूछे जाने पर कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस साल जनवरी में अपनी वीकली ब्रीफिंग में कहा था कि यह सवाल कतर के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कतर के अधिकारियों ने आरोपों के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि कतर ने उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक सवाल के जवाब में दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया था कि यह एक संवेदनशील मामला है। उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता में शामिल है। राजदूत और सीनियर अफसर कतर सरकार के संपर्क में हैं। 8 दिसंबर 2022 को दिए गए इस बयान को 5 महीने का समय हो चुका है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी के बाद से अब तक 8 बार इन लोगों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पूर्व नौसेना अफसर पूर्णेन्दु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने मानवीय आधार पर कतर सरकार से 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा करने की अपील की थी। मीतू ने 15 मार्च को ट्वीट कर कहा था कि ये सभी उम्रदराज रिटायर्ड नौसेना कर्मी एकांत कारावास में रहने के चलते मानसिक रूप से टूटने की स्थिति में हैं।

> *कोरोना संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण के लिए केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी, लेकिन मप्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों के कारण यह योजना एक साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई।*

अनाथों को नहीं मिला 'वात्सल्य'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी, लेकिन मप्र में अफसरों की भर्राशाही और लापरवाही के कारण अनाथ बच्चों को वात्सलय नहीं मिल पाया। यानी प्रदेश में यह योजना एक साल बाद भी लागू नहीं हो पाई है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4 हजार रुपए प्रदान किए जाने हैं। इसके अलावा नई योजना में 6 हजार हर महीने रहन-सहन के लिए भी बच्चों को प्रदान किए जाने हैं। अब संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने मिशन वात्सल्य को एक साल बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

जानकारी के अनुसार पूर्व में संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को नए प्रावधान के साथ भारत सरकार ने एक अप्रैल 2022 से देशभर में लागू कर दिया था। साथ ही केंद्र ने बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन मप्र महिला बाल विकास के अफसर इसे एक साल बाद भी लागू नहीं कर पाए हैं। खास बात यह है कि मिशन वात्सल्य को लागू करने में महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी गुमराह कर दिया है। महिला बाल विकास के अधिकारियों की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सालभर से आईसीपीएस योजना के तहत कार्यरत 600 कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला है। प्रदेश में किशोर न्याय बोर्ड, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को 7 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 5000 से अधिक अनाथ, बेसहारा बच्चों के भोजन, कपड़े एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी केंद्र सरकार ने बजट प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर 3 हजार किया है, लेकिन मप्र में यह लाभ भी बच्चों को नहीं दिया गया है।

समाज के बेसहारा, अनाथ, बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य अन्य राज्यों में लाभकारी साबित हो रहा है। लेकिन मप्र में नौकरशाहों ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने भी बगैर तथ्यों को जांचे, परखे इस संवेदनशील मामले में मप्र के करीब 10 हजार अनाथ, बेसहारा बच्चों के हक पर ताला लगा दिया। दूसरी तरफ गैर भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान पिछले साल ही इसे लागू कर चुके हैं। मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल देखरेख संस्थाओं, दत्तक ग्रहण एजेंसियों के लिए नए नार्म्स एवं वित्तीय प्रावधान लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने तो बच्चों के कल्याण के लिए अपनी तरफ से राशि मप्र सरकार को उपलब्ध करा दी लेकिन एक वित्तीय वर्ष की यह बढ़ी हुई राशि आखिर अब किस मद में खर्च की जाएगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 के स्थान पर 1 अप्रैल 2023 से लागू करने के आदेश दे दिए हैं।

मिशन वात्सल्य केंद्र और राज्य की 60:40 वित्तीय भागीदारी पर आधारित योजना है। यानी इसका 60 फीसदी अनुदान मप्र को केंद्र ने अप्रैल 2022 से जारी कर दिया, लेकिन मप्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर बीते वित्तीय साल में राज्य हिस्से का 40 फीसदी अनुदान नहीं दे पाए थे। अब संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने मिशन वात्सल्य को एक साल बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में पिछले साल अप्रैल 2022 में केंद्र से मिली 60 प्रतिशत की राशि अनाथ, बेसहारा बच्चों के नाम पर खर्च करने के बजाय कहां खर्च की गई, इस पर भी सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री एक तरफ हर संभव कोशिश करते हैं कि प्रदेश में बच्चों के कल्याण में कोई कसर नहीं रहे। सबसे पहले कोरोना में अनाथ बच्चों का पुनर्वास हो या मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने अनाथ, गरीब बेसहारा बच्चों के लिए दरियादिली दिखाई और नियमों को शिथिल किया लेकिन महिला बाल विकास के अफसर इस मामले में वित्त विभाग के आगे मुंह सीलकर बैठ गए हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

सालभर चुप बैठा रहा विभाग

मिशन वात्सल्य के कर्मचारियों के वेतन एवं संपूर्ण योजना के घटक जैसे- बाल देखरेख संस्थान, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर के मद में केंद्र से बढ़े मानदेय-बजट देने की फाइल को वित्त विभाग ने इस टीप के साथ विभाग को पिछले महीने लौटा दिया है कि भूत लक्षी प्रभाव से यानी 1 अप्रैल 2022 से इसे दिया जाना संभव नहीं है। सवाल यह है कि जब केंद्र ने सालभर पहले इसे लागू कर दिया तो महिला बाल विकास सालभर तक चुप क्यों बैठा रहा। इसके पीछे वित्त विभाग का तर्क है कि भारत सरकार ने मिशन वात्सल्य के तहत जिलों की संख्या कम करने को कहा था। वित्त विभाग 1 अप्रैल 2023 से मिशन वात्सल्य लागू करने की बात कह रहा है, लेकिन अप्रैल 2022 से जारी बजट का क्या होगा इसका कोई जवाब विभाग के पास नहीं है। देशभर में मिशन वात्सल्य 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, राजस्थान समेत अन्य राज्यों ने मिशन वात्सल्य का नई गाइडलाइंस के अनुरूप क्रियान्वयन भी जारी है।

बैकफुट पर लाल आतंक

एक के बाद एक कुल 8 हार्डकोर नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने से नक्सली न सिर्फ बैकफुट पर हैं, बल्कि उनके हौंसले पस्त हैं। जिला बल और हाक फोर्स की सटीक योजना, बल संख्या में बढ़ोतरी और लाल आतंक को किसी भी कीमत पर सिर न उठाने देने का जज्बा बालाघाट पुलिस की सफलता का कारण बन रहा है। जवानों ने बीते 16 महीनों में 1.30 करोड़ रुपए के ईनामी नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही सर्चिंग पार्टी को नुकसान पहुंचाने या अपनी दहाशत दिखाने जमीन के अंदर डंप की गई विस्फोटक सामग्रियों को बरामद कर उनके मंसूबों को ध्वस्त किया है। वहीं, गत दिनों तड़के गढ़ी के कदला के जंगल में हुए एनकाउंटर में सरिता और सुनीता नामक दो नक्सली महिलाएं मारी गईं, जिन पर 14-14 लाख का ईनाम था।

पुलिस जानकारी के अनुसार, कदला के जंगल में पुलिस व हाक फोर्स पार्टी पर फायरिंग करने वाले नक्सलियों के खिलाफ गढ़ी थाना में अपराध दर्ज किया गया है। मुठभेड़ मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 16 नक्सलियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनमें खटिया मोचा दलम व विस्तार दलम के नक्सली सदस्य हैं। नामजद नक्सलियों में राकेश ओडी, प्रशांत, एडमा उर्फ नवीन सहित अन्य 16 नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि महिला नक्सली सरिता और सुनीता के स्वजनों को घटना की सूचना दे दी गई थी। पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि नक्सली सरिता छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के ग्राम जोनागुडेम निवासी थी और सुनीता सुकमा जिले के ही जगरगुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम नागराम की निवासी थी।

16 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 20 जून 2022 को कादला के ही जंगल में हुई मुठभेड़ में कमांडर इन चीफ नागेश उर्फ राजू तुलावी, एरिया कमेटी मेंबर मनोज और महिला नक्सली रामे मारी गई थी। तीनों नक्सलियों पर मप्र सहित छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों में कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 30 नवंबर 2022 को गढ़ी क्षेत्र के सुपखार रेंज के जामसेहरा जंगल में बालाघाट और मंडला की संयुक्त कार्रवाई में जीआरबी डिवीजन के डिवीजन कमेटी मेंबर और प्रभारी गणेश मेरावी, भोरमदेव दलम का एरिया कमेटी मेंबर राजेश को मार गिराया गया था। दोनों पर 43 लाख का इनाम था। 18 दिसंबर 2022 को मलाजखंड के पाथरी चौकी अंतर्गत हर्राटोला जंगल में जवानों ने कान्हा भोरमदेव के सक्रिय नक्सली कबीर उर्फ सुरेंद्र के गार्ड रूपेश को मार गिराया था। रूपेश पर 12 लाख रुपए का ईनाम था। 22 अप्रैल 2023 को गढ़ी थाना क्षेत्र के कदला जंगल में हाक फोर्स, पुलिस व सीआरपी के जवानों ने नक्सलियों द्वारा की गई फायरिंग का जवाब देते हुए महिला नक्सली सरिता व सुनीता को मार गिराया।

नक्सली सरिता व सुनीता के पुलिस से प्राप्त अपराध रिकार्ड में दोनों के खिलाफ बैहर थाना क्षेत्र में हत्या का मामला पंजीबद्ध है। उनके खिलाफ 13 नवंबर 2022 को यह मामला पंजीबद्ध हुआ था। यह वह समय है जब नक्सलियों ने बैहर क्षेत्र के ग्राम मालखेड़ी आकर मुखबिरी के शक पर संतोष और जगदीश की हत्या की थी। इस घटना को नक्सलियों ने रंजिश के तौर पर अंजाम दिया था, क्योंकि 6 नवंबर 2021 को मालखेड़ी में ही पुलिस ने 8 लाख रुपए की ईनामी महिला नक्सली शारदा उर्फ पुज्जे को एनकाउंटर में मार गिराया था। नक्सली शारदा की मुखबिरी करने के शक पर संतोष व जगदीश की हत्या की थी। इससे पहले 27 जून 2021 को उकवा के बिठली चौकी अंतर्गत बम्हनी निवासी भागचंद अड़मे की भी नक्सलियों ने मुखबिरी के शक पर हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ का कहना है कि गढ़ी क्षेत्र के कदला के जंगल में अलग-अलग पार्टी ने सर्चिंग की है। एनकाउंटर के बाद जिला पुलिस व हाक फोर्स अलर्ट मोड पर हैं।

● **राजेश बोरकर**

नक्सलियों से निपटने हाई पावर यूनिफाइड कमेटी

मप्र में नक्सली आतंक पर नकेल कसने की कवायद तेज हो गई है। नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने और रोक लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा इस कमेटी के उपाध्यक्ष रहेंगें। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए डेवलपमेंट कोर ग्रुप का भी गठन किया गया है। मप्र में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूनिफाइड कमांड बनाई गई है। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कमेटियां प्रस्ताव तैयार करेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए आदेश जारी किए हैं। यूनिफाइड कमांड कमेटी कानून व्यवस्था, सुरक्षा के मुद्दे पर स्थिति, नक्सल प्रभावित इलाके में विकास कार्यों की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें उपाध्यक्ष हैं। यूनिफाइड कमांड में मुख्य सचिव (सदस्य), पुलिस महानिदेशक मप्र (सदस्य सचिव) अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव वित्त (सदस्य), अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव (गृह) (सदस्य), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल (सदस्य), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता मप्र (सदस्य), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-पुलिस महानिरीक्षक नक्सल विरोधी अभियान (सदस्य), सचिव जनसंपर्क, संयुक्त निदेशक सूचना ब्यूरो, पुलिस महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सदस्य) है। यूनिफाइड कमांड की हर साल 2 बार बैठक आयोजित की जाएगी।

न मजदूरी मिल रही, न काम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी की गारंटी है। ताकि ग्रामीणों को मजदूरी के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़े, लेकिन मजदूरों को पहले तो काम ही नहीं मिलता। यदि काम मिल भी जाए तो उनको समय से मजदूरी नहीं मिल पाती। जिससे मजदूर परेशान रहते हैं। ऐसे में मजदूर गांव में रोजगार नहीं मिलने के कारण शहरों में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत छोहरी के जीवनदास चौधरी अर्द्ध कुशल मजदूर हैं। इन्होंने राज मिस्त्री के तौर पर मनरेगा के अंतर्गत काम किया। वे बताते हैं कि एक साल से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।

जानकारों का कहना है कि रोजगार सहायकों द्वारा प्रदेशव्यापी की गई हड़ताल से भी मनरेगा के काम प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरों के मस्टर पंचायत के लोग कागजों में भर लेते हैं और उनके नाम से पैसा निकाल लेते हैं। सरपंच, सचिव खुद के कमीशन के लालच में मशीन चला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में खुलेआम भ्रष्टाचार मचा हुआ है जिससे मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते मजदूर बेरोजगार बने हुए हैं साथ ही सरकारी कार्यालयों में अराजकता भी बढ़ रही है और लोग पलायन पर मजबूर है।

एक जीआरएस ने बताया कि लाड़ली बहना योजना में बहनों के फार्म भरने के काम में लगे होने से भी कार्यों की मॉनीटरिंग नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार 13,94,953 कार्य पिछले 3 सालों से प्रगतिरत हैं। वर्ष 2022-23 में 8,81,801 नए कार्य लिए गए। इस तरह कुल 22,76,754 कार्य हुए। इनमें अभी तक 10,34,818 (45.45 प्रतिशत) पूरे हुए हैं और 12,41,936 कार्य प्रगतिरत हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में 12,540 अमृत सरोवर चिह्नित किए गए हैं। इनमें अभी तक 921 कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए। जबकि 5,739 कार्य प्रगतिरत हैं। महज 1,415 कार्य ही 10 अप्रैल 2023 तक पूरे होना बताया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 15 दिन में मजदूरी भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तय नियमों के तहत अगर 15 दिन में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो मजदूरों द्वारा जितने दिनों काम किया गया है उस मजदूरी का 0.05 फीसदी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। मजदूरों को यह क्षतिपूर्ति देने के बाद शासन संबंधित दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों से इस राशि की रिकवरी करती है। विधानसभा में विलंबित मजदूरी का मामला उठने के बाद आनन-फानन में अब प्रदेश के सभी जिलों में मजदूरों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के आदेश आयुक्त मनरेगा ने दिए हैं। मनरेगा में अब काम भी नहीं मिल रहा है, जिससे गांव के बाहर मजदूरी करने की मजबूरी हो गई है। प्रदेश के सभी 52 जिलों के 75 लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों को अभी मजदूरी मिलने का इंतजार है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल का करीब 640 करोड़ रुपए मजदूरी और सामग्री का भुगतान अटका है। इस राशि के लिए राज्य सरकार केंद्र का मुंह देख रही है। मजदूरी नहीं मिलने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। गत वर्ष 45 लाख 29 हजार 519 परिवारों के 75 लाख 73 हजार 576 व्यक्तियों को ही मनरेगा में काम मिला। इनमें 100 दिन का काम सिर्फ 94,971 परिवारों को मिला। जबकि 22 करोड़ 66 लाख 27 हजार से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए। वर्ष 2022-23 में प्रति परिवार औसतन 50 दिन का काम मिला।

मनरेगा में विकास कार्य प्रभावित होने और मजदूरी का समय पर भुगतान प्रभावी नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण डीबीटी को लेकर सामने आया है। अनूपपुर जिले के एक रोजगार सहायक ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि केंद्र सरकार मजदूरी का भुगतान डीबीटी यानि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से कर रही है। डीबीटी के हर मजदूर का बैंक में आधार लिंक होना आवश्यक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (प्रत्यक्ष लाभ भुगतान) सरकार द्वारा अनेक योजनाओं में लाभार्थियों के लिए किया जाता है। यह तत्काल भुगतान व्यवस्था है और इसमें बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है। इसका उद्देश्य सीधे लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करना है। इससे सीधा फायदा लाभार्थी को मिलता है। अनूपपुर जिले के नवागत सीईओ मनरेगा, एस. कृष्ण चैतन्य से मनरेगा में कार्यों की स्थिति, मजदूरों और सामग्री के अटके भुगतान तथा केंद्र से राशि उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर कई बार संपर्क किया गया। उन्हें सूचना भी दी गई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।

● **बृजेश साहू**

मप्र में सबसे कम मजदूरी

केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना की दरों में बदलाव किए हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब प्रतिदिन काम करने पर मिलने वाली राशि बढ़कर मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा किए गए मजदूरी की नई दरों में बदलाव एक अप्रैल से देशभर में लागू हो गई है। केंद्र की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, मजदूरों के वेतन में 7 से लेकर 26 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नई मजदूरी दरों के मुताबिक राजस्थान में पिछले साल की तुलना में इसमें सबसे अधिक वृद्धि की गई है। राजस्थान के मजदूरों के लिए संशोधित वेतन 255 रुपए प्रतिदिन है, जो वर्ष 2022-23 में 231 रुपए था। वहीं प्रदेश में संशोधित वेतन 221 रुपए प्रतिदिन किया गया है, जो वर्ष 2022-23 में 204 रुपए था। हरियाणा में मजदूरों को मनरेगा से तहत सबसे अधिक 357 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। एक ओर हरियाणा और राजस्थान में दैनिक मजदूरी दर सबसे ज्यादा है, तो वहीं मप्र और छत्तीसगढ़ में यह दर कम है। इन राज्यों में मजदूरों को 221 रुपए दैनिक मजदूरी के रूप में मिलेगी। वहीं, बिहार और झारखंड की बात करें तो यहां पिछले साल के मुकाबले मजदूरी की दरों में इजाफा किया गया है। बिहार में 210 रुपए और झारखंड में 228 रुपए 8 प्रतिशत बढ़कर की गई है। मजदूरी की दरों में सबसे कम इजाफा कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर में किया गया है। मनरेगा के तहत देशभर में हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान जैसे कई राज्यों ने रोजगार दिवस में इजाफा किया गया है। हरियाणा में मजदूरों को मनरेगा से तहत सबसे अधिक 357 रुपए प्रतिदिन मिलेगा जो कि पहले 331 रुपए थे। राजस्थान में मजदूरी दर 231 रुपए से बढ़ाकर 255 रुपए किया गया है। वहीं मप्र और छत्तीसगढ़ में 221 रुपए प्रतिदिन किया गया है, जो पहले 204 रुपए था। बिहार और झारखंड में दैनिक मजदूरी दर 210 रुपए से बढ़ाकर 228 रुपए किया गया है।

नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के उदय की गवाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों को सम्मानित किया। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और हवन और पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने संसद भवन में सेंगोल स्थापित कर 20 पंडितों से आशीर्वाद लिया। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन-जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह नई संसद आत्मनिर्भर भारत के उदय की गवाह बनेगी। उन्होंने कहा कि नया भारत आज नया लक्ष्य तय कर रहा है।

देश की प्राचीन संस्कृति के साथ मौजूदा वक्त की जरूरतों के हिसाब से बना नया संसद भवन आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ संगम है। नया संसद भवन एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। इस नए भवन के लिए प्रयुक्त सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों से मंगवाई गई है। नए संसद भवन के निर्माण में देश के करीब-करीब हर प्रांत की विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग किया गया है। एक तरह से लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए पूरा देश एक साथ आया। नए संसद भवन में प्रयुक्त सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगवाई गई जबकि लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से मंगवाया गया था। लाल किला और हुमायूं के मकबरे में भी इस बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। केशरिया हरा पत्थर उदयपुर से, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से और सफेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से मंगवाया गया है।

लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में फाल्स सीलिंग के लिए स्टील की संरचना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगाई गई है जबकि नए भवन का फर्नीचर मुंबई में तैयार किया गया था। इमारत पर लगी पत्थर की जाली का काम राजस्थान के राजनगर और नोएडा से मंगवाया गया था। अशोक प्रतीक के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से मंगवाई गई थी। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों की विशाल दीवारों पर अशोक चक्र और संसद भवन के बाहरी हिस्से में लगी सामग्री को इंदौर से लाया गया था। नई संसद भवन के निर्माण में काम आने वाली रेती-रोड़ी (एम-सैंड) हरियाणा के चरखी दादरी से मंगवाई गई थी। एम-सैंड को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण बड़े कठोर पत्थरों यानी ग्रेनाइट को पीसकर किया जाता है। वैसे निर्माण में काम आने वाला रेत आमतौर पर नदी से निकाला जाता है। निर्माण में उपयोग की जाने वाली फ्लाई ऐश ईंटें हरियाणा और उप्र से मंगवाई गई थीं जबकि पीतल के काम के लिए अहमदाबाद से सेवाएं ली गईं।

त्रिकोणीय आकार के चार मंजिला नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्र करीब 64,500 वर्ग मीटर है। जिसमें कुल छह द्वार हैं। इसमें तीन मुख्य द्वार हैं- ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें वीआईपी, सांसद और आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार होंगे। लोकसभा कक्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर की अद्भुत कलाकृति तो राज्यसभा कक्ष में राष्ट्रीय पुष्प कमल की कलाकृति सदन के सौंदर्य को निखार रही है। करीब 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बने नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के तो राज्यसभा कक्ष में 345 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हाल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है।

देश के नए संसद भवन की अनेकों खूबियां हैं। नए संसद भवन को फूलप्रूफ साइबर सिस्टम से लैस किया गया है। जिन विशेषज्ञों ने इस सिस्टम को तैयार किया है, उन्होंने इसे स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया है। यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में अत्याधुनिक सुरक्षा घेरा। इस सिस्टम को प्रो एक्टिव साइबर सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। नए संसद भवन में चीन, पाकिस्तान सहित अन्य किसी भी देश के हैकर्स सेंध नहीं लगा सकते। इतना ही नहीं, संसद भवन का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि वह साइबर अपराध की काली दुनिया डार्क वेब, जिसे इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है, को पार्लियामेंट के आईटी सिस्टम के निकट भी नहीं फटकने देगा।

● **राकेश ग्रोवर**

नए संसद भवन में लगा डबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम

नए संसद भवन में फूलप्रूफ साइबर सिस्टम को तैयार करने वाली टीम के सूत्रों का कहना है कि कोई भी हैकर, यहां के उपकरणों में सेंध नहीं लगा सकता। यही वजह है कि इसे स्टेट ऑफ आर्ट कहा गया है। संसद भवन के हर कोने में डिजिटल सर्विलांस का घेरा रहेगा। इसमें आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए डबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है। संसद भवन में इंटरनेट एक्ीकृत नेटवर्क के अलावा एयर-गैप्ड कम्प्यूटर तकनीक भी रहेगी। एयर-गैप्ड कम्प्यूटर, मौजूदा नेटवर्क से जुड़े उपकरणों के साथ वायरलेस या भौतिक रूप से कनेक्ट नहीं हो सकता। एयर गैप कम्प्यूटर सिस्टम के जरिए डेटा को मैलवेयर और रैनसमवेयर से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। इसे इंट्रानेट यानी बाकी नेटवर्क से अलग सिस्टम भी कहा जाता है। नए संसद परिसर में सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) द्वारा वाईफाई पर 2,500 इंटरनेट नोड्स के उपकरणों पर नजर रहेगी। इसके अलावा 1,500 एयरगैप्ड नोड्स और 2,000 उपकरणों का नेटवर्क, इन सबकी कार्यप्रणाली पर केंद्रीयकृत तरीके से सर्विलांस हो सकेगी।

पर्यटकों को फैन बना रहे बाघ

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बजरंग की छलांग ने सफारी में गए पर्यटकों को अपना फैन बना लिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बजरंग बाघ पर्यटकों की पसंद तो है, लेकिन बजरंग की छलांग ने पर्यटकों को अपना दीवाना बना लिया। पर्यटकों ने उस छलांग का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केवल बजरंग ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश बाघों के स्वभाव में बदलाव आ रहा है। टाइगर रिजर्व में बाघ पर्यटकों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे पर्यटकों की गाड़ी के पास आने से भी नहीं कतरा रहे हैं।

बाघों के व्यवहार में हो रहे इस बदलाव का खुलासा भी वन विभाग की मॉनीटरिंग में हुआ। अब इस गंभीर विषय पर बारीकी से पड़ताल के लिए वन विभाग ने शोध शुरू किया है। टाइगर रिजर्व समेत राजधानी भोपाल के अर्बन बाघ पर रिसर्च की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अच्छी बात यह है कि बाघ के बदलते स्वभाव में चिड़चिड़ापन या आक्रामकता नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व के बाघों की अपेक्षा भोपाल के टाइगर्स का स्वभाव अलग तरीके से विकसित हो रहा है। जिन संसाधनों का मानव उपयोग करते हैं उनका बाघ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते 10-12 सालों में यह परिवर्तन तेजी से दिखाई दिया है।

अब तक के रिसर्च में पाया गया है कि बाघ शोर-शराबे से दूर रहते हैं। लेकिन अब शोर या तेज आवाज को भी बाघों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जंगलों के स्थान रहवासी क्षेत्र से लगे वन क्षेत्रों में मानव दखल भी बढ़ा है। भोपाल में शहरी क्षेत्र में बाघों की आमद लगातार दर्ज करते हैं। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और विभागीय अमले में बढ़ोतरी के कारण बाघों से मानव का सामना सर्वाधिक होता है। लिहाजा बाघ भी अब संवेदनशील होते जा रहे हैं। बाघों के स्वभाव पर अध्ययन करने के लिए वन विभाग ट्रैप कैमरों का सहारा ले रहा है। अमूमन वहां ट्रैप कैमरे लगाए गए जहां बाघ मूवमेंट अधिक होता था। अब रास्तों, पर्यटक के स्थान, कोर और बफर जोन समेत बाघ संभावित सभी क्षेत्रों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुराने वीडियो और फोटो डाटा के आधार पर अध्ययन किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व के साथ ऐसे रहवासी क्षेत्र यहां बाघों का मूवमेंट एरिया अध्ययन का प्रमुख आधार है। इसमें देखा गया है कि पहले मानवीय हलचलों के कारण तत्काल बाघ मूवमेंट करते थे। लेकिन अब घंटों तक उसी स्थान पर दिखाई देते हैं।

बाघों के शिकार का तरीका भी बदल रहा है। रहवासी क्षेत्र के पास के क्षेत्रों में बाघों के शिकार के मामलों में वृद्धि हुई है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बीते 7 सालों में बाघ नाइट हंटिग 65 प्रतिशत बढ़ी है। अध्ययन का यह बिंदु भी बेहद महत्वपूर्ण है। टाइगर रिजर्व, अभयारण्यों में गश्ती दल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह हुआ कि बाघों को सर्च लाइट से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। भोपाल के शहरी सीमा क्षेत्रों में ऐसा देखा गया। रिसर्च में बाघों के आसपास लोगों की एक्टिविटी को आधार बनाया गया है। इस पॉइंट में बाघों की फोटो खींचते, शिकार करते या खाते समय, बाघ वाटर एक्टिविटी को केंद्रित किया गया है। इसमें देखा जाएगा कि आखिर ऐसी स्थिति में बाघों के रिएक्शन में कितना बदलाव आया है। जंगल हों या अर्बन एरिया में बाघ। शावकों के साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले बाघों के तथ्यों पर अध्ययन किया जा रहा है। शावकों के साथ बाघिन के स्वभाव में परिवर्तन पर पहले भी शोध हो चुके हैं। अब पाया है कि बाघिन निर्भीक होकर शावकों के साथ विचरण करती है। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल के शहरी सीमा क्षेत्र में लगे वन क्षेत्रों में अधिकतम 22 बाघों का मूवमेंट देखा गया है। यह भी कहा जा सकता है कि राजधानी में 18 बाघों का स्थाई मूवमेंट होता है। इन बाघों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कराई गई थी। इसमें अर्बन बाघ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक किया गया था। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि भोपाल बाघ कलियासोत, केरवा, समरधा समेत अन्य क्षेत्रों में ट्रैफिक, लाइट की समझ को जानते हैं। एक निश्चित समय में सड़कों को पार करते हैं। बाघ भी संबंधित मूवमेंट एरिया में अर्बन एक्टिविटी की मॉनीटरिंग करते हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

ह्यूमन एक्टिविटी के आदी हुए बाघ

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोगों की आवाजाही से भोपाल को फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सतपुड़ा, पेंच, कान्हा के बाघ भी समय के साथ इस आवाजाही, शोर, ह्यूमन एक्टिविटी के आदी हो चुके हैं। यह भी बताया गया कि बाघ के समीप होने पर बाघ आक्रामकता के मामलों में 70 फीसदी की कमी आई है। जो मानव-बाघ के बीच बेहतरीन तालमेल को साफतौर पर उजागर करता है। मप्र के टाइगर रिजर्व में शामिल कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-दुबरी में रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा सागर के नौरादेही, रायसेन के रातापानी अभयारण्य में रिसर्च की जा रही है। अर्बन क्षेत्रों में भोपाल, उमरिया और मंडला को शामिल किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस रिसर्च में एक साल से भी अधिक का समय लग सकता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन विभाग, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, बाघ मित्रों की रिसर्च में मदद ली जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बाघ संरक्षण की नई नीति और रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी भेजी जाएगी। ताकि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक संशोधन या नए नियमों का प्रावधान किया जा सके।

बुंदेलखंड में सजी चौसर

बुंदेलखंड से निकलेगी सत्ता की राह

बुंदेलखंड कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, आज हालात ये हैं कि बुंदेलखंड की एक-एक सीट पाने के लिए कांग्रेस को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों पर हार-जीत का समीकरण ही अब प्रदेश में सत्ता की चाभी बन गया है। यही कारण है 2018 के चुनाव से ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह के दौरे के पहले यहां उनके पुत्र जयवर्धन सिंह भी दौरा कर चुके हैं और कमलनाथ भी दौरा कर चुके हैं। भाजपा भी अपने चुनावी अभियान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मंडल बूथ और पन्ना प्रमुख की तैयारी के बाद अब भाजपा के संगठन स्तर पर कसावट का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा की पिछले दिनों खजुराहो में हुई एक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साफ संकेत दिए गए कि पार्टी को अपने अनुभव का लाभ दें और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इशारा साफ है कि पार्टी बड़े स्तर पर परिवर्तन की ओर बढ़ रही है।

2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए भाजपा और कांग्रेस कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा चुनाव के सालभर पहले से चल रहे राजनीतिक अभियान को देखकर लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद हाल ही में बुंदेलखंड इलाके में दिग्विजय सिंह की एंट्री के बाद चुनावी जोड़तोड़ अभियान तेजी पकड़ेगा। बुंदेलखंड इलाके के सागर संभाग में 26 विधानसभा और 4 संसदीय सीटें आती हैं। जिनमें कांग्रेस 2018 के चुनाव में तमाम सकारात्मक राजनीतिक हालात के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी थी। इस बार भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुंदेलखंड की कमान संभाली है। अब वे कांग्रेसियों को मंत्र दे रहे हैं कि डरो नहीं लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। सुप्त कांग्रेस को संजीवनी देने आए दिग्विजय सिंह सफल होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ भाजपा के संगठन ने अपने नेताओं को जो संदेश दिया है उससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है।

बुंदेलखंड के सागर संभाग के सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना जिले की 26 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 7 और बसपा के पास एक 18 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सागर जिले में सर्वाधिक 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 8 में से 6 पर भाजपा का कब्जा है। यहां के 6 विधायकों में से 3 मंत्री हैं, पिछले 40 साल से रहली सीट पर चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव, खुरई से भूपेंद्र सिंह और ज्योतरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए सुरखी के गोविंद सिंह राजपूत प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री हैं। दरअसल सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस जोड़ो अभियान की शुरुआत की। अजा के लिए सुरक्षित इस विधानसभा सीट पर पिछले 25 सालों से भाजपा का कब्जा है, यहां के वर्तमान विधायक महेश राय 2018 का चुनाव मात्र 460 मत से जीते थे। बीना और खुरई विधानसभा सीट अशोकनगर से लगी हुई होने के कारण यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। सियासत के जानकार लोगों को यह बात अच्छे से पता है कि सिंधिया घराने से दिग्विजय की पुरानी अदावत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण उतरने वाले शशि कथोरिया ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली थी। इस बार यहां से भाजपा शशि कथोरिया को टिकट दे सकती है। खुरई में दिग्विजय सिंह का 4 माह में यह दूसरा दौरा है, 17 दिसंबर 2022 को वे यहां आए थे। उस समय वे पीड़ित और प्रताड़ित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले थे। खुरई के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे के पार्टी छोड़ने के बाद से यहां कांग्रेस के पास कोई सशक्त प्रत्याशी नहीं है जो भूपेंद्र सिंह का मुकाबला कर सके। असल में अरुणोदय चौबे की प्रताड़ना के बाद भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया था। जिसके चलते इस इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां बुरी तरह से हतोत्साहित हुआ। आज जब चुनाव सर पर हैं तो कांग्रेस के आला नेता कार्यकर्ताओं का दुख-दर्द बांट रहे हैं, उनके सुख-दुख में साथ रहने की बात कह रहे हैं।

अब दिग्विजय सिंह ने विधानसभा सीट के मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनको एकजुट करने और उनको संजीवनी देने का प्रयास किया। हर जगह वे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला, उनके निशाने पर सागर जिले के तीनों मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह और गोपाल भार्गव थे। मंत्रियों पर दादागिरी के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी किसी की नहीं हुई, भगवान से तो डरो। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सताने और और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने मुख्यमंत्रीकाल की भी याद दिलाई। वे आपातकाल का जिक्र करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि राघौगढ़ क्षेत्र में कई लोगों को जेल जाने से हमने बचाया। कार्यकर्ताओं से भी कहा कि डरो नहीं लड़ो, अगर किसी से शिकायत नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं। गोविंद राजपूत के भाजपा में आने के बाद वे बिगड़ गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से यह जानना चाहते थे कि क्या वजह है कि एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा सागर जिले की सागर, बीना, नरयावली, रहली और खुरई विधानसभा सीट वर्षों से हम हार रहे हैं? उन्होंने फर्जी वोटरों के जुड़ने पर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि वे बूथ स्तर पर जांच करें और फर्जी वोटरों के नाम कटवाएं। वे लगभग हर बैठक में अपने को आम कार्यकर्ता प्रदर्शित करने का प्रयास करते रहे और कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठे।

दिग्विजय सिंह सागर जिले में शोषण, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बात तो करते रहे किंतु बुंदेलखंड के किसानों की समस्या पर उन्होंने एक तरह से मौन साध लिया। जबकि बुंदेलखंड के किसान इन दिनों ओला और पानी से फसलों की हुई बर्बादी को लेकर दुखी है। सियासत में अगर तात्कालिक मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाए तो यह पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस यह सब करती रही है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। बुंदेलखंड में कांग्रेस के नेता ही एक-दूसरे को हराते-हराते इतने नीचे पहुंच गए कि उसे अपने वजूद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पढ़ रहा है। वह आज भी इस आशा में है कि लोगों की भाजपा से बढ़ती नाराजगी उसकी जीत की वजह बनेगी। खुद दिग्विजय सिंह यह बात स्वीकारने में संकोच नहीं करते कि सागर में संगठन कमजोर है, कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए हम लोग आए हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

मप्र में हाईवोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू

तेरा काम... मेरा काम...

जनता किसको देगी ईनाम?

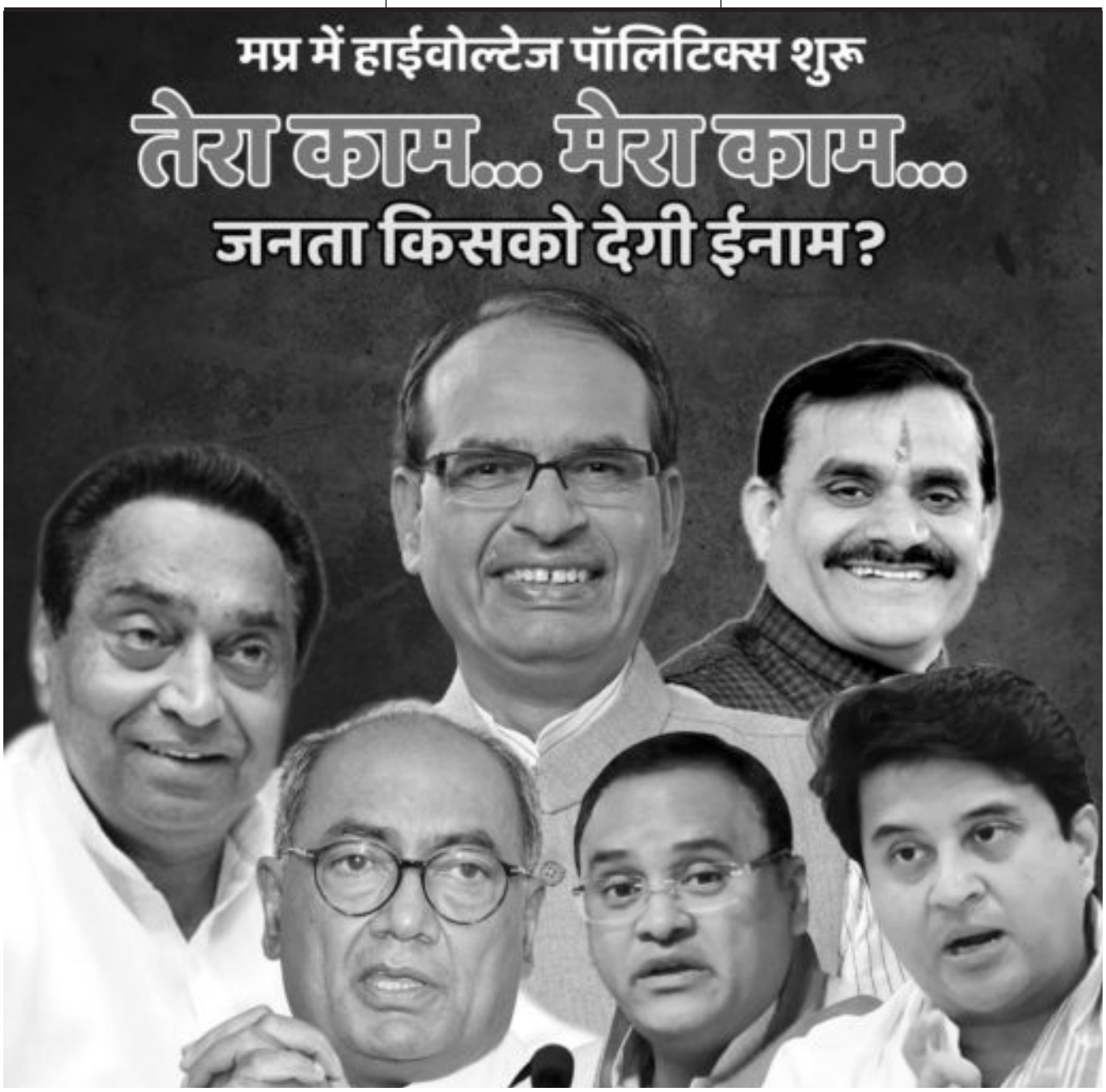

चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस में बगावत, भितरघात, वर्चस्व की जंग, क्षेत्रवाद और जातिवाद के कारण मप्र में हाईवोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रदेश में 200 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही भाजपा कई गुटों में बंट गई है। कांग्रेस के दावे के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा में बंट गई है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों में वर्चस्व की जंग इस कदर छिड़ गई है कि मंत्री एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। वहीं सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही कांग्रेस की भी स्थिति कमतर नहीं है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र के विधानसभा चुनावों में फिलहाल 5 महीने का वक्त बाकी है। चुनावी जंग के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके नेता गुटों में बंटे हुए हैं। कांग्रेस में तो गुटबंदी की परंपरा जन्मजात है। लेकिन भाजपा में यह इस बार चरम पर है। खासकर मप्र भाजपा में इस बार बगावत और भितरघात इस कदर है कि उन्हें खत्म करने के लिए आलाकमान और संघ भी लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बात थमने की बजाय तेजी से बढ़ रही है। इससे आलाकमान को डर सता रहा है कि हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब मप्र भी हाथ से न निकल जाए। सत्ता और संगठन में समन्वय की बात खूब हो रही है, लेकिन कहीं भी समन्वय नहीं दिख रहा है। कभी मुख्यमंत्री, तो कभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की हवा पार्टी के अंदर से ही बहाई जा रही है। जिससे कुलीनों के कुनबे में कलह साफ दिख रही है।

वैसे देखा जाए तो समर्थकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जबसे भाजपा में शामिल हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तबसे ही भाजपा में कलह तेज हो गई है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपदस्थ करने के लिए अभियान चलाया गया। शिवराज विरोधी नेताओं ने आपस में मुलाकात कर विद्रोह को भड़काने की कोशिश की, लेकिन संघ और आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद बात थम गई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह दूसरे को अध्यक्ष बनाने का अभियान चलाया गया। इन अभियानों के साथ ही पार्टी गुटों में बिखरती चली गई। उधर, पार्टी के मंत्रियों और विधायकों में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। तीन मंत्रियों वाले सागर में तो स्थिति इतनी विकट हो गई कि पार्टी के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने जिले के अन्य विधायकों के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि बाद में आलाकमान और संघ के हस्तक्षेप के बाद ये नेता चुप हो गए हैं। लेकिन इनके कलह के कारण पार्टी के कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। जिसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है।

पैसा, पावर और पॉलिटिक्स

मप्र भाजपा में वर्चस्व की जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे पैसा, पावर और पॉलिटिक्स बड़ी वजह मानी जा रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मार्च 2020 में जबसे सिंधिया समर्थकों के दम पर पार्टी की सरकार बनी है, वह दबाव में है। इस दबाव का नतीजा यह हुआ है कि सरकार में जहां बड़े और कमाऊ विभाग सिंधिया समर्थकों को दे दिए गए हैं, वहीं खांटी भाजपाईयों को सत्ता, संगठन से दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए इन नेताओं को महत्व क्या मिला, ये पैसा कमाने में इस कदर जुट गए कि उन्हें किसी की फिकर तक नहीं रही। वहीं वे अपना पावर भी खांटी भाजपाईयों पर दिखाने लगे। इससे भाजपा दो खेमों में नजर आने लगी है। एक है पुरानी भाजपा और दूसरी है नई भाजपा।

असमंजस में आलाकमान

मप्र में भाजपा आलाकमान तय नहीं कर पा रहा है कि विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रखते हुए लड़ना लाभदायक होगा या नहीं। शिवराज सिंह चौहान 2005 से लगातार सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। बीच में जब 2018 में भाजपा हार गई थी तब जरूर 15 माह के लिए कमलनाथ सूबे की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से भाजपा फिर सत्ता पर काबिज हो गई थी। पार्टी आलाकमान का एक धड़ा मानता है कि 2018 में पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ व्यवस्था विरोध के चलते हार का मुंह देखना पड़ा था। लिहाजा उन्हें कुर्सी पर रखते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने में जोखिम है।

भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर बगावत

मार्च 2020 में जिस बगावती फॉर्मूले को आधार बनाकर भाजपा ने सत्ता कब्जाई थी, अब वही फॉर्मूला उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में आए 28 विधायकों को जिस तरह महत्व दिया गया, उससे भाजपा कई गुटों में बंट गई है। उधर, पार्टी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों में वर्चस्व की जंग से भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस संदर्भ में संघ ने आलाकमान को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें भाजपा के कब्जे वाली 127 सीटों में से 60 पर बगावत की संभावना व्यक्त की गई है। गौरतलब है कि मप्र में पिछले एक माह से बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं ने बगावत कर कांग्रेस या अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया है। वहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर पार्टी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों में वर्चस्व की जंग देखी जा रही है। इससे भाजपा को बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसको लेकर संघ ने अपने फीडबैक के आधार पर भाजपा आलाकमान को रिपोर्ट दे दी है। आलाकमान को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें भाजपा और संघ के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक बगावत की आशंका जताई गई है। वर्तमान समय में भाजपा के पास जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, यानी ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, मालवा-निमाड़ में बगावत की संभावना जताई जा रही है। दरअसल, बगावत के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 3 सालों में सत्ता और संगठन ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को अधिक महत्व दिया गया है। इस कारण भाजपा दो भागों में बंट गई है। एक पुरानी भाजपा और दूसरी नई भाजपा।

वैसे, कांग्रेस के नजरिए से देखें तो वह सत्ता परिवर्तन को कर्नाटक की तरह ही तय माने बैठी है। एक तो भाजपा में गुटबाजी है। दूसरे, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी कम नहीं हैं। इसीलिए एक विकल्प यह भी है कि किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर चुनाव लड़ने से परहेज किया जाए। चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है तो आलाकमान भी सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से हिदायत मिली है कि सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा करें।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को खास तवज्जो देने का फरमान आया तो शिवराज सिंह चौहान को बैठक करनी पड़ी। मुद्दा था तो रणनीति बनाने का पर पहुंच गया सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल पर। इस बैठक से कुछ दिन पहले शिवराज सरकार के दो मंत्रियों गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत व तीन विधायकों ने आरोप लगाया था कि शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह उनके क्षेत्रों की विकास योजनाओं को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर भार्गव और राजपूत मुख्यमंत्री से भी मिले। आलाकमान ने अलग से इस गुटबाजी के बारे में राज्य संगठन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों अपनी अनदेखी से दुखी होकर पूर्व मंत्री दीपक जोशी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे सूबे के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं। पूर्व मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी अपनी सरकार की कार्यशैली की आलोचना कर चुके हैं।

राजनीतिक पार्टियों को अपनों से खतरा!

साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की प्रमुख पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि, चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक दलों को अपनों से ही खतरा है। भाजपा-कांग्रेस अपनों को मनाने की तैयारी में हैं, क्योंकि चुनावी साल में उनके अपने ही बाधक बन सकते हैं? बता दें कि चुनावी साल में एक इंटरनल सर्वे ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी को चिंतित कर दिया है। दरअसल, इस सर्वे में भाजपा और कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए कतार में खड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर वो बागी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस संभावित बगावत को देखते हुए ज्यादा चिंतित हो गई है। इसलिए कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर से जिला अध्यक्षों को इंटरनल पार्टी से जुड़ी हर बैठक में नाराज नेताओं को बुलाने के साफ निर्देश दिए हैं। वहीं सत्ताधारी भाजपा 2018 की तरह 2023 में न फंस जाए, इसलिए संघ और पार्टी के सीनियर नेता एक्टिव हो गए हैं। बता दें कि मालवा-निमाड़ जिसे सत्ता का रास्ता कहा जाता है, वहां पर सामंजस्य बिठाने का दौर शुरू हो गया है। 2018 में भाजपा को सबसे ज्यादा अपनों के ही बागी होने से झटका लगा था। कई सीनियर चेहरे चुनाव में या तो निर्दलीय खड़े हो गए थे या फिर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसी के चलते भाजपा की 15 साल की सरकार चली गई थी। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सोच सही है कि जनता के हितों के लिए सभी को साधने और सामंजस्य बिठाने-जोड़े रखने का दौर पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी 2018 की तरह 2023 में वापसी करेगी। कमलनाथ के यह भी निर्देश हैं कि पार्टी में सभी नेताओं को तवज्जो दी जाए।

नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट

मप्र में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भाजपा के भीतर एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। यूं तो शिवराज सिंह चौहान को हटाने की मुहिम पिछले साल भी शुरू हुई थी, पर बाद में आलाकमान ने फैसला टाल दिया था। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सूबे की भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। फर्क बस इतना आया है कि अब कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर माने जा रहे हैं। हालांकि पांच साल पहले तक अमित शाह के नजदीकी होने के नाते पार्टी में उनका रुतबा था, पर कई विवादों में फंस जाने और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे लाने में कामयाब नहीं होने के कारण वे अब एक तरह से हाशिए पर हैं। ऊपर से उनका विधायक बेटा अलग कोई न कोई बखेड़ा करता रहा है। पद की दौड़ में नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा है।

हालांकि, पिछले साल नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में आया था। लेकिन, अब दौड़ में नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2018 में भाजपा कांग्रेस से मात खा गई थी। तभी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। उनकी सरकार गिराने और वापस भाजपा की सरकार बनवाने का सारा श्रेय सिंधिया को ही जाता है। सिंधिया अभी राज्यसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री हैं। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना में युवा हैं। शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सूरत में पार्टी को 2018 जैसे अंजाम का डर सता रहा है। अगर पैमाना लोकप्रियता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में महारत को माना जाए तो नरोत्तम मिश्रा भारी पड़ते हैं, जो इस समय सूबे की सरकार में गृहमंत्री हैं। कुर्सी छिनने की आहट शिवराज सिंह को भी है। वे भी अपनी गोटियां फिट करने और पिछड़ा कार्ड खेलने का दांव चल रहे हैं।

टिकट का घमासान

भाजपा में टिकट का घमासान तेज होने लगा है। खासकर उन 28 सीटों पर सबसे अधिक घमासान है, जहां के कांग्रेसी विधायक श्रीमंत यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इन 28 सीटों पर नई भाजपा और पुरानी भाजपा के अलग-अलग दावेदार हैं। ऐसे में भाजपा में टिकटों के लिए सिंधिया समर्थक और पुराने भाजपाइयों के बीच घमासान मचेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट चयन पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने यह काम आकांक्षी विधानसभा (कांग्रेस के कब्जे वाली) सीटों से शुरू किया है। इनमें वे सीट भी शामिल हैं, जहां उपचुनावों में तो भाजपा जीती, लेकिन 2018 में हारी थी। पार्टी ने तय किया है कि आम चुनाव में किसी नेता का समर्थक होने मात्र से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। प्रत्याशी तो भाजपा की टिकट चयन की परंपरागत प्रक्रिया से ही तय होंगे। ऐसे में 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले 28 विधायकों में से आधे से ज्यादा नेताओं को फिर से टिकट मिलने पर संशय की स्थिति बन गई है। दरअसल, राजनीति में नए-पुराने सभी नेता मायने रखते हैं। नवंबर-दिसंबर में मप्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा के पुराने नेता फिर से आवाज बुलंद करने में लगे हैं। ये बदली हुई परिस्थितियां अपनों से ही मुसीबत के संकेत दे रही हैं। जो चेहरे पार्टी में कभी कद्दावर माने जाते थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, अब वही जीत के रास्ते पर कांटे बिछा सकते हैं। इन परिस्थितियों की जड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थकों सहित भाजपा ज्वाइन करना है। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में आने के बाद जिन सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां पार्टी के पुराने चेहरों को मौका न मिलना पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर-चंबल में नई भाजपा और पुरानी भाजपा के अलग-अलग दावेदार हैं। भाजपा में टिकटों के लिए सिंधिया समर्थक और पुराने भाजपाइयों के बीच घमासान मचेगा। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए लोग टिकट के लिए तगड़े दावेदार हैं, तो वहीं पुराने भाजपाई भी टिकट की दौड़ में लगे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सतीश सिकरवार विधायक हैं। इस सीट पर भाजपा के सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल सबसे बड़े दावेदार हैं। इसी सीट पर पुराने भाजपाई जय सिंह कुशवाहा, माया सिंह, अनूप मिश्रा की दावेदारी भी सामने आ रही है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक विधायक हैं। इस सीट से पुराने भाजपाई पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, प्रियांशु शेजवलकर, अभय चौधरी बड़े दावेदार हैं। वहीं, नई भाजपा यानी सिंधिया समर्थक मदन कुशवाहा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी भी सिंधिया के सहारे टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं। इस सीट पर तोमर टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। इसी सीट पर पुराने भाजपाई जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की अंदरूनी दावेदारी चल रही है।

जीत के लिए कुछ भी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, कट्टर हिंदुत्व का लंबा चला अभियान और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के बावजूद कर्नाटक में भाजपा की हार से मप्र में कांग्रेस जिस तरह उत्साहित नजर आ रही है, उससे मप्र भाजपा सतर्क हो गई है। सत्ता और संगठन के नेता किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए पार्टी ने रणनीति बनाई है कि प्रदेश में हर हाल में चुनाव जीतना है और जीत के लिए पार्टी कुछ भी करेगी। इसके लिए आलाकमान ने मप्र के रणनीतिकारों को गाइडलाइन बनाकर दी है। अब पार्टी उसी आधार पर मप्र में चुनावी रणनीति बनाकर काम करेगी।

गौरतलब है कि भाजपा ने करीब एक साल पहले से ही 51 फीसदी वोट के साथ 200 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कर्नाटक चुनाव परिणाम और पार्टी में तथाकथित वर्चस्व की जंग के बाद के हालातों को देखते हुए आलाकमान ने नई गाइडलाइन पर काम करने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत दिल्ली से मिली गाइडलाइन पर भाजपा में फिर मंथन शुरू हो गया। गत दिनों प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के 9 दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जुटे और ढाई घंटे तक मंथन कर निर्णय लिया कि इस बार वह सभी काम किए जाएंगे जिनसे चुनाव जीता जा सके।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में ढाई घंटे चली बैठक में दिग्गज नेताओं ने जहां महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की, वहीं चुनाव जीतने के लिए समन्वय व समझाइश के अलावा जोड़-तोड़ फॉर्मूला अपनाने पर भी मंथन किया। अब भाजपा हर क्षेत्र और क्षत्रप के हिसाब से काम करेगी। अलग-अलग अंचल के हिसाब से रणनीति की बेस लाइन तय की गई है। ये भी तय हुआ कि कहां-किन प्रमुख लोगों से संवाद बढ़ाना है। असंतोष वाले नेताओं को साधने व ऐसे लोगों से भी संवाद बढ़ाना है, जो भविष्य में भाजपा से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हर नेता अपने क्षेत्र में काम करेगा। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी योजनाओं के प्रचार-प्रसार करने के साथ ही डैमेज कंट्रोल में जुटेंगे। गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। 10 जून को जब 1 करोड़ 20 लाख लाड़ली बहनों के खातों के एक-एक हजार रुपए डाले जाएंगे, तब उत्सव मनाया जाएगा। 30 जून तक जनसंपर्क का महाअभियान चलेगा। इसमें केंद्र से लेकर राज्य के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। महाअभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक में असंतुष्टों को साधने के साथ कांग्रेस की घेराबंदी को लेकर भी चर्चा की गई।

भाजपा के असंतुष्टों को साधने में लगी कांग्रेस

नवंबर में होने वाले मप्र विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस भाजपा के असंतुष्टों को साधने और उन्हें अपने पाले में लाने के प्रयास में जुट गई है। इसके लिए जिलावार रणनीति तैयार कर काम शुरू किया गया है। देवास जिले में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी हों, अशोकनगर के यादवेंद्र सिंह यादव या फिर हरदा के दीपक जाट, सभी इसी कार्ययोजना के तहत साधे गए हैं। यही नहीं, बालाघाट जिले में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई है। इसी तरह पार्टी अब इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर और पन्ना जिलों में काम कर रही है। इन जिलों में भाजपा से जुड़े प्रभावशाली नेता जल्द ही कांग्रेस के मंच पर नजर आ सकते हैं। कांग्रेस जिन लोगों को पार्टी में शामिल करा रही है, उनके बारे में जिला संगठन से सहमति के बाद ही निर्णय लिया जा रहा है। स्थानीय समीकरण को साधने पर सर्वाधिक जोर है। दरअसल, पार्टी ऐसा कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहती है जो चुनाव में उसकी संभावना को मजबूती प्रदान करता हो। यही कारण है कि बालाघाट की राजनीति में खासा दखल रहने वाले मुंजारे परिवार को साधा गया है। अनुभा मुंजारे ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 2013 और 2018 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। यहां दोनों बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। उनके पति कंकर मुंजारे सांसद और तीन बार विधायक रह चुके हैं। इसे देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बिना देर किए, उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। संभावना है कि उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जाए।

मुख्यमंत्री के चेहरे पर रार

विधानसभा चुनाव को अभी 5 महीने से अधिक का समय है। चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? यह तो मतदाता ही तय करेगा, लेकिन इस बीच, मप्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जहां कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगवा चुके हैं, वहीं आलाकमान का कहना है कि कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यभर में 1 जनवरी 2023 को कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग बिना आलाकमान की अनुमति के लगाए थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमलनाथ को सीएम फेस घोषित कर दिया था। कांग्रेस में एक कहावत आम है, कांग्रेस को चुनाव में कभी विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं हराती है बल्कि खुद कांग्रेसी चुनाव हराते है। कांग्रेस में गुटबाजी का वृक्ष इतना घना है कि हर चुनाव से पहले विद्रोह के फल जनता को भी दिखाई देने लगते हैं।

मप्र में ऐसी गुटबाजी के चलते 15 सालों के संघर्ष के बाद आई सत्ता को कांग्रेस से महज 15 महीनों में तब गंवा दिया था, जब पहले मुख्यमंत्री बनने के दावेदार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर भाजपा की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाया था। अब जबकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बीते

चुनाव में चुनौती देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं हैं लेकिन फिर भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कद्दावर नेता अजय सिंह और अब युवा नेता जीतू पटवारी से कमलनाथ को पर्दे के पीछे से चुनौती मिलती रहती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री वाले होर्डिंग के सड़कों पर दिखाई देते ही कांग्रेस की गुटबाजी भी सड़कों पर दिखाई देने लगी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सामने आए और कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान की ओर से तय किया जाता है।

आपसी टूट-फूट के कारण 2020 में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के लिए 2023 में भी अंदरूनी गुटबाजी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदरखाने में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तकरार बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय गुट में खींचतान बढ़ गई है। साल 2018 में कांग्रेस ने 15 साल बाद अपनी खोई जमीन हासिल करते हुए मप्र में सरकार बनाई थी। उसके पीछे पार्टी नेताओं की एकजुटता प्रमुख कारण थी, लेकिन 15 माह बाद ही 2020 में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और सिंधिया के दलबदल के कारण कमलनाथ सत्ता से बाहर हो गए थे। कमोबेश 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस में इसी तरह के अंदरूनी टकराव के हालात बन रहे हैं। कमलनाथ का गुट उन्हें भावी मुख्यमंत्री मानकर चल रहा है। इसके लिए बकायदा कार्यक्रमों के दौरान पोस्टर बाजी में भी कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। उधर दिग्विजय खेमे के लोग भी अंदरूनी तौर पर कमलनाथ के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के खास समर्थक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने तो सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से तय होता है।

कमलनाथ को अपनों की चिंता

मिशन 2023 की तरफ बढ़ रहे मप्र में भाजपा हो या कांग्रेस, उसकी प्रतिष्ठा वाली सीटों पर सभी की निगाह हैं। चुनावी मौसम करीब आते ही दावेदारों के चेहरे भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। सियासी गलियारों में अभी से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी सवाल हो रहे है कि क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? यदि नहीं तो फिर उनकी जगह दूसरा चेहरा कौन होगा? सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ किसी और की बजाय वह अपनी बहू यानि सांसद नकुलनाथ की **पत्नी प्रियानाथ** को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं।

2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब हुई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ के लिए सीट खाली करने उनके करीबी विधायक दीपक सक्सेना ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जहां से उपचुनाव जीतकर कमलनाथ विधानसभा पहुंचे। इस बार फिर कांग्रेस ने सत्ता वापसी का सपना संजोया है। कमलनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार अभी से गर्म हो गया है। मीडिया भी उनका मन टटोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अभी खुलकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। यह जरूर कह रहे हैं कि उनका खुद के चुनाव लड़ने से ज्यादा फोकस पूरे प्रदेश में पार्टी को जीत दिलाने पर है।

कांग्रेस पार्टी से जुड़े जानकार बताते हैं कि कमलनाथ अपने राजनीतिक कद के हिसाब से ही हर फैसले लेते आए हैं। सांसद के तौर पर उनका लंबा कैरियर रहा है और केंद्रीय मंत्री भी रहे। मप्र में जब सियासी परिस्थितियां बदलीं तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा का उपचुनाव लड़ा। इस बात की कम गुंजाइश है कि वह चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फिर उनकी जगह नया चेहरा कौन होगा तो उस सीट को सुरक्षित रख सकें, यह बड़ा सवाल है। यदि छिंदवाड़ा सीट दूसरों के लिए छोड़ी गई, तो दावेदारों की लंबी फौज है, जिससे कांग्रेसियों में ही आपसी विरोध का बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे हालात न बने इसके लिए कमलनाथ अभी से परिवार का एक विकल्प लेकर चल रहे हैं। वे अपने बेटे सांसद नकुलनाथ की पत्नी और बहू प्रियानाथ को चुनाव मैदान में उतार सकते है। इस फैसले से न तो स्थानीय दावेदार आगे आएंगे और न ही किसी तरह का विरोध होगा। साथ ही सीट भी सुरक्षित रहेगी। यह सभी के लिए सरप्राइज हो सकता है।

आपदा को अवसर में बदलने का निर्देश

मप्र में दलबदल की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में बड़ी सेंध लगाई है। कांग्रेस ने भाजपा के दो पूर्व विधायकों को तोड़ लिया है। हालांकि, सत्ताधारी दल भाजपा में सेंध लगाने के बाद भी कांग्रेस ज्यादा उत्साहित नहीं है। कांग्रेस को विश्वास है कि भाजपा भी जरूर पलटवार करेगी। भाजपा के पलटवार के अंदेशे से कांग्रेस के सभी नेता अलर्ट पर हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। बता दें, चुनावी राज्य मप्र में अब दलबदल का खेल शुरू हो गया है। अपनी महत्वकांक्षा के चलते नेता भी अपनी पार्टी छोड़ अन्य पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। बीते कई दिनों में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। प्रसपा के अध्यक्ष कमल सिंह चौहान अपने 1500 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए तो वहीं भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी और सेवढ़ा से पूर्व विधायक ने भी भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सेंध लगाने के मामले में फिलहाल कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा से आगे चल रही है। बता दें एक महीने के अंदर कांग्रेस ने भाजपा में बड़ी सेंध लगाई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के चार बड़े नेताओं ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। इन नामों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री 8 बार के विधायक और पूर्व सांसद कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का नाम शामिल है। भाजपा में सेंध लगाने के बाद कांग्रेस भी उत्साहित नहीं है। कांग्रेस को अंदेशा है कि अब भाजपा भी पलटवार करते हुए सेंध लगाने का प्रयास करेगी, जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी अलर्ट पर है। वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के सभी नेताओं से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। भाजपा में अभी कुछ और ऐसे नेता हैं, जिनके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। इन नेताओं में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन भी शामिल हैं। बीते कुछ दिनों से वरिष्ठ नेता सत्तन अपनी ही पार्टी पर लगातार मुखर हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, अपैक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी शामिल हैं। समय रहते भाजपा ने इन्हें मैनेज नहीं किया तो ये नेता भी भाजपा के हाथ से निकल सकते हैं।

नायक या खलनायक?

इंफोसिस के फाउंडर एननारायण मूर्ति जब भी बोलते हैं तो उसे सबको सुनना ही पड़ता है। वे अपनी बात बेखौफ अंदाज में रखते हैं। उन्होंने पिछले दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद (आईआईएम-ए) के 58वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कहा कि कारपोरेट लीडर्स को अपनी सैलरी लेते हुए संयम बरतना चाहिए। उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत खर्चीला नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि जिस देश में अब भी खासी गरीबी है, वहां पर उद्योगपतियों को एक तरह से अपने व्यवहार से उदाहरण पेश करना चाहिए। नारायणमूर्ति की बात पर गौर तो किया ही जाना चाहिए। नारायणमूर्ति आईआईएम, अहमदाबाद के अध्यक्ष थे और कई विषयों पर मंत्रालय से अलग विचारों के लिए विवादों में भी आ जाते थे! पर, वे अपनी बात मजबूती से रखते थे और कौन क्या सोच रहा है, इसकी परवाह नहीं करते थे! यह कहना सही होगा कि हमारे यहां के अमीरों का लाइफ स्टाइल किसी राजा-महाराजा जैसा रहने लगा है। ये शादी-ब्याह के अवसरों पर या फिर अपने घरों को खरीदने में सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर चेयरमेन बिल गेट्स से अधिक धनी कौन होगा। पर उनका जीवन सादगी भरा है। वे कमाए हुए धन के बड़े भाग का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। इधर आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति भी हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमेन आनंद महिंद्रा अपनी पुत्री का **विवाह सादगी** के साथ करते हैं। उनके विवाह समारोह में तीन-चार दर्जन लोग रहते हैं। ये ही होना भी चाहिए। नारायणमूर्ति का लाइफ स्टाइल भी बहुत सादगी भरा है। वे अपने अरबों रुपयों के घर में नहीं रहते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्रषि सुनक के ससुर नारायणमूर्ति की पत्नी सुधा जी को भी आप कोई बहुत महंगी साड़ी पहने हुए नहीं दिखेंगीं। दोनों पति-पत्नी लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। रतन टाटा भी धन नहीं फूंकते। इस बीच, ये निश्चित रूप से विचारणीय मसला है कि किसी कंपनी के सीईओ को कितनी सैलरी मिले? सीईओ अपनी कंपनी का कप्तान होता है। तो क्या इसलिए उसे अपनी कंपनी के बाकी कर्मियों की अपेक्षा कई गुना अधिक पगार मिले? क्या कंपनी के कर्मियों का उसे बुलंदियों में लेकर जाने में कोई रोल नहीं होता? क्या सिर्फ सीईओ ही अपनी कंपनी की सफलता का श्रेय ले ले? सीईओ को भारी-भरकम पगार मिलती रहे, इसके पक्ष में एक तर्क भी दिया जाता है। कहा जाता है कि चूंकि वह अपनी मेहनत से शिखर पर पहुंचता है, इसलिए मोटी पगार पाना उसका हक बनता है। कुछ साल पहले देश की एक प्रमुख टायर कंपनी के सीईओ की पगार पर बवाल मचा था। उसने अपनी सालाना सैलरी में दस फीसदी तक की वृद्धि कर ली, हालांकि उसकी कंपनी का मुनाफा विगत वर्षों की तुलना में घट रहा था। अब एक सवाल? क्या कोई कर्मी खराब प्रदर्शन करने के बाद भी अपनी वेतन में मोटी वृद्धि की उम्मीद कर सकता है? नहीं।

ये ही सवाल उस टायर कंपनी के सीईओ से क्यों नहीं पूछा जाता? जब देश में करीब पौन अरब **आबादी एक लाख रुपए** सालाना रुपए से कम पर गुजर-बसर करती हो तब ऐसी बर्बर पगार-विषमता को कैसे न्यायपूर्ण ठहराया माना जा सकता है? सरकार किसी भी दल या गठबंधन की रहे, क्या इतनी वीभत्स पूंजीवादी व्यवस्था को झेलना चाहिए? आर्थिक उदारीकरण के पश्चात सैलरी में गुणात्मक सुधार हुआ है। सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों की सैलरी अब सम्मानजनक हो चुकी है। पर सैलरी में अंतर काफी बढ़ा है। इस स्थिति के कारण कर्मियों में तनाव और आपस में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास और वैमनस्थ का भाव भी बढ़ा है। ये तो तस्वीर का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहां सफल उद्यमियों को लेकर समाज के एक वर्ग की बड़ी नेगेटिव राय रहती है। देख लीजिए कि आजकल देश के दो महत्वपूर्ण औद्योगिक घरानों के पीछे अकारण सोशल मीडिया पड़ा रहता है। यहां पर बात **रिलायंस और अडानी समूहों** की हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा व्यापार और दूरसंचार के क्षेत्र में देश व्यापी बड़ा कारोबार करती है। रिलायंस भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है। इसका अर्थ यह हुआ कि रिलायंस के लाखों शेयर होल्डर भी उस लाभ के भागीदार हैं। इसमें लाखों पेशेवर काम भी करते हैं। लगभग सभी की तनख्वाह इतनी अधिक होती है कि सभी टैक्स देते हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

विवादों में अडानी

अब बात कर लें अडानी समूह की भी। कुछ समय पहले, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आरोप लगाया गया कि समूह स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी में शामिल है। इस रिपोर्ट के आने के बाद हमारा सोशल मीडिया अडानी के पीछे इस तरह से पड़ गया, मानो उसने कोई अपराध किया हो। अभी तो उस पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। पर इससे किसी को कोई मतलब भी नहीं है। फिलहाल अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धूल में मिल गए हैं। गौतम अडानी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। उन्हें जबर्दस्ती खलनायक बना दिया गया है। ये नकारात्मकता बढ़ती ही जा रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं। यूपीए सरकार के दौर में कुमार मंगलम बिड़ला समूह के अध्यक्ष आदित्य बिड़ला पर कोलगेट में एफआईआर ही दर्ज हो गई थी। बिड़ला का भारत के कॉरपोरेट जगत में टाटा ग्रुप के पुराण पुरुष रतन टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक के चेयरमेन दीपक पारेख के जैसा ही स्थान है। इससे पहले कभी कुमार मंगलम बिड़ला का नाम किसी विवाद में नहीं आया था। इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर करने से हड़कंप मच गया था। अगर हम अपने देश के उजली छवि वाले कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों पर मिथ्या आरोप लगाएंगे या फिर उन पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो समझ लें कि दुनियाभर में भारतीय कारोबारियों की गलत छवि ही जाएगी। खैर, अब कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे इस सम्मान के हकदार हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि एक तरफ तो एन नारायणमूर्ति की सलाह पर देश के बड़े कारोबारियों और धनी लोगों को अमल करना होगा। दूसरा, देश को अपने उद्योग जगत की सफल हस्तियों का सम्मान करना भी सीखना होगा।

कम हो रहा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव?

कुछ दशक पहले तक देश की राजनीति में दो पार्टियों भाजपा और कांग्रेस का प्रभाव था, लेकिन उसके बाद कई क्षेत्रीय पार्टियां तेजी से पनपीं। लेकिन एक बार फिर इन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो रहा है।

कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद से क्षेत्रीय दलों के सुर बदल गए हैं। बात-बात में कांग्रेस को कोसने और राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता न मानने की बात करने वाले अब चुप हैं। राहुल गांधी का मुखर विरोध करने वाले विपक्षी दल अब राहुल गांधी में नेतृत्व देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक विपक्षी गठबंधन की बैठकों में बुलाने के बाद भी आने में आनाकानी करने वाले अब कांग्रेस की शान में कशीदे पढ़ने लगे हैं। इसका कारण सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दलों को अब सामने अपनी राजनीति का अवसान दिख रहा है। दो आम चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने पर यही नजर आता है कि जनता छोटे दलों की अवसरवादिता, पदलोलुपता और भ्रष्टाचार के कारण अब इनको धीरे-धीरे राजनीति के मैदान से आउट करना चाह रही है।

मोटे तौर पर कहा जाए तो अब क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक यात्रा पर विराम लगने जा रहा है। उप्र, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसके साफ-साफ संकेत मिल रहे हैं। दीवार पर लिखी इस इबारत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले पढ़ा, और कांग्रेस की तरफ सार्वजनिक तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुस्लिम वोट टीएमसी से खिसक कर कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने लगा है। तबसे टीएमसी में खलबली है और ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस से अपील कर रही हैं कि बंगाल को उनके हवाले छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में वह कांग्रेस के साथ हैं।

राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कह रहे हैं कि अब देश में गठबंधन की राजनीति का समय खत्म होने जा रहा है। ऐसा कहने के पर्याप्त कारण हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2014 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। जनता ने अपनी तरफ से पूर्ण बहुमत देने में कोई संकोच नहीं किया। इसी तरह उप्र के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो 2017 और 2022 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। अभी हाल में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस का इस बार न सिर्फ मत प्रतिशत 18.3 प्रतिशत से घटकर 13.29 प्रतिशत हो गया बल्कि 2018 के मुकाबले उसकी सीट भी 37 से घटकर 19 रह गई। इस तरह कई बार से जनता साफ संकेत और संदेश दे रही है कि उसे कमजोर सरकार नहीं चाहिए, जो विकास कार्यों को रोकने या साफ-सुथरा प्रशासन देने की नाकामी के लिए सहयोगी दलों के मोल-भाव को जिम्मेदार ठहराए। दरअसल, अब जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ गुड गवर्नेंस चाहिए। उसे कोई बहाना नहीं चाहिए।

क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय जन आकांक्षाओं और जातीय अस्मिता को उभारकर एक समय तक राज किया। लेकिन 1989 से शुरू हुई गठबंधन की उठापटक की राजनीति और सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को जनता समझ चुकी है। क्षेत्रीय और छोटे दलों की राजनीतिक सीमा से भी सब वाकिफ हो गए हैं। ऐसे में आम जनता का झुकाव एक बार फिर राष्ट्रीय दलों की तरफ हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दल प्रदेश में स्वतंत्र क्षत्रप की हैसियत रखते थे तो केंद्रीय सत्ता में किंगमेकर की भूमिका निभाते थे। क्योंकि तब केंद्र सरकार छोटे-छोटे दलों को एकजुट करके ही बनती थी। इसके एवज में पहले तो वह राजनीतिक मोल-भाव करते थे, बड़ा और मलाई वाला विभाग मुझे चाहिए, और बाद में समय-समय पर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सौदा भी करते थे। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती, राजद के लालू प्रसाद यादव, एनसीपी के शरद पवार, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, तेलुगुदेशम के एन. चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक मोल-भाव से सब परिचित हैं।

अब देखते हैं कि देश में क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है। उप्र की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राज्य में कई बार सत्तारूढ़ रहे। इन दोनों दलों की राजनीतिक धमक केंद्र सरकार तक सुनाई देती थी। लेकिन विगत दो विधानसभा चुनाव से सपा विपक्षी दल की हैसियत में तो है, लेकिन बसपा अपना आधार ही गवां बैठी है। बसपा के समक्ष अब अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की चुनौती है। वहीं चुनाव दर चुनाव दोनों दलों के मतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पंजाब में यही हाल अकाली दल का है। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल की राजनीति और धार्मिक नीति की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। कर्नाटक में यही हाल

वोटरों पर टिका दलों का वजूद

सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वजूद मुस्लिम, दलित, ओबीसी, आदिवासी वोटरों पर टिका है। ये चारों जातियां और समुदाय मूलतः कांग्रेस का वोटबैंक था। आजादी के बाद ब्राह्मणों को आगे रखकर कांग्रेस इन सभी दलों के वोटबैंक को इस्तेमाल करती रही। इस कारण एक-एक कर इन जातियों के वोट कांग्रेस से अलग होते गए। मंडल आंदोलन ने ओबीसी को कांग्रेस से दूर किया, तो ओबीसी मतदाता समाजवादी तासीर की क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ चला गया। काशीराम के दलित आंदोलन ने दलितों की आंखें खोलीं, तो दलित भी कांग्रेस से छिटक गया। बाबरी ढांचा टूटा तो मुस्लिम भी कांग्रेस से छिटक कर क्षेत्रीय दलों की ओर चला गया। आरएसएस ने आदिवासी क्षेत्रों में अपना काम बढ़ाया तो आदिवासी भाजपा की तरफ चला गया। 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार ने अपना सारा जोर मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने में लगा दिया, इसका नतीजा यह निकला कि ओबीसी, दलित और आदिवासी ने एकजुट होकर भाजपा का साथ दिया।

फिर दो ध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रहा देश

2014 और 2019 का नतीजा कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों से भी मोहभंग का था। सवाल यह है कि 2024 किस दिशा की ओर जा रहा है। तो उसके संकेत कर्नाटक के चुनाव नतीजों से मिलते हैं। देश फिर से दो ध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रहा है। यह क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी है। जेपी नड्डा की भविष्यवाणी सच हो रही है। 1992 के बाद यानि 42 साल बाद मुस्लिम कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। पहले यह संकेत पश्चिम बंगाल की सागरदीघी सीट के उपचुनाव नतीजे से मिला, और अब यह संकेत कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे से मिला। इसलिए खतरा तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राजद, समाजवादी पार्टी, बसपा, एनसीपी, टीआरएस या कहें बीआरएस और आम आदमी पार्टी को है। ममता, पवार, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, मायावती, चंद्रशेखर राव सब डरे हुए हैं। राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरने वाले केजरीवाल को तो कर्नाटक ने आईना दिखा दिया। आम आदमी पार्टी ने 209 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, आप को नोटा से भी कम सिर्फ आधा प्रतिशत वोट मिले। लेकिन सवाल है कि क्या दलित, आदिवासी और ओबीसी भी कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। कर्नाटक में ये तीनों समुदाय भी कांग्रेस की तरफ लौटे हैं, इसीलिए भाजपा 65 सीटों पर अटक गई। उसकी दलित समुदाय की आरक्षित सीटें घट गईं और आदिवासी आरक्षित सीट तो एक भी नहीं मिली। ओबीसी समुदाय तो इसलिए कांग्रेस की तरफ गया होगा कि उसे सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी, दलित भी इसलिए कांग्रेस की तरफ चला गया, क्योंकि दलित समुदाय के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस को भी सोचना होगा कि आदिवासी कांग्रेस की तरफ क्यों लौटा।

किंगमेकर देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल (सेकुलर) का हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भारी उठापटक का दौर चल रहा है। राज्य में शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख राजनीतिक दल हैं। शिवसेना भाजपा तो एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाते और चलाते रहे हैं। लेकिन शिवसेना का भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही पार्टी का हर समीकरण बदल गया। शिवसेना में बगावत हुई और अब उद्धव ठाकरे अपनी वाली शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हाल एनसीपी का है। यदि अजित पवार पार्टी से विद्रोह कर भाजपा में चले जाते हैं तो संगठन के ज्यादातर कार्यकर्ता अजित के साथ होंगे। ऐसे में शरद पवार के समक्ष अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में स्थापित करने के लिए कांग्रेस में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती दलित और ओबीसी जातियों का अलग-अलग रूप से राजनीतिक व्यवहार है। जिस तरह से उप्र में सपा और बसपा ओबीसी और एससी की एक विशेष जाति की पार्टी बनकर रह गईं, उसके बाद दलितों-पिछड़ों की अन्य जातियों का उनसे मोहभंग हुआ। कुछ जातियां भाजपा तो कुछ कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। ठीक इसी तरह क्षेत्रीय दलों को एक झटका उनके मुस्लिम वोटरों से मिलता दिख रहा है जो अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है। मुसलमानों का मानों क्षेत्रीय दलों से मोहभंग हो गया है और वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा वोट बैंक उससे छिन रहा है।

गौरतलब है कि 30-31 जुलाई 2022 को पटना में भाजपा के सात मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी। इस बैठक में दिया गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण बहुत चर्चित हुआ था। बल्कि विवादास्पद भी हो गया था। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा था कि देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। राजनीतिक पंडितों ने उनके इस बयान को सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद करने के नजरिए से देखा। जबकि उस समय बिहार में जदयू और भाजपा की साझा सरकार थी। नड्डा के बयान के नौंवे दिन 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर लालू यादव के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। इसलिए भाजपा के भीतर भी बहुत लोगों ने नीतीश से गठबंधन टूटने के लिए नड्डा के बयान को जिम्मेदार माना था।

2020 का विधानसभा चुनाव जेडीयू और भाजपा ने मिलकर लड़ा था, जिसमें जेडीयू की सीटें घटी थीं, और भाजपा की सीटें बढीं थीं। चुनाव नतीजों के समय भी चुनावी पंडितों ने समीक्षा की थी कि भाजपा ने चिराग पासवान के कंधों पर बंदूक रखकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे थे कि चिराग पासवान ने जेडीयू के सामने हर जगह उम्मीदवार खड़े करके उन्हें नुकसान पहुंचाया था। नड्डा के बयान को उसी संदर्भ में देखा गया कि भाजपा की रणनीति क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की है। लालू यादव और नीतीश कुमार के हित साझा हो गए, राजद और जेडीयू ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हाथ मिलाया और भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन जेपी नड्डा का बयान सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं था। उनका बयान राजनीतिक रिसर्च पर आधारित था। रिसर्च यह कहती है कि भाजपा के केंद्रीय राजनीति में उभरने के बाद छोटे-छोटे गुटों में बंटे भाजपा विरोधी वोटर एक जगह इकट्ठे होने के लिए विकल्प खोज रहे हैं। अगर भाजपा विरोधी वोटरों का केंद्र बिंदु फिर से कांग्रेस बनती है, तो उसका सीधा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को होगा। क्योंकि एक आध क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ दें, तो बाकी लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के परंपरागत वोटों को अपने पाले में लाकर ही पनपी हैं।

अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा विरोधी हैं, इसलिए भाजपा को हराने में क्षेत्रीय पार्टियों की विफलता के बाद भाजपा विरोधी वोटर कांग्रेस की ओर लौटेगा तो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होंगी। कर्नाटक में जेडीएस के साथ वही हुआ है, जो 31 जुलाई 2022 को जेपी नड्डा ने कहा था। जनता दल से निकलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपनी अलग पार्टी जनता दल सेक्युलर नाम से बनाई थी। उनकी पार्टी वोक्कालिंगा समुदाय और मुस्लिम वोट पर आधारित थी। क्षेत्रीय दलों की भाजपा को हराने की विफलता के चलते मुस्लिम वोट इस बार एकमुश्त कांग्रेस की तरफ लौट गया, वोक्कालिगा को भी जब लगा कि कुमारस्वामी पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन उनके समुदाय के डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वोक्कालिगा वोटर भी कांग्रेस की तरफ चला गया। जेडीएस 37 सीटों से घटकर 19 पर आ गई। जेडीएस का जो हश्र हुआ है, वह जेपी नड्डा की भविष्यवाणी के सत्य होने का पहला प्रमाण है।

● **विपिन कंधारी**

कर्नाटक के मतदाताओं ने जोड़-तोड़ की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। इसीलिए एक लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर एक स्थाई सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ताकि सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर सके। इसके साथ ही पिछली बार बहुमत से दूर रहने के उपरांत भी भाजपा द्वारा जोड़-तोड़ व खरीद-फरोख्त कर कांग्रेस व जनता दल सेकुलर की सरकार को गिरा कर अपनी सरकार बनाने का भी मतदाताओं ने भाजपा को कड़ा दंड दिया है। कर्नाटक के मतदाताओं ने बता दिया है कि उनका ऐसी किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं मिलेगा जो विधायकों को तोड़कर प्रदेश में कार्य कर रही सरकार को गिराकर अपनी पार्टी की सरकार बनाए।

कर्नाटक से कांग्रेस को मिला बूस्टर

चुनाव कई मायनों में खास

कर्नाटक विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में खास माना जाएगा। कर्नाटक के मतदाताओं ने 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 135 सीटों के साथ ही 42.88 प्रतिशत यानी 1 करोड़ 67 लाख 89 हजार 272 वोट देकर सत्ता की चाबी सौंप दी है। वहीं अब तक प्रदेश में सत्तारूढ़ रही भाजपा को 66 सीटों के साथ मात्र 36 प्रतिशत वोट यानी 1 करोड़ 40 लाख 96 हजार 529 वोट देकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं प्रदेश में अब तक तीसरी ताकत माने जाने वाली जनता दल सेकुलर पार्टी को महज 18 सीट 13.29 प्रतिशत यानी 52 लाख 5 हजार 489 वोट मिल पाए हैं। प्रदेश की राजनीति में सत्ता बनाने और बिगाड़ने की चाबी अभी तक जनता दल सेकुलर के हाथ में रहती आई थी। जिसे मतदाताओं ने इस बार छीनकर जनता दल सेकुलर की स्थिति को बहुत कमजोर बना दिया है। कांग्रेस को इस बार भाजपा से 26 लाख 92 हजार हजार 743 वोट ज्यादा मिले। जिस कारण कांग्रेस को भाजपा से दोगुनी से भी अधिक सीटें मिली हैं।

तमाम राज्यों में मिल रही शिकस्त के बीच कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव एक बूस्टर की तरह साबित हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जिसके बाद अब पार्टी कैडर में एक बार फिर जोश नजर आ रहा है, जो आने वाले चुनावों के लिए काफी अहम है। कर्नाटक के इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए 2024 की जमीन तैयार करने का भी काम कर दिया है।

कांग्रेस के पास इस साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज होने और 2018 में जीते गए मप्र को फिर से हासिल करने की कोशिश करने का एक मुश्किल काम था, क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ भाजपा में नाटकीय दलबदल के कारण उसे सत्ता गवानी पड़ी थी। अब उच्चतम स्तर पर, कांग्रेस नेतृत्व ने 2024 के आम चुनावों से पहले चुनाव होने वाले राज्यों में कर्नाटक टेम्पलेट को दोहराने का फैसला किया है। स्थानीय रणनीति, सकारात्मक अभियान, मुफ्त उपहार, टिकटों का जल्द वितरण और कांग्रेस की विचारधारा पर जोर देना मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।

हाल ही में भोपाल हवाई अड्डे पर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड के दिग्गज पार्टी नेताओं के बजाय चार एआईसीसी पर्यवेक्षकों- कुलदीप राठौर, अर्जुन मोधवाडिया, सुभाष चोपड़ा और प्रदीप टम्टा की उपस्थिति देखी गई। एमपीसीसी प्रमुख कमलनाथ और एआईसीसी महासचिव जय प्रकाश अग्रवाल की उपस्थिति में हुई एक लंबी बैठक में, पार्टी के नेताओं ने जल्द से जल्द एक चुनावी घोषणापत्र तैयार करने और 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए टिकटों को अधिकतम करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने 2021 में अपने उदयपुर मंथन सत्र में 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50 फीसदी टिकट देने का वादा किया था।

38 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो कांग्रेस हलकों में घूम रहा है जिसमें बजरंग बली शैली में बने एक चरित्र को भगवान राम को सूचित करते हुए दिखाया गया है कि कर्नाटक में काम पूरा हो गया है। मास्टर को अपने सबसे उत्साही भक्त कमलनाथ की मदद करने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है, जो वर्तमान में एमपीसीसी प्रमुख और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। संयोग से, नाथ एक साहसी हनुमान भक्त हैं। उन्होंने अपने छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में हनुमानजी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसने उन्हें दस बार संसद और विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना है। यह देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है। नाथ ने कहा था, छिंदवाड़ा हनुमान की मूर्ति दिल्ली के छतरपुर में एक से 8 इंच लंबी है। मैंने

भगवान हनुमान की भक्ति के कारण कुछ साल पहले इस मंदिर को तैयार करवाया था। इसके अलावा, माइंडशेयर एनालिटिक्स के पोल रणनीतिकार सुनील कानूगोलू और डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा को कार्रवाई में लगाया गया है। लॉ प्रोफाइल रहने वाले कानूगोलू को कथित तौर पर 2024 के संसदीय चुनावों के लिए पार्टी के अधिकार प्राप्त पैनल में शामिल किया गया है। अरोड़ा, जो 2021 में असम विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं। एआईसीसी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सुनील कानूगोलू और नरेश अरोड़ा दोनों सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार, विनोद वर्मा, एक पूर्व पत्रकार, ने स्वयंसेवकों का एक विशाल नेटवर्क विकसित किया है, जो पार्टी और उम्मीदवारों की समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्ट, टॉकिंग पॉइंट और निर्वाचन क्षेत्रवार प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस बैक टू बेसिक्स के दृष्टिकोण की ओर मुड़ रही है। जीत के तुरंत बाद, विशुद्ध रूप से दृश्य रूप में, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य के साथ फोटो साझा करने से परहेज किया। नवनिर्वाचित विधायकों ने भी नए मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया न कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को। इस छोटे से प्रतीत होने वाले विकास का अपना महत्व है क्योंकि अतीत में, सोनिया गांधी को संसद के दोनों सदनों में नेताओं का चयन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए पार्टी संविधान में संशोधन किया गया था जब सीताराम केसरी एआईसीसी प्रमुख थे। वास्तव में, वह प्रावधान पार्टी संविधान में अब भी है। इसी तरह, दशकों में पहली बार, कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव से 45 दिन पहले पार्टी प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करने में सफल रही।

1998 से 2017 और फिर 2019-2022 के बीच पार्टी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के लंबे कार्यकाल में इस सिफारिश को स्वीकार किया गया, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। खड़गे को श्रेय जाता है कि वे पदभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर इसे लागू करने में सफल रहे। ये भव्य पुरानी पार्टी में पुनरुद्धार या मानसिकता में बदलाव के शुरुआती संकेत हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अपने विश्वास और इस विश्वास को पुन: प्राप्त कर रही है कि वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले हाई-वोल्टेज अभियानों को जीतने या हराने में सक्षम है।

राज्यों के अलावा कर्नाटक विधानसभा सीट के रिजल्ट के बाद कांग्रेस को जो नई आशा नजर आई है उससे भी कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में संभावनाएं तलाशने में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि कर्नाटक की जीत, 2024 के आम चुनावों की शुरुआत है। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2024 के चुनावों में पार्टी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराएगी, यह जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि यह देखा गया है कि मतदाता अक्सर विधानसभा और **लोकसभा चुनावों** में अपनी पसंद का अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। यह ट्रेंड नहीं देखा गया कि विधानसभा चुनाव के वोटर्स लोकसभा चुनाव में भी उसी सोच के साथ वोट करते हों।

यह सही है कि कर्नाटक चुनाव परिणाम 2023 निसंदेह कांग्रेस के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। 2019 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस को राज्य में सिर्फ एक लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। यह सीट है बैंगलोर ग्रामीण। कांग्रेस पदाधिकारी सलीम अहमद का मानना है कि विधानसभा चुनावों ने हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बूस्टर डोज दिया है। रेकॉर्ड और वोटिंग पैटर्न दिखाते हैं कि कर्नाटक में मतदाता पारंपरिक रूप से राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अलग-अलग पार्टियों को चुनते हैं। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि भाजपा बहुमत को 104 सीटें ही मिली थीं और वह बहुमत से चूक गई थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा का कर्नाटक में वोट शेयर 36 प्रतिशत था। वहीं अगले साल हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 54 प्रतिशत रहा। इतना ही नहीं भाजपा 25 संसदीय सीटें जीती थी। कर्नाटक में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव देश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माने जाएंगे। इस चुनाव से देश की राजनीति की दिशा व दशा बदल सकती है। कर्नाटक चुनाव में मतदाताओं ने जहां सत्तारूढ़ भाजपा का सफाया कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी को बंपर बहुमत से जिताकर उसे नई संजीवनी प्रदान की है। लगातार जीत के नशे में चूर केंद्र में सरकार चला रहे भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व वाली छवि को भी इस विधानसभा चुनाव परिणाम से गहरा आघात लगा है। अब तक माना जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करिश्माई व्यक्तित्व के चलते हार को भी जीत में बदलने की क्षमता रखते हैं। मगर कर्नाटक में दिन-रात धुआंधार प्रचार व सैकड़ों किलोमीटर के रोड शो करने के उपरांत भी चुनाव में करारी हार से उनका करिश्माई व्यक्तित्व कमजोर पड़ा है।

● **इन्द्र कुमार**

इस बार नहीं चला भाजपा का जादू

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति के जानकार लोगों को लग रहा था कि इस बार भाजपा के हाथ सत्ता की चाबी नहीं आने वाली है। 2018 में कांग्रेस, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे। तभी से भाजपा उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में लग गई थी। कांग्रेस, जेडीएस के विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर भाजपा ने कुमारस्वामी सरकार को गिरा दिया तथा 26 जुलाई 2019 को भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया था। उसके 2 वर्ष बाद भाजपा के बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने। जिनका कार्यकाल 2 वर्ष से कुछ कम रहा। कहने को तो बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बन गए मगर उनकी सरकार पूरी तरह बीएस येदियुरप्पा के नियंत्रण में ही कार्य करती रही थी। बसवराज बोम्मई की मुख्यमंत्री के रूप में छवि एक कमजोर नेता की बन गई। जिस कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। कर्नाटक सरकार में ठेकेदारी करने वाले ठेकेदारों ने बोम्मई सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों पर 40 प्रतिशत कमीशन लेकर बिल पास करने के आरोप लगाए गए। जिसके चलते आमजन में भ्रष्टाचारी सरकार की छवि बन गई थी। सभी मंत्री अपनी मनमानी कर रहे थे। वहीं अधिकारियों पर भी काबू नहीं रहा था। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी कर्नाटक में सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह सफल रहा था।

नौकरशाह ठोकेंगे चुनावी ताल

छत्तीसगढ़ के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की धमक इस चुनाव में देखने को मिलेगी। कांग्रेस और भाजपा से एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी टिकट की दौड़ में हैं। अब तक आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस और शिक्षक चुनावी राजनीति में परचम लहरा चुके हैं। पिछले चुनाव में रिटायर आईएएस शिशुपाल सोरी कांग्रेस की टिकट पर कांकेर से विधायक चुने गए। वहीं, वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में उतरे आईएएस ओपी चौधरी को खरसिया सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में प्रमुख सचिव रहे गणेश शंकर मिश्रा, सरजियस मिंज, नीलकंठ टेकाम सहित अन्य अधिकारी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी नीलकंठ टेकाम की अब राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इस संबंध में उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन भी भेज दिया है। टेकाम ने कहा कि मैंने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। राजनीति में आने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले सलाह लूंगा। बता दें कि आईएएस नीलकंठ टेकाम वर्तमान कोष एवं पेंशन विभाग में डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले वे कई जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं। उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के बाद अब उनके राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उनकी आवेदन को अभी सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। गौरतलब है कि नीलकंठ टेकाम बस्तर के अंतागढ़ के रहने वाले हैं। वहीं उनका जन्म हुआ और अंतागढ़ में ही स्कूली शिक्षा भी पूरी की है। कांकेर से उन्होंने महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण की। कांकेर में वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के बाद अधिकांश पोस्टिंग उनकी बस्तर में ही रही। वे करीब पौने तीन साल तक कोंडागांव में कलेक्टर रहे। इसके अलावा राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं।

नीलकंठ टेकाम मूलत: कांकेर जिले के अंतागढ़ सरईपारा के रहने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कांकेर के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर 1990 में समाजशास्त्र विषय से एमए किया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और कुशल नेतृत्व के कारण वह छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। 1994 में एमपीपीएससी पास करने में सफल रहे और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में टॉपर रहे। उनका ज्यादातर कार्य क्षेत्र बस्तर रहा। कार्य के दौरान 6 साल जगदलपुर में एसडीएम और जगदलपुर में नगर निगम आयुक्त भी रह चुके हैं। कुंडा गांव में कलेक्टर रहते हुए उनके कामों की लोगों ने सराहना भी की और नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में कुंडा गांव को नंबर वन भी बनाया था। वर्तमान में नीलकंठ टेकाम कोष एवं लेखा विभाग के संचालक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आईएएस नीलकंठ टेकाम जनता के बीच बड़े चर्चित चेहरे हैं। टेकाम सामाजिक गतिविधियों में भी आगे रहते हैं। इसके साथ ही अपने कुशल कार्य दक्षता के कारण जनता के बीच में उनकी बेहतर छवि भी है। नीलकंठ टेकाम साल 2028 में रिटायर होंगे। हालांकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ही वीएसआर के लिए आवेदन कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने ओपी चौधरी को खरसिया से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव में ओपी चौधरी की हार हुई। वर्तमान में ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है।

प्रदेश की राजनीति में सबसे सफल ब्यूरोक्रेट के रूप में प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पहचान बनाई। पिछले चुनाव में एसीएस रहे सरजियस मिंज ने कांग्रेस का दामन थामा था। उम्मीद थी कि उनको जशपुर या कुनकुरी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि उनकी टिकट पक्की नहीं हो पाई। मिंज के पहले रिटायर्ड आईएएस आरपीएस त्यागी, इस्तीफा देने वाले डीएसपी विभोर सिंह व निरीक्षक गिरिजा शंकर जौहर कांग्रेस में गए थे। विभोर को कांग्रेस ने कोटा से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी से चुनाव हार गए। सेवानिवृत्त आईजी रवींद्र भेड़िया की पत्नी अनिला भेड़िया को पिछले चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया और चुनाव जीतने के बाद उनको महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया। आईजी रहे आरसी पटेल भी रिटायर होने के बाद कांग्रेस खेमे में गए थे। वहीं, पूर्व डीजी राजीव श्रीवास्तव पिछले लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद वह सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ गए।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

आदिवासी समाज के अफसर उतरेंगे मैदान में

सर्व आदिवासी समाज भी इस चुनाव में उम्मीदवार उतारने जा रही है। इसमें कई रिटायर अफसर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। नवंबर-दिसंबर में भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रिटायर आईपीएस अकबर राम कार्राम ने निर्दलीय ताल ठोंकी थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। गौरतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए राजनीति हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। पिछले साल इसी उद्देश्य से पूर्व आईएएस शैंकी बग्गा नौकरी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे। बग्गा का कहना है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित हैं और खुद भी जमीनी स्तर पर देश सेवा करना चाहते हैं। पूर्व आईएएस शैंकी बग्गा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं। वो 2013 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया। सिविल सेवा में चयनित होने के बाद शैंकी बग्गा ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर के भंडारा और ओडिशा में काम किया। शैंकी बग्गा एक युवा आईएएस हैं और अभी वह राजनांदगांव में ही रह रहे हैं।

तलवार की धार पर अजीत पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के इस्तीफे से उठा बवंडर अब लगभग शांत हो गया है। पवार के इस्तीफे से पार्टी में अनिश्चितता का जो माहौल बना था वो लगभग थम गया है। लेकिन यह तूफान आने के पहले वाली शांति है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष बने रहने को तैयार हो गए हैं। वहीं नया अध्यक्ष खोजने के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति ने भी शरद पवार को ही अध्यक्ष बने रहने की सिफारिश की है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है।

राजनीतिक हलकों में लोग यह जानते हैं कि शरद पवार के कमान से जब भी कोई राजनीतिक तीर निकलता है तो वह केवल एक शिकार नहीं करता है बल्कि वह एक साथ कई शिकार करने में सिद्धहस्त हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने और शरद पवार के स्वास्थ्य की दशा को देखते हुए एनसीपी आंतरिक कलह की शिकार है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का कोई मजबूत गठबंधन अभी आकार नहीं ले सका है। ऐसे में पार्टी के राज्य स्तरीय नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई बार ऐसी अफवाह भी फैली कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वशीभूत अजित पवार पार्टी के कई विधायकों को लेकर भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में शरद पवार के सामने पार्टी बचाने और पार्टी के अंदर अपनी हनक का अंदाजा लगाने की चुनौती थी। वह इस बात का भी आंकलन करना चाह रहे थे कि यदि भविष्य में वह अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं तो क्या उन्हें किसी विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुटबाजी, असंतोष और महत्वाकांक्षा से उपजे संघर्ष से हलकान है। सही बात तो यह है कि एनसीपी में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है। आंतरिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो ध्रुव हैं। एक तरफ शरद पवार-सुप्रिया सुले हैं तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों गुटों में संघर्ष की स्थिति है। लेकिन अजित पवार अपने को पार्टी और शरद पवार का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। घर से लेकर विधानसभा तक वह पवार की अंगुली पकड़ कर बढ़ते रहे। लेकिन अब वह पवार की छाया से मुक्त होना चाहते हैं। पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेने और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने को उतावले हैं।

सपा जैसी हो गई राकांपा की स्थिति

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस समय वही स्थिति है जो कुछ वर्षों पहले उप्र में समाजवादी पार्टी की थी। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन इटावा से लेकर लखनऊ तक उनके छोटे भाई शिवपाल यादव अपने को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष में क्या हुआ और शिवपाल यादव को क्या-क्या दिन देखने को मिले, यह हर कोई जानता है।

शरद पवार के वह दुलारे हैं और उनके हर राजनीतिक दांवपेच से वाकिफ हैं। लेकिन शरद पवार अपना उत्तराधिकारी अपनी लाडली बेटी सुप्रिया सुले को ही बनाना चाहते हैं। यह बात सही है कि वह इसके लिए कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करना चाहते। उनकी इच्छा है कि अजित पवार समेत समस्त पार्टी उनकी इस इच्छा को मान ले। और सुप्रिया को वह मान-सम्मान दे जो पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें मिलता रहा।

अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के बाद पवार के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसमें उनके भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का नाम आगे माना जा रहा था। इसके अलावा सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल जैसे नेताओं का नाम भी सामने आ रहा था। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए पवार ने एक कार्यकारिणी की नियुक्ति कर दी। और इस कार्यकारिणी में उन नेताओं को रखा जो भाजपा में जाने की योजना पर काम कर रहे थे। लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव और भावनाएं ऐसी तीव्र थीं कि उस कार्यकारिणी को पवार का इस्तीफा नामंजूर करना पड़ा। फिलहाल शरद पवार की इस्तीफे की शातिर चाल भी पुत्री सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाने में असफल रही। जैसे ही उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, पार्टी जड़ से हिल गई।

शरद पवार का इस्तीफा पार्टी में बगावत को थामने और सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बनाने का लिटमस टेस्ट था। पवार यह देखना चाहते थे कि क्या आज भी एनसीपी के सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं के दिल में उनका वही सम्मान है, जो पहले था, या अब पार्टी पर अजित पवार का एकछत्र राज हो गया है। शरद पवार ने बड़ी चालाकी से अपने को पार्टी के लिए अपरिहार्य साबित कर दिया। भतीजे को एक ही चाल में चित कर देने के बाद अब वह सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक समय उत्तराधिकार के संघर्ष में पार्टी और परिवार के लोगों ने तय किया था कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे और सुप्रिया सुले के हाथ में केंद्र की राजनीति होगी। लेकिन सुप्रिया सुले ने इस फॉर्मूले को नहीं माना। अजित पवार लंबे समय से पार्टी और परिवार का अधिकांश निर्णय करते और मानते रहे हैं। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार के भी वह प्रिय हैं तो सुप्रिया सुले के बड़े भाई हैं। मुंबई से लेकर बारामती और समूचे महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका जीवंत संपर्क-संबंध है। ऐसे में वह हर कीमत पर एनसीपी की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक बात और है, वह अपने चाचा की तरह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने सुप्रिया सुले आ गई हैं।

● **बिन्दु माथुर**

घाव बन चुका है नासूर

राजस्थान कांग्रेस में भी पंजाब जैसे हालात

बहरहाल, अशोक गहलोत सरकार से नाराज युवाओं का जिस प्रकार सचिन पायलट की यात्रा को साथ मिला है, वह कांग्रेस को परेशानी में डालने वाला है। यह स्पष्ट है कि गहलोत किसी कीमत पर पायलट को फिर से स्थापित होने नहीं देंगे और पायलट भरसक प्रयास करेंगे कि गहलोत फिर से सत्ता में न लौट पाएं। कुल मिलाकर दोनों में कटुता इतनी बढ़ चुकी है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा किसी तरह के सीजफायर करवाने का भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। राजस्थान कांग्रेस भी पंजाब की तरह आपसी कलह की शिकार होकर सत्ता से बाहर होने की कगार पर है। देखना यह है कि क्या इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, या सचिन पायलट अन्य कुछ जातिवादी संगठनों के साथ तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव के बाद राजस्थान में निर्णायक भूमिका में आ पाएंगे।

बीते तीन सालों में राजस्थान की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पूरी न हो पाने पर रूष्ट सचिन पायलट द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरूद्ध खोले गए मोर्चे को देखकर राजनीति के जानकार लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सचिन पायलट की अनुभवहीनता और उतावलेपन को जानने वाले लोगों को पता था कि वे अपने आपको मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बनने योग्य नेता मानते हैं। इसलिए सचिन की महत्वाकांक्षा के चलते यह तय था कि 2023 के चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस दो धड़ों में बंटेगी। राजेश पायलट के पुत्र होने के नाते 45 वर्षीय सचिन पायलट गुर्जर समाज के नेता हैं। कम उम्र में बड़े-बड़े पद मिल जाने के उपरांत भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी है। अपने स्वजातीय समर्थकों के हुजूम के दम पर पायलट को लगता है कि उनमें भारत का भावी नेता बनने की योग्यता है। वहीं 50 वर्षों से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति कर रहे अशोक गहलोत के सामने ठीक चुनावी साल में पार्टी के अंदर से हुई बगावत एक बार फिर से बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी है।

राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने की चाह में कोरोना संकट के दौरान सचिन पायलट अपने समर्थक 19 विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर में एक रिसॉर्ट में जाकर बैठ गए थे। उन्हें आशा थी कि उनके समर्थन में 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायक रहेंगे और भाजपा के समर्थन से वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे लेकिन वे 20 विधायक भी नहीं जुटा पाए और उपमुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद भी खो बैठे। इस घटनाक्रम के बाद कुछ समय तक गांधी-नेहरू परिवार द्वारा गहलोत और पायलट के बीच सुलह करवाने की कोशिश हुई फिर दोनों की आपसी कड़वाहट को देखते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। समय के साथ यह कड़वाहट बढ़ती गई। एक घाव सही समय पर देखभाल ना मिलने की वजह से नासूर बन गया। जब भी सचिन पायलट के तेवर थोड़े बगावत वाले नजर आए, उन्हें राहुल और प्रियंका द्वारा आश्वासन देकर मना लिया गया। लेकिन सोनिया गांधी को हमेशा गहलोत पर ही भरोसा रहा। इसलिए राहुल और प्रियंका चाहकर भी सचिन को दिए आश्वासन पूरे नहीं कर पाए। अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश असफल हो जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के लिए अवसर सीमित ही बचे हैं। इसलिए चुनावों से पहले उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना जरूरी हो गया है। कांग्रेस में उनको पहले जैसा महत्व मिले तो ठीक, नहीं तो वे अपनी अलग राह पकड़ने के लिए भूमिका बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे पिछले कुछ समय से अशोक गहलोत के साथ-साथ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी आरोप लगाकर अपने आप को दोनों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह चर्चा आम है कि सचिन पायलट के बारे में निर्णय करते समय कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत के दबाव में आ जाता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पिछले साल अशोक गहलोत का नाम सामने आया था। उसी वक्त यह स्पष्ट हो गया था कि दिल्ली कांग्रेस पर गहलोत का दबाव काम कर रहा है। गहलोत अपनी शर्तों पर कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते थे। उनकी शर्त थी कि राजस्थान की कमान उनके किसी विश्वासपात्र के पास ही रहेगी। लेकिन प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट को तुरंत मुख्यमंत्री बनाना चाहती थीं। उनके इशारे पर पार्टी महासचिव अजय माकन ने विधायकों की राय जानने के बहाने पायलट की ताजपोशी करवाने का प्रयास किया। उसी दौरान गहलोत के समर्थक विधायकों की बगावत वाला घटनाक्रम चला। बाहरी तौर पर दिख रहा था कि यह साफ तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ खुला विद्रोह था, लेकिन सोनिया गांधी के करीबी लोगों का कहना था कि गहलोत सबकुछ उनकी स्वीकृति से कर रहे थे। सोनिया और गहलोत की अंडरस्टैंडिंग काम कर गई और प्रियंका चाहकर भी पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। गहलोत ने चालाकी दिखाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इंकार कर दिया और राहुल व प्रियंका के दबाव के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहे।

सचिन पायलट अप्रैल माह की 11 तारीख को एक दिन के लिए अनशन पर बैठे थे। कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि वे ऐसा करें। क्योंकि उन्होंने अनशन अपनी ही सरकार की नाकामियों के खिलाफ रखा था। उनके अनशन पर राजस्थान के कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का ट्वीट आया कि उनका यह अनशन एंटी पार्टी एक्टिविटी माना जाएगा। वे जो मुद्दे मीडिया और जनता के बीच उठा रहे हैं, उन्हें पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए। रंधावा ने लिखा कि वे पिछले पांच महीने से राजस्थान के इंचार्ज हैं लेकिन उनसे कभी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। यह सारी बातें एक तरफ पार्टी द्वारा लिखी और समझाई जा रही थीं। दूसरी तरफ एक सच यह भी था कि प्रियंका का वरदहस्त होने के कारण कांग्रेस पार्टी ना सचिन पायलट पर कार्रवाई करने की स्थिति में थी और गहलोत की पीठ पर सोनिया का हाथ होने के कारण पायलट को पुन: सत्ता में हिस्सा देने की स्थिति में भी नहीं थी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

अपराधियों के लिए भयकारी है योगी मॉडल

उप्र में अपराध की दुनिया पहली बार इतनी भयभीत और सहमी हुई है। यहां जुर्म के किले की हर कुख्यात ईंट पर जीरो टालरेंस के फैसलाकुन प्रहार से कानून-व्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाने वाले दुर्दांत माफिया सरगना मुख्तार अंसारी व उनके भाई अफजाल अंसारी को सजा, अतीक अहमद गिरोह के लगभग खात्मे और कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना समेत संगठित अपराध के अनेक रसूखदारों का दमन सूबे में कानून के अमृतकाल की दास्तां कह रहा है।

जो माफिया सरगना दशकों से आतंक का पर्याय थे, जिनकी देहरी पर सजदा कर कानून के मुहाफिज खुद को महफूज समझते थे, जिनके मुकदमों में गवाही से मुकरना ही गवाह की जान-ओ-माल की सुरक्षा का एकमात्र रास्ता था, आत्मरक्षा हेतु 10-10 न्यायाधीशों ने जिनके मुकदमों को सुनने से इंकार कर दिया हो, जिनकी हजारों करोड़ की लंकाओं की कार्यकर्ता भाव के साथ चौकीदारी कानून के बहुतेरे रक्षकों के लिए जीवन की उपलब्धि रही, ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजा अथवा उनके पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने, गिरफ्तार होने, उनके अवैध आर्थिक साम्राज्यों के जमींनदोज होने से इस तथ्य, कथ्य और सत्य को मजबूती मिली है। यहां सवाल उठता है कि थाना भी वही, पुलिस भी वही, वही वर्दी, वही कानून की धाराएं, वही समाज, धनबल और बाहुबल भी वही, लेकिन साल 2017 के बाद पुलिस की क्षमता व दक्षता में अभिवर्धन और कार्यशैली में आया अभूतपूर्व परिवर्तन का कारण क्या है? दरअसल यह गुणात्मक परिवर्तन नेतृत्व की शक्ति व उद्देश्य की स्पष्टता का सुफल है।

20 मार्च, 2017 से मार्च, 2023 के मध्य पुलिस और अपराधियों के बीच हुईं 10,713 मुठभेड़ें बता रही हैं कि योगी सरकार में उप्र पुलिस अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। अब पुलिस पलायन नहीं, बल्कि अपराधियों को ललकार रही है। अब तक 184 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर उप्र पुलिस ने अपने ध्येय वाक्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम को मूर्तरूप प्रदान किया है। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक, मार्च, 2017 से लेकर मार्च, 2023 तक उप्र पुलिस द्वारा 23,069 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसके साथ ही 4,911 अपराधी ऐसे थे, जिन्हें मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली ने कानून का पाठ पढ़ाया। दीगर है कि इन सफलताओं के पथ को प्रदेश की पुलिस ने अपने लहू की कीमत पर निर्मित किया है। गौरतलब है कि मुठभेड़ों के दौरान 1,424 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक दर्जन से अधिक पुलिस कार्मिक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बलिदान भी हो गए।

कभी राज्य सरकार के समानांतर सत्ता चलाने वाले माफिया सरगनाओं की आपराधिक लंकाएं आज जमींदोज हो रही हैं। विगत 6 वर्षों में उप्र के अंदर गैंगस्टर अधिनियम में 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की चल-अचल संपत्तियों का जब्तीकरण हुआ है। योगी जानते थे कि प्रगति के उजले पन्नों को असुरक्षा की काली स्याही बदरंग कर देती है। लिहाजा उन्होंने सत्ता संभालते ही समर्थ अभियोजन समेत सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हेतु सभी अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी। उसी श्रृंखला में पुलिसिंग में सुधार एवं कानून व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई। कार्यवाहियों में शीघ्रता तथा विवेचनाओं में गतिशीलता, गहनता और निष्पक्षता के लिए पुलिस के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए राज्य सरकार ने 114 नए पुलिस स्टेशन, 163 नई चौकी, 6 नए महिला पुलिस स्टेशन, आर्थिक अपराध से संबंधित 4 नए पुलिस स्टेशन, 16 नए साइबर क्राइम स्टेशन, सतर्कता प्रतिष्ठान की 10 नई शाखाएं, 90 नए फायर स्टेशन और 2 जल पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब और जोन स्तर पर साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित की गई हैं। योगी सरकार ने विभिन्न पदों पर 1 लाख 64 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती को अंजाम देकर पूर्ववर्ती सरकारों को आईना दिखाया है।

दीगर है कि धूप कितनी भी नरम क्यों न हो, वह चांदनी का हक अदा नहीं कर सकती है और इस सत्य को समझते हुए योगी सरकार ने महिलाओं को थाने में माकूल माहौल मुहैया कराने के लिए प्रदेश के सभी 1,535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है, अब महिलाएं अपनी शिकायतों को महिला पुलिसकर्मियों के सामने खुलकर बता सकेंगी। पुलिस विभाग में महिलाओं की 20 फीसदी अनिवार्य भर्ती के फैसले और 3 महिला पीएसी बटालियनों के गठन से नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिली तो 218 फास्ट ट्रैक कोर्टों के गठन से महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

ई-अभियोजन में उप्र प्रथम

महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1,016 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक कारावास की सजा, 3,076 आरोपियों को 10 साल से कम की सजा, प्रदेश सरकार की स्त्री सुरक्षा के प्रति गंभीरता को प्रकट करती है। पॉक्सो और महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए ई-अभियोजन में उप्र पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ये उपलब्धियां किसी भी लोकनिष्ठ सरकार द्वारा अपराध मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में बढ़े महत्वपूर्ण कदम हैं। ये कार्य पिछली हुकूमतें भी कर सकती थीं, लेकिन भूतपूर्व हुक्मरानों ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कोई संकल्प नहीं किया था। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का उद्घोष योगी के विजन को, उनके मिशन को बखूबी बयान करता है। यह ऐलान प्रभु श्रीराम के उस प्रण की प्रतिध्वनि है जिसमें वे कहते हैं कि निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद वे नाम हैं, जिनके दोषी सिद्ध होने से लोगों का कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है। हालांकि अतीक अहमद अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जीते जी उसको सजा मिलना जरायम की दुनिया के लिए बड़ा सबक था। इससे यह स्थापित हुआ कि निष्पक्ष विवेचना, गहन साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी से अधिकांश अपराधियों को सजा भी मिलेगी और भविष्य में ये प्रमोट होकर माननीय भी नहीं बन पाएंगे।

बिहार में हिंदुत्व की हुंकार?

बागेश्वरधाम वाले धीरेंद्र शास्त्री और विवाद एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन, बयान, टिप्पणी और चमत्कार को लेकर मुख्य धारा के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान न मचे। मगर बिहार का उनका दौरा, उनसे मिलने और उन्हें सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी संख्या, बाबा के बयान, गैर-भाजपा दलों की तीखी आलोचना आदि ने पूर्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।

छतरपुर के पंडित धीरेंद्र शास्त्री देशभर में कथावाचन कार्यक्रम करते हैं। लेकिन बिहार में उनके कार्यक्रम की घोषणा होते ही विरोध शुरू हो गया। राजद नेता, मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने सार्वजनिक घोषणा की कि वे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। उनके समर्थक बाबा को हवाई अड्डा से बाहर नहीं निकलने देंगे। इसके लिए उन्होंने बाकयदा डीएसएस नामक निजी सेना बना डाली। उन्होंने चेतावनी देते हुए यहां तक कह डाला कि बाबा मत भूलें कि बिहार में किनकी सरकार है। मगर 13 मई को पटना जिला अंतर्गत नौबतपुर के तरेत मठ में बिना किसी बाधा के कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। राज्य के कोने-कोने से लोग नौबतपुर जाने लगे। पटना पहुंचने वाली ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यह सिलसिला अगले 17 मई तक जारी रहा। अनुमान लगाया जाता है कि पांच दिनों में करीब 10 लाख लोग बाबा को सुनने नौबतपुर पहुंचे। लोगों की भीड़ और जनसमर्थन को देखकर विरोधी नेताओं की हिम्मत पस्त हो गई।

नौबतपुर में भी बाबा ने वही सब किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। पर्ची निकालकर लोगों के मन का सवाल जान लेना, अपने चमत्कार का बखान करना, समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना... यह सिलसिला चलता रहा। बीच-बीच में वे अपने प्रवचन के दौरान हिंदू, हिंदुत्व की रक्षा और हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को जागरूक होने का आव्हान भी करते रहे। जाहिर है गैर-भाजपा दलों को यह सब बर्दाश्त नहीं होना था। इसलिए गैर-भाजपा दलों द्वारा बाबा के बयानों और टिप्पणियों की तीखी आलोचना शुरू हो गई। इस क्रम में जहां नेताओं ने उन्हें भाजपा का एजेंट कहा, वहीं सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के विरोध में गंदी-गंदी गाली दी गई, अपशब्दों से भरे अनगिनत वीडियो प्रसारित हुए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा जिसका मन करता है, वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। बाबा बागेश्वर को जेल में रहने की जरूरत है। धीरेंद्र शास्त्री जेल में नहीं हैं, ये अफसोस की बात है। इन्हें कोई पूछता नहीं है, इसलिए ये कैसे अपनी पूछ बनाए रखें... इसी के लिए सबकुछ करते हैं। इनका बना रहना भारत की संत परंपरा के लिए घातक है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तो गिरफ्तार करने तक का इशारा कर दिया। मंत्री सुरेंद्र यादव और अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह डाला कि उनका हश्र भी आसाराम बापू जैसा होगा।

इसके प्रत्युत्तर में बाबा के पक्ष में भाजपा नेताओं ने भी आक्रामक बयान देना शुरू कर दिया। भाजपा नेता विजय सिन्हा ने कहा, संतों का विरोध करने वालों का अंत निश्चित है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वालों के मुंह पर जनता कालिख पोतेगी। दूसरी ओर बाबा के चमत्कार, हिंदुत्व जागरण के लिए उनके प्रयास की प्रशंसा करने वाले वीडियो की भी सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई।

देखा जाए, तो जातियों में बंटे बिहारी समाज के लिए धीरेंद्र शास्त्री प्रसंग ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विश्लेषकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को चुनाव पूर्व भाजपा की राजनीतिक तैयारी मानते हैं। उनका मानना है कि प्रखर हिंदुत्व की बात कर बाबा बिहार के हिंदू वोट को ध्रुवीकृत करने में मदद करेंगे। तकनीकी रूप से भले ही इस तर्क में दम प्रतीत होता है, मगर व्यवहारिक और जमीनी तथ्य का विश्लेषण करने पर यह महज एक परिकल्पना प्रतीत होती है। इसमें संदेह नहीं कि धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार भाजपा उत्साहित रही, लेकिन आम लोग बस अपनी निजी समस्या के समाधान की तलाश में बाबा के दरबार पहुंचे थे। इसमें न तो किसी भाजपा कार्यकर्ता का सहयोग था न ही किसी अन्य राजनीतिक संगठन का।

दरअसल, बाबा के चमत्कारों का हाल के दिनों में जो अति-प्रचार हुआ है, उसने हर किसी के मन में उत्सुकता पैदा कर दी है। चूंकि बिहारी समाज दैवी आशीर्वाद, मंत्र-जप-पूजा-पाठ आदि के सहारे निजी समस्या के समाधान होने में विश्वास रखता है, इसलिए जब बाबा बिहार आए तो ऐसे लोग उनसे मिलने घर से निकल पड़े, क्योंकि हर किसी के लिए मप्र जाना संभव नहीं है। बाबा के दरबार से लौटे आम लोगों की टिप्पणी में हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का कोई निशान नहीं मिलता। वे बस बाबा के चमत्कार और समस्या समाधान के लिए दिए गए सुझाव, उपाय आदि की बात कर रहे हैं। उनके दरबार से लेकर घंटों रास्ते में खड़े रहकर जिस तरह से बिहार के लोगों ने बाबा के प्रति अपना प्रेम दिखाया उसका राजनीति से दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं था। इसलिए यह कहना कि बाबा के कार्यक्रम से लोगों के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन (उन्मुखता) में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, आधारहीन आंकलन प्रतीत होता है।

● **विनोद बक्सरी**

लोगों का मिला भरपूर समर्थन

बिहार में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को बेहद सफल बनाने में लोगों का जबर्दस्त सहयोग रहा। लोगों के सक्रिय सहयोग ने ही कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने की बिहार सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। सरकार को पता चल गया था कि कार्यक्रम रोके जाने पर ये लोग, जो कि आम लोग हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सवाल है कि फिर बागेश्वर वाले बाबा को तमाम हिंदुत्ववादी लोगों का इतना समर्थन क्यों है? इसमें कोई संदेह नहीं कि देशभर में हिंदू नवजागरण की हवा चल रही है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। गांव से लेकर शहर तक, हर क्षेत्र में ऐसे लोगों की अब अच्छी खासी संख्या है जो हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर जागरूक हैं। कथित सेकुलरिज्म और उदारवाद के नाम पर हिंदुत्व के साथ होने वाले छल, गांव-गांव तक पहुंच रही मजहबी कट्टरता, हिंदुओं का धर्मांतरण, इस्लामिक संगठनों की कारगुजारी आदि को यह वर्ग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि धीरेंद्र शास्त्री इस सबके खिलाफ बहुत साफ शब्दों में बोलते हैं, इसलिए हिंदुत्ववादी आम लोगों का उन्हें खुला समर्थन मिलता है।

क्या दूसरे मुजीबुर्रहमान साबित होंगे इमरान?

पाकिस्तान में राजनीतिक हालात पल-पल बदल रहे हैं। अगले पल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। पीटीआई के नेता इमरान खान एक तरफ सत्ता में आने के लिए तत्काल चुनाव कराने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ पीडीएम की सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह इमरान खान को व्यक्तिगत तौर पर या पूरी पीटीआई को ही चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहारा दिया जाए। इस सत्ता संघर्ष में फिलहाल पाक फौज पीडीएम सरकार के साथ नजर आ रही है तो कोर्ट इमरान खान के प्रति नरम लग रहा है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है कि नेशनल असेंबली अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तत्काल चुनाव पर अड़े हुए हैं। अब 9 मई को पाकिस्तान में हुए उपद्रव की घटना में शामिल लोगों को पाकिस्तान सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने और सैन्य कोर्ट में केस चलाने के फैसले से पीटीआई में बिखराव शुरू हो गया है। बहरहाल, मुजीबुर्रहमान बन जाने वाली इमरान खान की धमकी को पाकिस्तान में भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि 1969 और 70 के पाकिस्तान के राजनीतिक हालात की तुलना आज की परिस्थितियों से की जा रही है। यह तुलना स्पष्ट रूप से राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप, सरकार द्वारा पीटीआई के खिलाफ आक्रामक बदले की कार्रवाई और जनता के अंदर उभर रहे असंतोष के आधार पर की जा रही है।

51 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने 1971 के विघटन से कोई सबक नहीं लिया है। इमरान खान खुद अपनी पार्टी पीटीआई को तब के बांग्लादेश अवामी लीग के बराबर लोकप्रिय मानते हैं। वह धौंस देते हैं कि यदि लाठी और दमन का जोर चलाकर उनकी बढ़ती लोकप्रियता का सम्मान नहीं किया गया तो वह मुजीबुर्रहमान बन सकते हैं। वह साफ कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में फौज का हस्तक्षेप जिस तेजी से बढ़ा है और जिस तरह से अघोषित सेंसरशिप के जरिए लोकप्रिय नेताओं की आवाज दबाई जा रही है, उससे सेना और सरकार दोनों के प्रति लोगों का भरोसा उठ रहा है। एक तरह से इमरान अपने समर्थकों को सेना के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसा रहे हैं।

इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुलना तब के जनरल याह्या खान से करके परोक्ष रूप से यह आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह तब के सैन्य शासन ने अवामी लीग के वैध लोकतांत्रिक जनादेश को नजरंदाज किया। एक राजनीतिक आंदोलन को बूटों से रौंद डाला और जिसके कारण बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन में बदला गया, वैसी ही स्थिति आज भी पैदा हो गई है। मार्च 1971 में भी आज ही की तरह पाक फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था, जिसके कारण एक राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा हो गया जो अंतत: खूनी गृहयुद्ध में बदल गया। इस समय भी यही स्थिति है।

9 मई को इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस में जमकर तोड़फोड़ की, लाहौर कोर कमांडर का घर लूट लिया और आग लगा दी। पाकिस्तानी सेना के युद्धक प्रतीकों को खंडित कर दिया और सैन्य मुख्यालय जीएचक्यू की तरफ कूच किया। यही नहीं पाकिस्तान की आजादी की पहले पहल घोषणा करने वाले पाकिस्तान रेडियो की इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी फौज 9 मई की घटना को काले दिवस की संज्ञा देकर पीटीआई पर टूट पड़ी है। सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले 25 से ज्यादा उपद्रवियों को मार गिराया गया है, 7000 से ज्यादा पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का निर्णय किया है और पीटीआई के पूरे नेतृत्व को साजिशकर्ता बनाकर उन्हें जेल में ठूसने का मंसूबा बना लिया है। यह पाकिस्तानी आर्मी का डर ही है कि पीटीआई के नेता अब सार्वजनिक रूप से उनसे अलग हटने का ऐलान करने लगे हैं।

आवामी लीग की तरह पीटीआई के नेता भी खुले तौर पर सेना की रैंकों के भीतर अपने समर्थन का दावा करते हैं। खासकर पूर्व आईएसआई प्रमुख जनरल फैज को इमरान खान का खास सलाहकर और सहुलियतकार माना जाता है। 9 मई की घटना में भी ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि सेना के रैंक एंड फाइल में इमरान खान और उनकी पार्टी को लेकर मतभेद है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने पहले भी इस समर्थन का दावा किया था, जब उन्होंने पिछली मार्च में कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका निष्कासन हुआ तो सेना के जवानों के परिवार उनके साथ इस्लामाबाद मार्च करेंगे। उनकी पार्टी के नेता शाहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी पर लोकतांत्रिक द्रोह का मुकदमा दायर हो चुका है। हालांकि डीजी आईएसपीआर की तरफ से कई मौकों पर इन दावों का खंडन किया गया और यह दावा किया गया कि सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के नेतृत्व में सेना एकजुट है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पाक में बल और छल की प्रवृति बढ़ी

हालांकि सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान ने 1971 की पराजय से सीखने के बजाय, बल और छल के साथ राजनीतिक मुद्दों को हल करने की अपनी प्रवृति अभी भी नहीं छोड़ी है। अभी भी जबरन लोगों को गायब करना, राजनीतिक हत्याएं, गैरकानूनी कारावास, उत्पीड़न और डराना-धमकाना जैसी मानवीय और अलोकतांत्रिक घटनाएं बिना रोक टोक हो रही हैं। जो भी सत्ता में आता है वह अपने असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी और राजद्रोह कानूनों को हथियार बनाकर उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास करता है। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और यहां तक कि ओकारा जैसे क्षेत्रों में अत्याचार और लूटमार चरम पर है। इन क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन वर्षों से चल रहे हैं और यदि पाकिस्तान कहीं से फिर टूट सकता है तो ये क्षेत्र पहले हो सकते हैं। क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में पुलिस सेना और अलगाववादियों के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है, रोज ही पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां मारे जा रहे हैं। पंजाब में भी इस समय उत्पीड़न और डराने-धमकाने की घटना बड़े पैमाने पर हो रही है। एक विशिष्ट पार्टी के सेना के साथ खराब संबंधों का यह असर हो या इमरान की अपनी जिद। इस समय पाकिस्तान जिस अनिश्चितता की सुरंग में घुस रहा है वहां प्रकाश का कोई दूसरा सिरा नजर नहीं आ रहा है।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

यूपीएससी में लड़कियों ने मारी बाजी

देश की सबसे कठिनतम परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सीएसई 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस परीक्षा में चार लड़कियों ने टॉप किया है। जिसमें पहली रैंक इशिता किशोर ने हासिल की है। वहीं दूसरा स्थान गरिमा लोहिया ने प्राप्त किया है, तीसरा स्थान उमा हरति एन ने प्राप्त किया है। 2022 यूपीएसी सीएसई परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाली इशिता किशोर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकॉनमिक्स में ग्रेजुएट हैं। वह अपने कॉलेज की मेधावी छात्र रही हैं। इशिता किशोर ने अपनी कड़ी मेहनत से परिवार वालों का तो नाम ऊंचा किया ही है साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज का भी नाम रौशन किया है। यूपीएससी 2022 में टॉप करने वाली इशिता किशोर ने मीडिया से कहा कि, मेरे परिवार ने मुझे असीम समर्थन दिया, भले ही मैंने प्रीलिम्स को दो बार पास नहीं किया लेकिन उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था। जिस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मेरे लिए चीजों को आसान बनाया, मैं उसके लिए उनकी आभारी रहूंगी।

पिछले साल श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला क्रमश: शीर्ष तीन स्थानों पर रही थीं। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हर साल तीन चरणों में होता है। इनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। इस परीक्षा के आधार पर ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) समेत कुछ अन्य शीर्ष केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।

यूपीएससी ने बताया कि परिणाम जारी होने के 15 दिन के भीतर परीक्षार्थियों के अंक यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली इशिता डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। वहीं मूलत: बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक हैं। उन्होंने कॉमर्स एवं अकाउंटेंसी का वैकल्पिक विषय रखा था। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुकी उमा हराती मूलत: तेलंगाना के नालगोंडा जिले की हैं। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को वैकल्पिक विषय बनाया था। डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज से बीएससी कर चुकी स्मृति मिश्रा ने जीव विज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। पांचवें स्थान पर असम के मयूर हजारिका ने जगह बनाई है। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में जाने का फैसला किया है।

परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद यूपीएससी ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि इस बार फाइनल रिजल्ट में कुल 933 उम्मीदवारों का चयन सिविल सर्विसेस में हुआ है। इनमें से 345 कैंडिडेट्स सामान्य वर्ग से हैं। 99 उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। 263 सफल उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। पास होने वाले 154 उम्मीदवार शेड्यूल कास्ट और 72 सफल उम्मीदवार शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से हैं।

इनके अलावा यूपीएससी ने 178 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट भी तैयार की है। वहीं आईएएस पदों पर चयन के लिए 180 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यूपीएससी ने 3 अलग-अलग चरणों में सिविल सेवा 2022 के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए थे। साक्षात्कारों का तीसरा व अंतिम चरण इसी महीने 18 मई 2023 को समाप्त हुआ था। यूपीएससी द्वारा घोषित किए गए रिजल्ट के अनुसार, सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2,529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था।

मप्र में भी कई युवाओं ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। सतना की रहने वाली स्वाति शर्मा ने इस परीक्षा में ऑलइंडिया 15वीं रैंक हासिल की है। उनके अलावा धार की संस्कृति सोमानी ने 49वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा प्रदेश में कई युवाओं ने बाजी मारी है। साथ ही साथ बता दें कि भोपाल की भूमि श्रीवास्तव का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन हुआ है। भूमि श्रीवास्तव को देशभर में 304वीं रैंक हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये सफलता बिना किसी कोचिंग के हासिल की है। यानि की सेल्फ स्टडी के जरिए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं और नेट जेआरएफ में भी सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। इस परीक्षा में जबलपुर के जतिन जैन को 91वीं रैंक मिली है। जबकि बीना जिला सागर के शुभम सिंह ठाकुर ने 466वीं रैंक हासिल की है और उज्जैन की रोचिक गर्ग ने 174वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रौशन किया है। इन लोगों के अलावा भी प्रदेशभर में कई लोगों ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

पहली बार 34 प्रतिशत महिलाओं का चयन

यूपीएएसी के इतिहास में पहली बार एक तिहाई पदों पर महिलाओं का चयन हुआ है। कुल चयनित अभ्यर्थियों में 613 पुरुष और 320 महिलाएं हैं। इस बार 34 प्रतिशत महिलाओं का चयन हुआ है। वहीं 2021 में कुल 685 में 177 महिलाएं, 2020 में कुल 833 में 238 महिला, 2019 में कुल 922 में 220 महिलाओं और 2018 में कुल 812 में 193 महिलाओं का चयन हुआ था। 2022 में महिलाओं का पास प्रतिशत सर्वाधिक है। इस परीक्षा को पास करने के बाद 180 अभ्यर्थी आईएएस बनेंगे जबकि 38 अभ्यर्थी आईएफएस बनेंगे। 200 अभ्यर्थियों को आईपीएस बनने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1022 पद भरे जाने हैं। बता दें कि 18 अप्रैल तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू राउंड हुए थे। 30 जनवरी से साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। मुख्य परीक्षा में पास 2529 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। पहले स्थान पर इशिता किशोर, वहीं दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर उमा हरति एन और चौथा स्थान स्मृति मिश्रा ने प्राप्त किया है। वहीं टॉप 5 में एक छात्र भी शामिल है जिसका नाम मयूर हजारिका है। ये टॉपर की अंक तालिका में पांचवे नंबर पर है।

कर्म करें फल की चिंता त्याग दें

महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था वो अपने आप में जीवन गाथा है। लेकिन श्रीकृष्ण का अर्जुन को दिया गया संदेश ही वास्तविक महाभारत है, तीर-तलवार तो सिर्फ मनुष्य का मनुष्य के साथ मारकाट वाली स्थिति मात्र है। गीता उपदेश जिसका जीवन में अहम योगदान है और जो जीवन में होने वाली हर घटना के बारे, स्थिति के बारे में हमें अवगत करता है कि किस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है?

श्रीमद्भागवत का संदेश श्रीकृष्ण ने श्लोकों के माध्यम से दिया है और गीता में लगभग 700 श्लोक हैं। जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आम जन मानस में खूब ख्याति मिली है।

कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि॥

इस श्लोक का प्रचलित अर्थ है जिसे हमें आजतक बताया गया है, जानते समझते है, वो है कर्म करो या तुम सिर्फ अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। अब अगर किसी से पूछो कि तुमको ये अर्थ कहां से पता चला है तो वो कहेगा कि श्रीकृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, जबकि वास्तव में उन्हें ये ज्ञान व्हाट्सप्प और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पता चला है क्योंकि गीता तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती बस किसी ने बोला तो चिपका दिया।

कर्म आधारित इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है; तुम कर्मफल की आशा से कर्म में प्रवृत हो जाओ, फिर कर्मत्याग में भी तुम्हारी प्रवृति न हो अर्थात् अपना कर्तव्य-कर्म करते चलो। यहां पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि तुम कर्म करो और फल कि चिंता मत करो। जबकि कहा ये गया है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। साथ ही लोग इसका अर्थ समझते है फल की परवाह किए बिन तुम अपना कर्म करो। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि श्रीकृष्ण कौन से कर्म की बात कर रहे है?

क्योंकि अगर एक बलात्कारी या चोर अगर इस श्लोक का अपने कर्म के संदर्भ में अर्थ करने लगे तो वो भी ये ही बोलेगा कि मैंने तो अपना कर्म कर दिया अब फल की चिंता क्यों करूं। इसीलिए यहां उस कर्म का अर्थ समझना जरूरी है जो श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अपने स्वजनों के मोह में फंसकर, अपने युद्ध के कर्म से पीछे हट रहा है तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं- हे अर्जुन! तुम इस समय अपने सही कर्म को पहचानो और वो करो जो सही है। बिना किसी फल की चिंता किए बिना क्योंकि जो काम सही होगा उसका फल भी सही होगा और अगर तुमने गलत कर्म का चुनाव किया है तो फल भी गलत ही होगा। इसीलिए हे पार्थ! तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है उसके फल की चिंता में नहीं।

कुछ भी करने से पहले हम चयन करते हैं सही और गलत का। श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो कर्म मुझे ध्यान में रखते हुए अर्थात् सत्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है वो ही सही कर्म है। जो काम निष्काम भाव से अर्थात् अपनी कामना को पीछे रखकर किया गया है वो ही सही कर्म है। लेकिन हमें अपनी उस कामना को पीछे रखकर निष्काम कर्म करना आता ही नहीं है, फिर हम जो चुनाव करते हैं वो गलत ही होता है। जब उस काम में डर और तनाव होता है तो श्रीकृष्ण को बदनाम करते हैं और अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। इसीलिए अगली बार गीता के किसी भी श्लोक का ऐसा अर्थ लगाने से पहले अपने आप से एकबार जरूर पूछना कि मैं व्हाट्सएप्प या फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ रहा हूं या फिर मैंने सच में गीता पढ़कर इस अर्थ को जाना है। भगवान श्रीकृष्ण गीता में बताते हैं कि धरती पर हर एक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसलिए उन्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्मों में लिप्त रहता है, भगवान उसे वैसा ही फल प्रदान करते हैं। साथ ही जिसे बुरे कर्मों में आनंद आता है, उसे उसी प्रकार का जीवन दंड के रूप में भोगना पड़ता है।

इंद्रियों को नियंत्रित करें- गीता में बताया गया है कि मनुष्य की इंद्रियां बहुत चंचल स्वभाव की होती हैं। वह आसानी से गलत आदतों को अपना लेती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे अपनी इंद्रियों पर और खासकर अपने चित्त अर्थात् मन पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चंचल मन के कारण कई प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

क्रोध पर रखें काबू- श्रीकृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को महाभारत के युद्धभूमि में बताया था कि व्यक्ति के लिए क्रोध विष के समान है। वह न केवल शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है, बल्कि इससे मानसिक तनाव में भी वृद्धि होती है। इसके साथ गीता में बताया गया है कि क्रोध से भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे चिंतन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना ही व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है।

● **ओम**

पहचान

दोपहर का समय था। सुनसान सड़क पर एक अधेड़ भिखारी को जाते देखकर अपने घर के बरामदे में बैठे पतिदेव ने कहा, बड़ा शातिर है यह भिखारी।

कैसे? पत्नी ने पूछा।

यह भिखारी जब हिंदू मोहल्ले में जाता है तो राम के नाम भीख मांगता है और जब मुस्लिम मोहल्ले में जाता है तो अल्लाह के नाम हाथ पसारता है।

आखिर वह ऐसा क्यों करता है? वह हिंदू है या मुस्लिम? पत्नी ने उत्सुक होकर पूछा।

पति ने भिखारी को बुलाया और पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है। मतलब तुम्हारा मजहब क्या है?

हुजूर! एक भूखे इंसान का क्या मजहब हो सकता है? भिखारी ने जवाब दिया।

– निर्मल कुमार डे

चीर हरण

दुर्योधन दास, टेंडर स्वीकृत हो जाने पर बहुत खुश है। हजार किलोमीटर फैला अरण्य प्रदेश, जहां विकास के बीज बोये जाने हैं, उस जमीन को तैयार करना है।

प्रभु स्मरण, पूजा पाठ कर, आज सुबह अपनी सेना के साथ हथियारबंद हो रण-क्षेत्र में पहुंच गए। अरण्य के एक-एक वृक्ष पर घाव करती कुल्हाड़ी। परत-दर-परत टूटता श्रृंगार। निरावरण, निर्वस्त्र होती धरा। सूरज की तेज किरणों से, आग सी धधकती वसुंधरा। व्याकुल, विचलित, शुष्क अधर।

साहेब, पैर जल रहें हैं, गला सूख रहा है। कहीं छांह दिखे तो सुस्ता लें। सैनिक विकर्ण ने कहा।

कुल्हाड़ी और छांह का, कहीं मेल है विकर्ण? दुर्योधन दास कुटिलता से मुस्कराए।

साहेब जी, जंगल क्यों काटा जा रहा है? यहां के पशु-पक्षी, फल-फूल, पेड़-पौधों का क्या होगा?

यहां, बड़ी-बड़ी कंपनी, ऊंचे-ऊंचे भवन, बड़े शहरों से जुड़ती सड़कें, नदी पर बांध, बनेगा। समझो यहां टकसाले खुलेंगी। सोने-चांदी की खेती होगी।

आदमी सोने-चांदी, अपनी सांसे बेचकर खरीदेगा क्या? विकर्ण के प्रश्न में आश्चर्य और जिज्ञासा थी।

तुम, यह समझ सकते तो प्यादे से वजीर न बन जाते विकर्ण। जीप में बैठते हुए दुर्योधन दास ने कहा।

गला तर करने, और क्षुधा शांत करने, जीप धूल उड़ाते हुए होटल के रास्ते चल पड़ी। उड़ी हुई धूल के कुछ कण विकर्ण के चेहरे पर आकर चिपक गए। उन कणों को, हाथ में लेकर, विकर्ण ने माथे से लगा लिया। फिर जाती हुई जीप की दिशा की ओर देखकर बोला-विनाश काले विपरीत बुद्धि।

– सुनीता मिश्रा

गीत

पहले ढोया स्वयं कोख में,
कांधे पर वह अब ढोती है,
मां की ममता।
सह लेती है सब उलाहना,
सभी कष्ट वह तन पर झेले,
अला-बला को दूर हटाए,
सिर पर दुनियादारी ले ले,
पीड़ा नहीं व्यक्त करती है,
मां की ममता!
गोदी शैशवकाल लिटाए,
झेली है हर द्वंद्व अकेली,
खाली हाथ जेब भी खाली,
कैसी है रचना अलबेली!
पहुंची-कंगन-चूड़ा-चूड़ी,
मां की ममता।
कांधे पर है बोझ समय का,
बगल दबाए लंबी झोली,
चमके दांत श्वेत मोती-से,
लौंग नाक में छोटी भोली,
कानों में है कुंडल पहने,
मां की ममता।
माला गले अंगूठी स्वर्णिम,
लाल रंग की शोभित बिंदी,
मंगलसूत्र गले में हंसता,
बोले ब्रज की टूटी हिंदी,
मां तो मां है! क्या बतलाएं?
मां की ममता।

– डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'

चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल चैंपियन

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स 29 मई 2023 की रात 1:30 बजे पांचवीं बार आईपीएल चैंपियन बनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। महेंद्र सिंह धोनी पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे कप्तान बनने के अलावा 250 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर भी बने। चेन्नई सुपर किंग्स ने इससे पहले आईपीएल 2010, 2011, 2018, 2021 का खिताब भी जीता था। वर्षा से बाधित मैच में चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य मिला था। चेन्नई ने 14.4 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन ही बनाए थे। उसे अगली 2 गेंद में 10 रन बनाने थे। रविंद्र जडेजा ने पांचवीं गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर चौका जड़कर चेन्नई की झोली में जीत डाल दी। गुजरात टाइटंस की ओर से मोहित शर्मा ने 3 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। साई सुदर्शन की 96 रन की बेहतरीन पारी की मदद से गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के 3 गेंद ही फेंके गए थे कि बारिश आ गई। बारिश रुकने के बाद दो बार मैच का मुआयना हुआ और अंपायर्स ने 12:10 बजे दोबारा मैच शुरू करने का फैसला किया। बता दें कि आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला 28 मई को 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश के कारण नहीं हो पाया था, इसलिए फाइनल रिजर्व डे पर खेला गया। रविवार 28 मई को भारतीय समयानुसार रात 11 बजे तक बारिश रुकने का इंतजार किया गया, फिर मैच सोमवार शाम तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 29 मई, को रिजर्व डे पर गुजरात टाइटंस की पारी पूरी होने के बाद बारिश ने फिर खलल डाल दिया।

गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाए। चेन्नई ने 3 गेंद पर 4 रन ही बनाए थे कि बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा। बारिश रुक गई, लेकिन प्रैक्टिस पिच भीगने के कारण 29 मई रात 12 बजे तक मैच शुरू नहीं हो सका। अगर ओवर्स में कटौती होती है तो चेन्नई को क्या टारगेट मिलेगा? इसे लेकर हर किसी के जेहन में सवाल था। इस बीच टीम इंडिया और राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विजेता की भविष्यवाणी कर दी। रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट करके कहा कि ओवर्स में कटौती हुई तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास सभी विकेट हैं। गेंद गीली होगी और फिसलन भरी आउटफील्ड होगी। सीएसके के नाम 5वां टाइटल होगा। उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई।

बता दें कि 29 मई, सोमवार को रात 11:30 बजे अंपायर्स ने मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद मैच 30 मई, को रात 12:10 बजे से मैच शुरू हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स को डकवर्थ लुईस स्ट्रेन नियम के मुताबिक 15 ओवर में 171 रन का टारगेट मिला। टीम ने आखिरी गेंद पर इस टारगेट को हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वेदर फॉरकास्ट के कारण उन्होंने फैसला लिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाए। साई सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद पर 8 चौके और 6 छक्के की मदद से 96 रन बनाए। ऋद्धिमान साहा ने 39 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाए। शुभमन गिल ने 20 गेंद पर 7 चौके की मदद से 39 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 12 गेंद पर 21 रन बनाए।

● आशीष नेमा

100+ मैच खेलने के बाद भी ये 10 प्लेयर्स नहीं छू पाए ट्रॉफी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 का 29 मई की देर रात 1:30 बजे समापन हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनी। महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान 9 टी20 टाइटल जीतने वाले कप्तान बने। हालांकि, कुछ खिलाड़ी रहे, जिन्हें पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने का मौका मिला। ये खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, डेवोन कॉनवे, तुषार देशपांडे, मथीसा पथिराना और महेश तीक्षणा हैं। अजिंक्य रहाणे को 172 मैच खेलने के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। वैसे आईपीएल इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा मैच खेले, लेकिन कभी चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। सबसे ज्यादा मैच खेलने के बाद भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली शीर्ष पर हैं। 237 मैच खेलने के बाद भी विराट कोहली का आईपीएल चैंपियन बनने का ख्वाब अधूरा है। विराट कोहली के अलावा इस लिस्ट में उनके दोस्त एबी डिविलियर्स का नाम भी शामिल है। एबी डिविलियर्स ने अपने कैरियर में 184 आईपीएल मैच खेले, लेकिन कभी उनकी टीम चैंपियन नहीं बन पाई। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अब तक 152 आईपीएल मैच जीत चुके हैं, लेकिन एक बार भी चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। आईपीएल 2022 में उनकी अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स फाइनल खेली थी, लेकिन तब उसे गुजरात टाइटंस से हार झेलनी पड़ी थी। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में चौथे नंबर पर काबिज वरिष्ठ गेंदबाज अमित मिश्रा भी 161 मैच खेलने के बाद खाली हाथ हैं। उनके नाम आईपीएल में 173 विकेट हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा 357 छक्के लगाने वाले कैरेबियाई दिग्गज क्रिस गेल भी आज तक आईपीएल चैंपियन नहीं बन पाए। अक्षर पटेल, ग्लेन मैक्सवेल, मयंक अग्रवाल और प्रवीण कुमार भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो 100 से ज्यादा आईपीएल मैच खेलने के बाद ट्रॉफी से महरूम हैं। अक्षर पटेल अब तक 136, ग्लेन मैक्सवेल 124, मयंक अग्रवाल 123 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। आईपीएल में 90 विकेट लेने वाले प्रवीण कुमार भी कभी आईपीएल चैंपियन नहीं बन पाए। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 119 मैच खेले थे।

मां ने 4 साल की उम्र से ही दी थी एक्टिंग की तालीम, बड़े होकर अभिनय की पाठशाला बन गए दिग्गज अभिनेता

मशहूर एक्टर पंकज कपूर आज हर एक्टर के लिए एक्टिंग के गुरु कहे जाते हैं। 1954 में पंजाब के लुधियाना में जन्मे पंकज कपूर महज 4 साल की उम्र से ही एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। पंकज के पिता प्रॉफेसर थे और अपने समय के गोल्डमेडलिस्ट रहे थे। पंकज की मां ने उन्हें बचपन से ही छोटे एक्ट की तालीम दी थी। स्कूलिंग पूरी करने के बाद पंकज कपूर ने एक्टिंग की दुनिया में जाने का मन बनाया और पिता से इस बारे में सलाह मांगी।

पंकज के पिता ने उन्हें कहा, अगर तुम एक्टिंग करना ही चाहते हो तो फिर इसकी सलीके से पढ़ाई करो और बारीकियां समझो। पिता की इस बात के बाद पंकज कपूर ने एफटीआईआई में दाखिला लेने के लिए इम्तिहान दिया लेकिन उनकी किस्मत काम नहीं आई। 19 साल के पंकज कपूर को तब कहां पता था कि उनकी किस्मत में भगवान ने घर की जगह महल लिखा है। एफटीआईआई से रिजेक्ट होने के बाद मायूस पंकज को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिल गया। पंकज कपूर ने यहां अपनी एक्टिंग को धार दी और कई कलाओं में महारथ हासिल की। 1976 में 22 साल के पंकज कॉलेज से डिप्लोमा लेकर मुंबई आ गए। यहां उन्हें गांधी फिल्म में काम करने का मौका मिला।

इसके बाद उन्हें श्याम बेनेगल ने फिल्म आरोहण दिला दी। पंकज को फिल्मों में काम तो मिलने लगा लेकिन अभी भी उनकी एक्टिंग की भूख नहीं मिट रही थी। 80 का दशक शुरू हो गया था और टीवी की दुनिया फल-फूलने लगी थी। पंकज कपूर को भी टीवी से ऑफर आने लगे। लेकिन टीवी से पंकज काफी दिनों तक किनारा करते रहे और आखिरकार आर्थिक तंगी ने उन्हें टीवी की तरफ मोड़ दिया।

टीवी ने ही दी कैरियर को उड़ान... इसके बाद यही उनकी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बन गया। यहां पंकज कपूर ने करमचंद जैसे कई शानदार सीरियल्स में काम किया और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के कई नमूने पेश किए। इसके बाद पंकज की रफ्तार ऐसी निकली कि आज उन्हें एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है।

सुपरस्टार ने पहले गोविंदा को फिल्म के लिए मनाया, फिर सेट पर धमकाया, डर से शूटिंग करने नहीं पहुंचे चीची

गोविंदा की फिल्में मनोरंजन का फुल पैकेज होती हैं, इसलिए दर्शक उन्हें आज भी देखकर बोर नहीं होते। बड़े मियां छोटे मियां उनकी ऐसी ही हिट फिल्म है, जिसमें गोविंदा ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि गोविंदा ने अमिताभ बच्चन के कहने पर फिल्म साइन की थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा ने खुलासा किया कि फिल्म के एक खास सीन के शूट से पहले बिग बी उनके पास आए और उन्हें धमकाते हुए बोले कि अगर डेविड धवन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है, तो वे उन्हें थप्पड़ मारेंगे। गोविंदा घबरा गए, जिसकी वजह से एक्टर ने फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी। कहते हैं कि चीची फिल्म के एक गाने से खुश नहीं थे। उनका दावा था कि गाना चलेगा नहीं,

जिसकी वजह से शूटिंग में देरी हुई और बिग बी को भी अपना शूट रद्द करना पड़ा। 59 साल के गोविंदा ने बताया कि डेविड धवन उनकी स्टेटमेंट पर बात करने के लिए आए और पूछा कि वे इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि गाना चलेगा नहीं? तब एक्टर ने बिग बी के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया, जिससे डायरेक्टर को लगा कि गाना कोई बहुत बढ़िया नहीं है। फिल्म के जिस गाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, वह मखना गाना है जो आखिर में माधुरी दीक्षित के साथ शूट हुआ।

जब अभिषेक बच्चन पर गुस्सा हुआ था नया डायरेक्टर, जलसा में जाकर सुनाई थी खरी-खरी! बोले- तुम अमिताभ के बेटे...

हसीना पार्कर, जंजीर, शूटआउट एट लोखंडवाला और दस कहानियां जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने अभिषेक बच्चन से जुड़ा एक यादगार किस्सा बताया। अपूर्व लाखिया ने कहा कि अभिषेक बच्चन ने मुंबई से आया मेरा दोस्त के ऑफर पर शुरुआत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस पर रिस्पांस देने के लिए 6 महीने का समय लिया। इतना समय लेने के बाद भी उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे घर बुलाया और मुझसे कहा, यह फिल्म बननी चाहिए। यह एक शानदार स्क्रिप्ट है। इसे 100 प्रतिशत बनाया जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ नहीं।

अपूर्व लाखिया ने कहा, मैं चौंक गया। मुझे लगा कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभिषेक बच्चन के इस रिस्पांस पर अपूर्व को बहुत गुस्सा

आया। उन्होंने कहा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे स्क्रिप्ट वापस मांग ली और वहां से आ गया। मैं इंडस्ट्री में नया था तो मुझे नहीं पता था कि आप किसी एक्टर पर गुस्सा कर सकते हैं या नहीं। फिर मुझे अभिषेक कॉल आया। उन्होंने मुझे पूछा- क्या आप नाराज हैं? अपूर्व लाखिया ने कहा, हां, आप अमिताभ बच्चन के बेटे हैं और आपको किस बात की चिंता है। मैं 6 महीने से इंतजार कर रहा हूं। ऑटो से आना-जाना कर रहा हूं। इस बात के बाद अभिषेक ने मुझे मिलने को बुलाया और हां कर दी।

हैप्पीनेस इंडेक्स वाली वर्ल्ड रैंकिंग

उस दिन नाई की तलाश में एक प्लाजा में गया। वहां एक सुसज्जित सैलून के सामने ठिठक पड़ा। एक बार ऐसे ही एक सैलून में एक फैशनेबल नाई ने, जिसे मैंने सिद्धहस्त माना था, मेरी टपोरी-कट कटिंग किया था। इसे यादकर मैं सैलून में जाने से हिचका भी। लेकिन शीशे के पार से नाई ने देख लिया और मुझे अंदर आने का संकेत किया। मैं गया और उसे अपने बालों की कटिंग समझाया। इसे समझकर उसने कहा, जो नाई दिखाई पड़ने में साधारण हो वही आपके बालों की कटिंग समझ सकता है फैशनपरस्त नहीं। मेरे पूर्वानुभव से उसकी बात सिद्ध हुई। उसकी बात ऊंची और अद्‌भुत थी! मैंने तत्काल वहीं एक दार्शनिक सूत्र भी गढ़ा कि साधारण, साधारण के मन की बात समझता है दिखावटी पर्सनालिटी वाला नहीं, अर्थात् सिम्पल पर्सन समझदार होता है। फिर कैंची और कंघी हाथ में लेकर उसने कहा 'पहली बार आए हो, ऐसी कटिंग करूंगा कि अगली बार भी यहीं आओगे?।' जैसे ही उसने बालों पर नपे-तुले अंदाज में कैंची चलाना शुरू की मुझे उसकी बातों पर इत्मीनान हो गया। इस बीच सैलून में तीन लोग आए थे और अंदर की लंबाई-चौड़ाई लेने लगे। वे यहां प्लाजा में ऐसी ही एक दुकान लेने की बात कर रहे थे। उनकी बातचीत का कुछ अंश यह था,

'यहां बार खोला जा सकता है भीड़ भी खूब होगी!'

'नहीं, आसपास सोसायटियां हैं, बार खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी।'

अरे सब हो जाएगा, पंद्रह लाख खर्च करने होंगे बस, लाइसेंस मिल जाएगा। यह आत्मविश्वास से लबरेज वाक्य था। इस बातचीत के बाद वे चले गए थे।

नाई बाल बना चुका तो जैसे छोटी बात में आम आदमी खुशी ढूंढ़ लेता है वैसे ही मन मुताबिक कटिंग देख मुझे भी हैप्पीनेस फील हुआ। लेकिन एक सौ बीस रुपए में बाल बने थे, इसलिए यह खुशी आम आदमी वाली नहीं थी।

प्लाजा से बाहर आया। धूप कड़ी थी। पार्कनुमा स्थान से पेड़ों की छांव में होकर चल रहा था। अचानक दूर एक कोने पर निगाह पड़ी। वहां चबूतरे पर पेड़ के तने के सहारे एक व्यक्ति बैठा था। निकट पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि यह घिसइया है मौसमी मजदूर! जो गाहे-बगाहे गांव-शहर-गांव करता रहता है। यह शहर आया है इसकी मुझे जानकारी थी। लेकिन उसके हाथ में चिलम देख मैं अचंभित हुआ। वह यहां दम मारो दम वाली मस्ती में मगन था। वैसे भी गांजे का नशा अन्य के मुकाबिल कुछ आध्यात्मिक किसिम का होता है और निठल्लई की अवस्था में चढ़ता भी खूब है। इसीलिए धुएं के पार उसके चेहरे पर दुश्चिंता की नहीं बल्कि अनोखे आनंद की रेखाएं दृष्टिगोचर हुई!

इधर देश चिंता में हलकान मैं विश्व समुदाय में भारत को प्रतिष्ठित कराने हेतु आइडिया पर आइडिया खोज रहा था उधर घिसइया ने खेला कर दिया! उसने ऐसा जोर का दम मारा कि चिलम सुलग पड़ी! फिर मुंह से धुआं आसमान की ओर ऐसे उड़ाया कि जैसे दुनियां को बताकर ही दम लेगा कि असली खुशी यह है! मुझे लगा अपने इस प्रयास से वह खुशहाली की रेटिंग मामले में हुई बदनामी से भारतवासियों को उबारना चाह रहा है! उसकी इस अद्‌भुत देशभक्ति पर मैं गदगद था। सोचा, ऊपर वाले ने भारतीयों में गजब की नेमत बख्शी है। इनमें रुहानी खुशियाली के बलबूते भारत को विश्व गुरू बनाने की अद्‌भुत क्षमता है! सौभाग्य से हम दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, तो परमात्मचिंतनोत्पन्न इस खुशी को विश्व खुशहाली रैंकिंग में शामिल कराने से भारत दुनिया में अधिकतम खुशी वाला देश बन सकता है। इस विचार के साथ मैं देश-चिंता से लगभग मुक्त हुआ चुपचाप वहां से खिसकने लगा। लेकिन गांव-जवार के आदमी से नजरें चुराकर जाना अच्छा नहीं लगा तो स्वयं को घिसइया के सामने प्रकट कर दिया। मुझे साक्षात अपने सामने खड़ा देख वह सकपका गया। जल्दबाजी में जैसे-तैसे चिलम को बंडी की जेब में ठूंसा। उसे जेब में व्यवस्थित करते हुए बोला, अरे गुरु! आप इंहां?

अरे भाई! जहां रोजी-रोटी होगी वहीं न होंगे हम, तुम भी तो... लेकिन अचानक मैंने बात बदलकर उससे कहा, तुम्हें देखा तो सोचा, गांव-जवार का हालचाल लेता चलूं लेकिन तुम दीन-दुनिया से बेखबर यहां साधना में लीन दिखाई पड़े! वह सकुचाकर सफाई देते हुए बोला, 'गुरु, ई नशापाती से थकाई नहीं लगता। लेकिन यह तो स्वास्थ्य और कानून दोनों के खिलाफ है? मैंने प्रश्नात्मक प्रतिवाद किया।

देखो साहेब! हमका स्वास्थ्य-फ्वास्थ की चिंता नाहीं, कऊन आप सुंभा की नाईं हम राज खड़ा किहे हैन कि ओकर सुख भोगना है, अऊर रही आपकइ कानून-फानून की बात तो यह कब कहां किसके खिलाफ अऊर कब किसके पच्छ में हुई जात है ई आपऊ जानत हैं...है कि नाहीं? कोनऊ गलत तो नाय बोल दिए साहेब?

उसकी बात पर मैं भौंचक था। जैसे सैलून में हुई बातें उसने भी सुनी हो! वैसे मुझे पता है कानून की चिंता करते-करते वह 'साहबों' और 'साहबी' पर कटहा कुकुर बनकर दौड़ पड़ता है। मुझे याद आया पिछली बार जब गांव में मिला था तो खिन्न मन से बताया था कि कैसे एक हत्यारोपी को तमाम सबूतों के बावजूद तीन महीने में ही जमानत मिल गई क्योंकि पीड़ित की ओर से कोई पैरोकार नहीं था। उस दिन उसने यह भी कहा था, गुरू ई साहबों की साहबी और उनकइ ठाट-बाट कऊने काम के! उसकी बात में आज भी वही खिन्नता बरकरार थी तभी उसने मुझे 'गुरु' की बजाय 'साहेब' बोल दिया है। यह सच है कि 'कानून' की बात करने पर वह ऐसे ही खुन्नस खा जाता लेकिन हो सकता है आज चिलम के साथ देख लिए जाने पर सब झार मगरइलै पर उतारने की नाईं उसने मुझे 'साहेब' बोल दिया हो! मैंने मन को समझाया। वैसे मेरे लिए उसका चिरपरिचित संबोधन गुरु ही होता है।

● **विनय कुमार तिवारी**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

UNSTOPPABLE ENERGY.....

Milestones

- **Highest Coal Production 131.17 MT**
- **Dispatched all time highest offtake of 133.51 MT**
- **Highest OBR of 462.10 MCuM**

Northern Coalfields Limited

A Miniratna Company

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Singrauli (M.P). 486889

/northerncoalfields eNCL_SINGRAULI /northerncoalfields